खण्ड-231, अंक-9
शनिवार, 12 ज्येष्ठ, शक संवत् 1884
(2 जून, 1962 ई0)

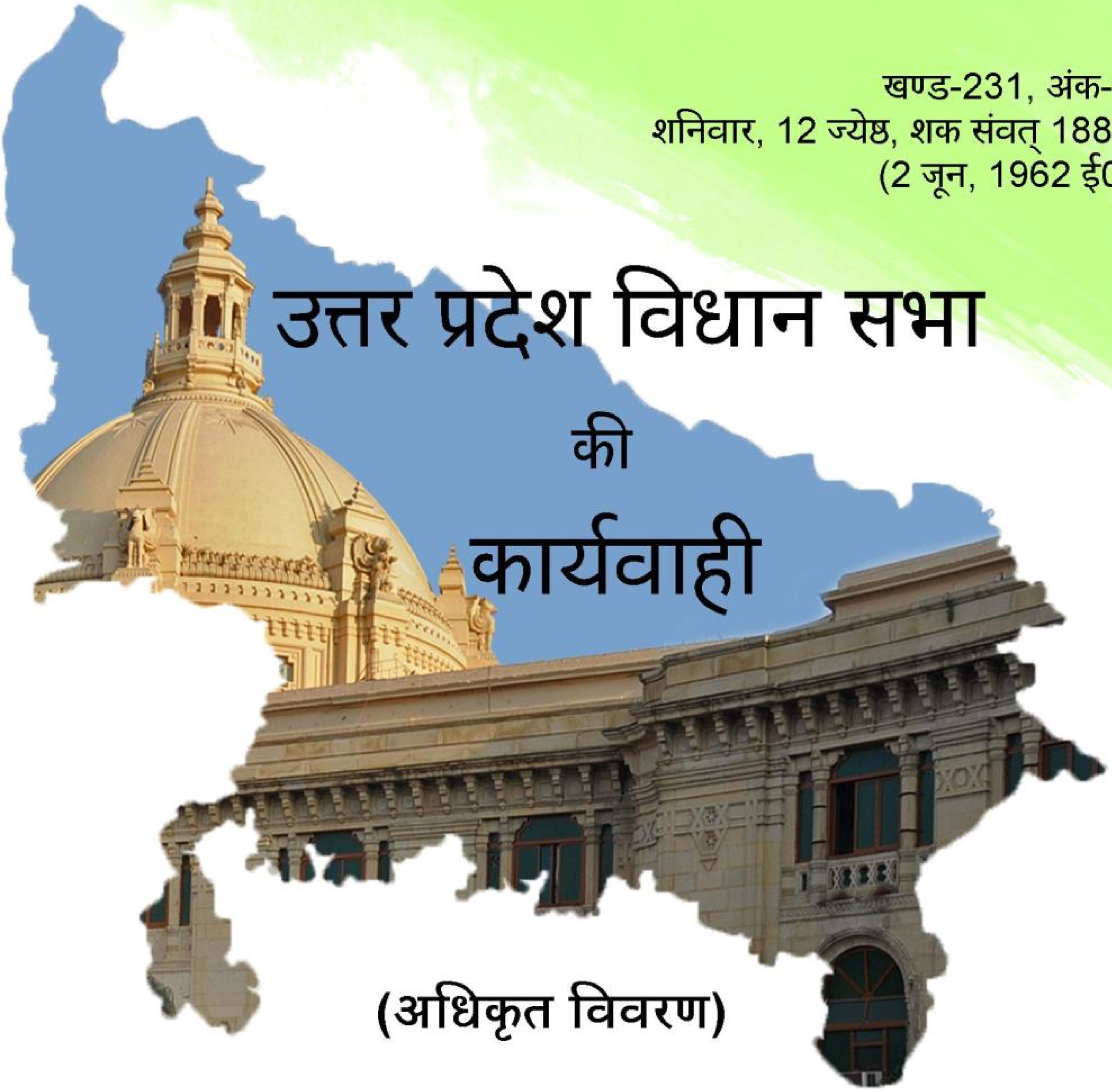

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 231 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	८०१–८०५
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	८०५–८०६
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	८०६–८०७
विधान भवन प्रवेश-पत्र न देने पर समाजवादी दल की आपत्ति	८०७
नियम ५३ के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी	८०७–८०९
२ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न २ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन ..	८०९–८१०
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३७—संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत (जारी)	८१०–८६९
गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	८६९–८७०
१९६२–६३ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३७—संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	८७०–८७४
२४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न १—३ के विषय पर नियम ५० (१) के अन्तर्गत विवाद	८७५–८८१
नत्थी	८८२

अविभाजित प्रस्तुत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २ जून, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६८

अखण्डप्रताप सिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अवधेश प्रताप, राजा
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नगुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीरद, श्री
खेमचन्द श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गनेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री

SEP

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंगादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री

प्रेम सुन्दर, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कन्नौजिया, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी

श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह युसुफ़, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त, भी उपस्थित थे ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---दो कामरोको प्रस्ताव की सूचनायें आयी हैं । एक तो श्री नरसिंह नारायण जी की है । वह मैंने शिक्षा मंत्री जी के पास भेज दी है यह जानने के लिये कि उनको क्या कहना है । वह (प्रस्ताव) अभी आये तो उसकी सूचना अभी भेजी है ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, हमारी आल इंडिया कांफ्रेंस ११-१५ तक गोरखपुर में हो रही है और मैनेजिंग कमेटी ने २७ तारीख को यह प्रस्ताव पास कर दिया कि महाराणा प्रताप इंटर कालेज देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद डी० आई० ओ० एस० वहां पर उस मैनेजिंग कमेटी पर यह दबाव डाल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---यह तो आपने लिख कर दिया ही है ।

श्री नरसिंहनारायण---श्रीमन्, मैंने कल शिक्षा मंत्री जी को टेलीफोन भी किया, पत्र लिख कर दे दिया । यह सूचना शायद आज आ गई हो मंत्री जी के पास ।

श्री अध्यक्ष---मैंने उनके पास अभी भेजा है ।

श्री नरसिंहनारायण---क्या इसको आप स्थगित कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में तो नहीं ले रहा हूं लेकिन इस सम्बन्ध में मंत्री जी से वक्तव्य दिला दूंगा ।

दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री चन्द्रबली का है । इनकी शिकायत यह है कि दोहरीघाट से निकलने वाली पम्प नहर १४-५-६२ से बिजली के अभाव से बन्द है ।

[श्री अध्यक्ष]

यह प्रश्न सदन में कई बार हो चुका है कि कोयले की कमी से कठिनाइयां हो गई थीं। लेकिन कल खाद्य मंत्री जी ने बताया, और इसके पूर्व सिंचाई मंत्री ने भी अपने भाषण में और वक्तव्य में बता दिया है कि कठिनाई उत्पन्न हो गई थी। कल तो खाद्य मंत्री ने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हर प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है चाहे रेल के जरिये से हो, चाहे नाव के जरिये से हो, चाहे जैसे हो, अधिक से अधिक मात्रा में कोयला पहुंचाया जायगा और कोई नुक्सान नहीं होगा।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—उस नहर के चालू होने के सिलसिले में क्या हो रहा है, मंत्री जी ने तो जनरल बात बतायी थी। गन्ने की फसल सूख रही है, वहां के अधिकारी भी परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष—मूल कारण तो उसका कोयले का अभाव है, और तो कारण है नहीं और उस कोयले का प्रबन्ध किया जा रहा है। माननीय खाद्य मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि प्रत्येक उपाय इस सम्बन्ध में किया जा रहा है। अतः इसको कामरोको के रूप में लिया जाना असम्भव है।

श्री चन्द्रबली—बहुत बड़ा नुक्सान हो रहा है। दूसरे काम रोक करके बिजली वहां दी जाय।

श्री अध्यक्ष—कोयले का प्रबन्ध शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिये, खाद्य मंत्री जी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो नुक्सान हुआ है दोहरीघाट पम्प कैनाल के बन्द होने से, उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—जब क्षतिपूर्ति का समय आयेगा तो देख लिया जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—दो प्रस्ताव नियम ५२ के सम्बन्ध में आये हैं। एक माननीय ऊदल जी का है। उन्होंने यह लिखा है कि प्रदेश की सरकार ने हरिद्वार के पास ज्वालापुर में ली जाने वाली जमीन के सम्बन्ध में किसानों को कुछ आश्वासन दिये थे। मैं मंत्री महोदय के पास इसे भेज रहा हूं इस जानकारी के लिये कि क्या यह सत्य है कि आश्वासन दिये थे? फिर उसके बाद अगर जरूरत होगी तो हम वक्तव्य ले लेंगे, जो उचित होगा वह किया जायगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—इसका निर्णय कब तक होगा?

श्री अध्यक्ष—मैं भेज रहा हूं। परसों तक आ जाना चाहिये।

श्री चन्द्रबली जी ने बाढ़ के सम्बन्ध में कई मर्तबा मुझे सूचना भेजी है और वह सदैव अस्वीकृत इस कारण की कि उनका कहना है कि बाढ़ आने वाली है, इस साल प्रलयंकर हो जायगा। एक काल्पनिक बात है। काल्पनिक बात पर....

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—काल्पनिक नहीं है। नियमित रूप से बाढ़ आती है। मैं कहता हूं कि इस साल बाढ़ आयेगी, भयंकर बाढ़ आयेगी। मंत्री जी कह दें कि नहीं आयेगी तो मैं मान लूंगा।

श्री अध्यक्ष--वित्त मंत्री ने बाढ़ के सम्बन्ध में बहुत बातें कही हैं और राजस्व मंत्री ने भी कही हैं। यह भी आश्वासन दिया है कि हर हालत में उसका प्रबन्ध किया जायगा। तो मैं इसको ५२ में न लेकर उनके पास भेज दूंगा कि इस बात को वह ध्यान में रखें।

विधान भवन प्रवेश-पत्र न देने पर समाजवादी दल की आपत्ति

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---निवेदन यह है कि कल हमारे बहुत से सोशलिस्ट सदस्यों ने, बाहर के आने वाले व्यक्तियों को, सचिवालय के अन्दर आने के लिए पास के लिये लिखा था, लेकिन पास के अधिकारी ने यह कह कर मना कर दिया कि आज आदेश यह है कि सोशलिस्ट सदस्यों द्वारा लिखे हुए व्यक्तियों को पास नहीं दिये जायंगे। कांग्रेस वालों ने जिनको लिखे, उनको दिये गये। तो यह विशेषाधिकार की अवहेलना है और इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही हो क्योंकि हमें अधिकार है कि हम पास इश्यू करा सकें।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। माननीय उग्रसेन जी लिख कर दें। यह कहा गया कि सोशलिस्ट पार्टी वालों को नहीं देंगे, मैं समझता हूं कि अनुचित बात कही गयी। जो आदेश उस सम्बन्ध में जारी किये गये थे वह आदेश यह नहीं थे कि सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या फलां पार्टी को पास न दिये जायं। आप लिख कर भेज दीजियेगा। मैं दरियाफ्त कर लूंगा।

नियम ५३ के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तावों के संबंध में जानकारी

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---मालगुजारी की बढ़ोत्तरी के होने के सम्बन्ध में मैंने कल एक प्रस्ताव नियम ५३ के अन्तर्गत दिया था। लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि उसका क्या हश्र हुआ और न यह बतलाया गया कि कामरोको प्रस्ताव का क्या हश्र हुआ ?

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य समाचार पत्र रोज पढ़ते हैं। उसमें आ गया है कि ४ तारीख को इस सम्बन्ध में चर्चा होने जा रही है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---उसमें माननीय नरसिंह नारायण का प्रस्ताव भी जोड़ दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष---नाम किसी का नहीं लिखा जायगा। यह लिखा जायगा कि सदन के माननीय सदस्यों के आग्रह पर यह विषय रखा जाता है।

श्री नरसिंहनारायण---मैंने दफा ५३ में जो विषय दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---आपको दफा ५३ की क्यों फिक्र है ? विषय जो है वह सदन के समक्ष आयेगा, चाहे दफा ५२ में हो, दफा ५३ में हो या दफा ५० में हो।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)---मैंने नियम ५३ के अन्तर्गत जो सूचना दी थी उसके विषय में आप क्या कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्यों को मैं बतलाना चाहता हूं कि सूचनायें अगर मालूम करनी हों तो आप कृपा कर मेरे कमरे में मिल सकते हैं। यहां पर सूचना मांगना गलत है।

आपने, किसी जिला परिषद् में किसी व्यक्ति को मंत्री या किसी पद पर रखा गया है उस पर आपत्ति की है कि वह व्यक्ति किसी मंत्री से संबंधित है इस वजह से आपने दफा ५३ के अन्तर्गत प्रश्न उठाया है। अब किसी की नियुक्ति करना यह जिला परिषद् का काम है। उसने अपने स्वविवेक से किसी की नियुक्ति की। इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं। इसलिये यह अस्वीकृत हुआ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, दफा ५३ में जो ४ तारीख के लिये आप ने स्वीकार किया है वह कितने घंटों का विवाद होगा ?

श्री अध्यक्ष---आप क्यों परेशान हैं ? मैंने कल स्वयं कहा था कि मैं बता दूंगा। अभी मैं बताता हूं।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---आज आपने दफा ५२ का कोई स्वीकार किया है ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

श्री चन्द्रजीत---ऊदल जी का आपने कहा था।

श्री अध्यक्ष---हां, ऊदल जी का मैंने मंत्री जी के पास जानने के लिये भेजा है कि क्या वस्तुस्थिति है, उसके बाद मैं तय करूंगा।

श्री चन्द्रजीत---माननीय ऊदल जी का जो आपने दफा ५२ में भेजा है तो माननीय राजस्व मंत्री जी यहां मौजूद हैं, यह उनसे सम्बन्ध रखता है। तो वे बता दें कि क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष---माननीय ऊदल जी, यह किसने आश्वासन दिया था ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---श्रीमान् जी, भारत सरकार की तरफ से बिजली कारखाना खुल रहा है। तो भारत सरकार ने जमीन मांगी प्रदेश की सरकार से। प्रदेश की सरकार ने एक्वायर कर के भारत सरकार को जमीन दे दी और हमारी सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था.....

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसका आप जवाब दीजियेगा। यह नहीं कि कौन मंत्री महोदय थे जिन्होंने आश्वासन दिया था ?

श्री ऊदल---श्रीमान् जी, सरकार ने दिया था, पूरी सरकार ने।

श्री अध्यक्ष---तो मैं सरकार से पूछ लूंगा।

श्री चन्द्रजीत---परिस्थिति यह है कि अगर ऐक्वीजीशन हुआ है तो उसके लिये माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हैं, वे बतायें कि कितनी लैंड एक्वायर की गयी, किन शर्तों पर की गयी और कैसे भारत सरकार को दी गयी ?

श्री अध्यक्ष---मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि सरकार ने इन किसानों को वादा किया था कि किसानों के बसाने, रोजी, शिक्षा खेती आदि का इंतजाम करेगी। तो बसाने के लिये रोजी के लिये, शिक्षा के लिये और उनकी खेती का प्रबन्ध करेगी, ये चार चीजें हैं। अब माननीय ऊदल जी नहीं बता पा रहे हैं कि किसने वादा किया था। अब सिर्फ प्रश्न यह रह जाता है कि किस मंत्री ने यह कहा था। मेरी फीलिंग यह है कि अगर ऐसा आश्वासन दिया है तो

क्या कार्यवाही हो रही है वह बतायेंगे और अगर ऐसा आश्वासन नहीं दिया है तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री चन्द्रजीत---माननीय राजस्व मंत्री उसको बतलायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---क्या माननीय राजस्व मंत्री ने कोई ऐसा आश्वासन दिया था ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है मैंने तो कोई ऐसा आश्वासन दिया नहीं ।

श्री चन्द्रजीत---श्रीमन्, याददाश्त से काम नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष---मैं एक बात रखता हूं आपके सामने, उसको आप स्वीकार नहीं करते । उनके पास मैंने भेजा था तो वे देख कर बताते । आप कहते हैं कि नहीं, पूछ ही लो, तो मैंने पूछ लिया ।

श्री चन्द्रजीत---आप उनसे कहिये कि पता लगायें ।

श्री अध्यक्ष---मैं नहीं कहूंगा ।

श्री चन्द्रजीत---श्रीमन्, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि हमारे जो नियम हैं उनके अनुसार यह है कि आप सूचना दें और अगर संबंधित मंत्री जी इस स्थिति में हैं नहीं तो वह बयान दें, उसके लिये वे समय मांगेंगे और सदन के सामने बयान देंगे । यह नहीं कि वे कहें कि नहीं मालूम, तो आप वाश आउट कर दें ।

श्री अध्यक्ष---बहुत अच्छा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब तक यह तय न हो जाय कि आप प्रश्न ऐडमिट करते हैं तब तक कैसे वह मुझसे पूछ सकते हैं । अगर आपको उसके लिये कोई जानकारी करनी हो तो आप पूछ सकते हैं जो कि आप पूछ रहे हैं ।

२ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न २ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन*

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---अध्यक्ष महोदय, दिनांक २ मई, १९६२ को श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २ के सम्बन्ध में श्री उग्रसेन ने अनुपूरक प्रश्न पूंछा था कि "क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उनकी दिक्कत को देखते हुये किस्त की जो सुविधा दे दी गई है तो कब से सुविधा दी गई और कितना धन वसूल हो गया ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "श्रीमन्, तफसील से बताने की जरूरत हो तो मैंने बताया कि जे० के० काटन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स से १० हजार रुपये माहवार की किस्त में वसूली हो रही है । यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने वसूली रोक दी है तब भी हो रही है और जे० के० जूट मिल्स में रकम बकाया है उसके सिलसिले में १९४८-४९, १९४९-५० को जो असैसमेंट हुआ था उसमें जज पुनरीक्षण ने यह फैसला कर दिया कि यह रिअसैस किया जाय । उसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है । जब तक फैसला नहीं होता तब तक उनके कहने के मुताबिक १९४८-४९ का रुपया बाद वाले सेल्स टैक्स में मुजरा किया जाय वैसा करने में दिक्कत है और इसके अलावा बाकी जो रुपया बचता है उसकी वसूली का सार्टिफिकेट जारी हो गया है । उसकी कार्यवाही की जा रही है ।"

---

*२ मई, १९६२ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया ।

[श्री जयराम वर्मा]

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार है---"श्रीमन्, तफसील से बताने की जरूरत हो तो जैसा कि मैंने बताया जे० के० काटन स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल्स से १० हजार रुपये माहवार की किस्त में वसूली हो रही है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने वसूली रोक दी है तब भी मिल स्वेच्छा से बकाया कर का किस्तों में भुगतान कर रही है। जे० के० काटन जूट मिल्स से जो रकम बकाया है उसके सिलसिले में १९४८--४९ तथा १९४९--५० का जो असैसमेंट हुआ था उसमें जज पुनरीक्षण ने यह फैसला कर दिया कि यह रिअसैस किया जाय। उसके खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। जब तक फैसला नहीं होता तब तक उनके कहने के मुताबिक १९४८--४९ तथा १९४९--५० का रुपया बाद वाले सेल्स टैक्स में मुजरा करने में दिक्कत है। इसके अलावा बाकी जो रुपया बचता है उसकी वसूली का सार्टिफिकेट जारी हो गया है और उसकी कार्यवाही की जा रही है।"

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८८२ पर।)

१९६२--६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३६---सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३७--संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३८---सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५१---सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३६---सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,८८,०२,७० रुपयों के अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३७--संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखाअनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१८,२९,६०० रुपयों से अनधिकृत धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३८---सार्वजनिक निर्माण--कार्यों अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान, द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९४,२८,८०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,८३,४९,३०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह चारों अनुदान मैंने इस वक्त माननीय सदन के सम्मुख रख दिये हैं। मैं समझता हूं कि इसका जितना भी ब्योरा है वह साहित्य से पूरे तौर पर प्राप्त हो जायगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग किस तरह से आगे को अपना काम लिये जा रहा है।

जहां तक पहले अनुदान का सम्बन्ध है इसका खास ताल्लुक रिपेयर वर्क, या मेंटिनेंस से है। इसमें पिछले साल ४ करोड़ २० लाख रुपया रखा गया था लेकिन चूंकि अब काम बढ़ रहा

है, पिछले वर्ष से रोड्स का माइलेज भी बढ़ गया है, साथ ही साथ मानसून के कारण काफी क्षति हुई है और सड़कों पर प्रेशर बहुत काफी है, मैटीरियल वगैरह की कास्ट बढ़ रही है, यह मेंटिनेंस इस वक्त बढ़ कर ५ करोड़ ५ लाख ४० हजार रुपया कर दिया गया है। इसी के मातहत बहुत से छोटे-छोटे काम भी किये जाते हैं। इसमें १२ हजार ४ सौ ९९ मील पक्की सड़कें, १ हजार ३६ मील श्रमदान से सड़कें, और ३ हजार१८० मील ब्राइडल पाथ्स पहाड़ों पर हैं, उनकी देखरेख और मरम्मत इससे होती है।

इसके अलावा दूसरा अनुदान जो है उसका सम्बन्ध सेंट्रल रोड फंड से है। जैसा कि हमारे साहित्य में दिया हुआ है वह केन्द्रीय सरकार से मिलता है। जो पेट्रोलियम ड्यूटी लगती है उसमें से थोड़ा सिविल एविक्शन के लिये छोड़ कर हर स्टेट को बांट दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार मिल कर तय करती हैं और उसके ऊपर वह पैसा खर्च किया जाता है। इसमें १ करोड़ ५६ लाख रुपया पुराना है और कुछ नया भी रखा हुआ है।

जहां तक ओरिजिनल वर्क का सम्बन्ध है उसमें इस वर्ष ५ करोड़ ९१ लाख रुपया इस्तेमाल नहीं हो सका। पिछले वर्ष जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है उसमें भी रुपया रखा गया था, ५ करोड़ कुछ लाख रुपया रखा था। लेकिन पूरा रुपया नहीं खर्च हो पाया। कारण यह था कि उसमें पूरे स्टेट भर के लिये स्वीकृत हुआ था लेकिन उत्तराखंड को बाद में निकाल दिया गया। उसकी वजह से कम हुआ है करीब ५०,६० लाख।

इसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह हमारे सूबे में काफी बनायी गयीं और उसमें भी काफी पैसा पिछले वर्ष रखा गया था लेकिन चूंकि सामान की कमी है, खास तौर से कोयले की कमी है, ईंटों की कमी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की कमी है, इसके अलावा बिल्डिंग साइट्स का सवाल रहता है, जमीन वगैरह एक्वायर करने में, कुछ देर लगती है, और कुछ प्रोसीजरल दिक्कतें होती हैं। इन तमाम बातों में काफी समय लगा और पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाया। लेकिन मैं समझता हूं कि इस साल पूरा पैसा खर्च किया जायगा, पिछले तजुरबे को देख कर आगे का अनुदान उसी रूप में रखा गया है।

जहां तक तीसरे प्लान का सम्बन्ध है मैंने दो एक दफा प्रश्नों के सम्बन्ध में कहा था १९४७ से पहले करीब ९ हजार कुछ मील सड़कें थीं। और दूसरे प्लान के अन्त तक हमारे पास सब मिलाकर करीब १४ हजार मील सड़कें थीं। अब क्योंकि सड़कों की बहुत ज्यादा हमारे सूबे के अन्दर जरूरत है, हर माननीय सदस्य ही नहीं हर नागरिक को आने जाने की सहूलियत चाहिये और आज का जैसा जीवन है उसमें जल्दी से जल्दी हर एक काम को करने की ख्वाहिश हर एक की होती है जिससे कि उसके एकोनामिक कंडीशन और उसकी संस्कृति पर पूरा असर पड़ता है। इसलिये काफी लम्बा-चौड़ा प्रोग्राम करीब ६० करोड़ रुपये का होता था, लेकिन जिस वक्त यह प्लान बना उस वक्त धनाभाव के कारण वह ६० करोड़ से १८ करोड़ रुपये का रह गया और इसमें से ११ करोड़ रुपया वह है जो कि पिछले प्लान के अधूरे रह गये कामों को पूरा करने में खर्च होना है। इस तरह केवल ७ करोड़ रुपया हमारे पास नये कामों के लिये बचता है। इस सात करोड़ रुपये में ५८२ मील नयी सड़क बनाने की योजना हमने रखी है।

अब इन ५८२ मील सड़कों को किस तरह से रखा है, वह मैंने कल भी एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इस वक्त अपने सूबे के अंदर या और और स्थानों पर भी स्टार ऐंड ग्रिड फारमूले से चलने की कोशिश हो रही है। जितने भी चीफ इंजीनियर्स हैं तमाम सूबों के उनका नागपुर में सन् ४७ में एक सम्मेलन हुआ था और उसमें यह तय हुआ था कि हर जिले के अन्दर स्टार ऐंड ग्रिड फारमूले के हिसाब से सड़कें बनाई जायं तो काफी सुविधा लोगों को प्राप्त होगी। इस फारमूले के हिसाब से हर एक बसती में जहां कि खेतीबाड़ी होती हो या और काम होता हो और जहां आबादी दो हजार से पांच हजार तक हो वहां से पांच मील के रेडियस में कोई न कोई

[श्री गिरधारीलाल]

पक्की सड़क मिलनी चाहिये। तो उस हिसाब से इस वक्त हमारा यह विभाग काम कर रहा है और हर जिले में कितना माइलेज होना चाहिये, यह माइलेज उसने निकाला है और उसका साहित्य हरएक माननीय सदस्य के पास पहुंचा होगा। तो उसको देखते हुये और साथ ही हमारे पास जो धन की कमी थी उसको देखते हुये हमने यह देखा कि जिस जिस जिले के अन्दर स्टार ऐंड ग्रिड फारमूले से सड़कें पूरी हो गई थीं उनको छोड़कर बाकी जिलों में इस सात करोड़ रुपये को खर्च करने की कोशिश हम करें। ३१ जिले ऐसे हैं जो कि डैफिसिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उनमें हम उन कमियों को जहां तक पूरी कर सकें वह पूरी करने की कोशिश हमने की है। हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हर जिले के अन्दर गये। वहां जाकर उन्होंने अन्तिरम जिला परिषद् के जो अध्यक्ष हैं, कलेक्टर हैं, पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट हैं और जितने हमारे एम०एल०एज० और दूसरे नुमाइन्दे वहां के हैं उन सबसे सलाह मशविरा लेकर सड़कों का प्रोग्राम तय किया गया और उसके हिसाब से जो कि सूबे में प्रायरिटी तय हुई उस प्रायरिटी के हिसाब से सड़कें तय की गईं और यह सात करोड़ रुपया उसी के हिसाब से हर जिले में बराबर-बराबर बांटने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से तीसरी योजना में ये कार्य किये जा रहे हैं। मैंने जैसा पहले भी एकाध दफा कहा है कि आगे भी कहीं से अगर धन हमको उपलब्ध होगा तो उस वक्त उसी हिसाब से उसके ऊपर सोचा जायगा और यह कोशिश की जायगी कि और भी माइलेज हम बढ़ायें। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास योजना के अन्तर्गत सड़कें बननी हैं वह करीब ५८२ मील सड़कें हैं जिनको कि हम बना रहे हैं।

एक चीज और कह दूं। यह पूरा कार्यक्रम जो इस विभाग का है वह करीब-करीब २१ करोड़ ३६ लाख रुपये का इस वर्ष के लिये है। जो एस्टैब्लिशमेंट इसके अन्दर कार्य कर रहा है उसके ऊपर १ करोड़ २५ लाख का खर्च पड़ता है। तो मैं यह समझता हूं कि वह खर्च तमाम बातों को देखते हुये और परसेन्टेज चार्ज के हिसाब से देखें तो वह कुछ नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर और स्टेट भी हैं, कहीं पर यह खर्च दस परसेंट है, कहीं आठ परसेंट है, कहीं ९ परसेंट है। लेकिन हमारे यहां यू०पी० के अन्दर यह परसेन्टेज चार्ज ६ परसेंट वर्क लोड के हिसाब से आकर पड़ता है। इसके अलावा थोड़ा-सा वर्क चार्ज्ड एस्टैब्लिशमेंट के सिलसिले में भी कह देना चाहता हूं। वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट में जैसा मैंने शुरू में कहा रखरखाव के लिये इस वर्ष हमको ५ करोड़ से थोड़ा सा कुछ अधिक रुपया मिला है। इसी में वर्क चार्ज्ड एस्टैबलिशमेंट है जो इस विभाग में सड़क का पूरा काम करते हैं। वर्क चार्ज्ड एस्टैबिलिशमेंट में कई क्लासेज होते हैं। एक तो उसके टैक्नीकल परसोनल होते हैं, जैसे रोड रोलर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, सुपरवाइजर और मैट आदि इस महकमे का जितना काम है वह सब निर्माण का ऐसा काम है कि जिसके किसी खास काम में बहुत आदमियों की जरूरत पड़ती है। हमेशा उसकी जरूरत नहीं होती है। यह पूरा विभाग ही ऐसा है जिसमें ऊपर के जो हमारे इंजीनियर हैं वह भी इसमें सब के सब परमानेन्ट नहीं हैं। आप जानते हैं कि जितने पहले डिप्टी कलेक्टर अपने कैडर में आते हैं वह सब जल्दी ही परमानेन्ट हो जाते हैं। हमारे यहां इंजीनियर परमानेन्ट नहीं हुआ करते और उनका परमानेन्ट कैडर बहुत कम है। मैं समझता हूं उसमें मुश्किल से कुल एक-तिहाई से भी कम परमानेन्ट होंगे।

जहां तक नये वर्क चार्ज्ड एस्टैबलिशमेंट का सम्बन्ध है वह भी इसी तरीके से चल रहा है लेकिन पहले भी जितना मेन्टेनेन्स का काम है १५,१६ हजार मील सड़कों का उस सब काम के लिये कुछ मजदूरों की हमेशा जरूरत पड़ती है। इसलिये वह बराबर चला आ रहा है। उनकी मांगों पर पूरी तरह से ध्यान देकर उनकी मांगों को पूरा किया गया है। यह जो पी०डब्लू०डी-रिआर्गनाइजेशन कमेटी ने सिफारिश की थीं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुये हम करीब १ हजार आदमियों को रेगुलर एस्टैबलिशमेंट में ले आये हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया उनमें रोड रोलर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ट्रक क्लीनर, सी०सी० मिक्सर ड्राइवर, रोलर फोरमैन, जीप ड्राइवर, चौकीदार, एलेक्ट्रिशियन, वायरमैन यह सब उसमें शामिल हैं। इनकी तादाद एक हजार होती है। यह सब हम रेगुलर एस्टैबलिशमेंट में ले आये हैं। इन लोगों को वही अधिकार प्राप्त

होंगे जो कि इस प्रकार के रेगुलर एस्टैबलिशमेंट को प्राप्त होते हैं और सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होते हैं। पिछले साल से यानी १ अप्रैल, १९६१ से इन लोगों को यह सुविधा दी गई है इसके अलावा और भी तादाद ऐसे लोगों की रह जाती है जो इसमें नहीं आ सके। हमारी कोशिश है कि जितना हो सके इनके लिये भी कुछ किया जाय। अभी यह प्रश्न सरकार के सामने है और जहां तक सम्भव होगा, जहां तक उचित होगा वहां तक जितने भी आदमियों को हम इसमें ला सकते हैं उतने आदमियों को इसमें लाने की कोशिश करेंगे। अब मैं इस पर अधिक न कहकर दूसरी बात का जिक्र करना चाहता हूं।

जहां तक एजेंसी आफ एक्जीक्यूशन की बात है हमारा जितना काम है वह सब ठेकेदारों के द्वारा हुआ करता है। हमारी शुरू से यह मंशा रही है कि हमारे देश के अन्दर और हमारे सूबे के अन्दर सहकारिता के भाव को काफी फैलाया जाय और साथ ही हमने उसको दूसरा रूप भी देने की बात सोची। वह रूप यह है कि हमारे जितने छोटे छोटे वर्क हैं उन सब कामों के अन्दर हम सहकारिता को लाना चाहते हैं। छोटे-छोटे जितने हमारे काम हैं उन कामों को बगैर टेन्डर काल किये हुये हमने उन मजदूरों की यूनियन को देने की बात कही है। सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि कोई भी मजदूर अपनी मजदूर सहकारिता समिति बनाये और वह सारा काम लेना चाहे तो हमारे यहां के जो जिलों के रेट हैं उस पर वह उस काम को ले सकते हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमको उसमें सन्तोषजनक सफलता नहीं मिली क्योंकि हमारे लोग उसमें नहीं आये। लेकिन फिर भी उसमें हम कोई हतोत्साह होकर नहीं बैठे। हमने इस बात की कोशिश की कि जहां तक सहकारी समितियां हैं उनको भी यह काम दिया जाय। हमारे अफसरों का ध्यान इस तरफ गया है और मेरा भी ध्यान उस तरफ है। मेरी बातचीत सहकारी विभाग से हो रही है और उस बातचीत के बाद उस काम के अन्दर तेजी आयेगी और काम और ज्यादा तादाद में हमारे यहां हो सकेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जो काम उनको दिया जायगा उस काम में वह आगे बढ़ेंगे।

जैसा मैंने बीच में कहा इन तमाम कामों में, जो तामीर के काम हो रहे हैं, पी०डब्लू०डी० ही नहीं बल्कि एम०ई०एस०, लोकल बाडीज और प्लानिंग विभाग के भी ऐसे काम हैं जो इस समय कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। इस तरह से जनता के अन्दर बहुत से काम तामीर के चल रहे हैं जिनमें मैटीरियल की जरूरत होती है और वह मैटीरियल बहुत कम प्राप्त हो रहा है। पिछले दो वर्ष से हमने कोल लाने के लिये, ट्रांसपोर्ट करने के लिये कुछ इंतजाम किया लेकिन हमारी जरूरत १२ हजार वैगन्स की है जिसमें से केन्द्रीय सरकार ने ४,८०० वैगन्स की उम्मीद दिलाई है। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि नदियों के जरिये से भी या सड़कों के जरिये से ट्रकों द्वारा इस कमी को दूर किया जाय जो कि हमारे यहां आजकल चल रही है ताकि हम अपने कार्यक्रमों को पूरा कर सकें। इसके अलावा एक बात मैं टेक्निकल आडिट सेल के बारे में बतलाना चाहता हूं कई बार एक बात सामने आती थी कि हमारे यहां जो काम हो रहे हैं उन के ऊपर पूरे तौर से देखभाल नहीं हो पाती। मैं होऊं या दूसरा कोई व्यक्ति इधर का या उधर का हो, वह उन तमाम कामों को डिटेल में नहीं देख सकता और इन सब बातों को देखकर एक टेक्निकल आडिट सेल की स्थापना हमारे सूबे में की गयी थी और वह हर जिले में, हर स्थान पर जाता है और जहां भी काम हुआ है, जैसे मकान हैं, उनकी बुनियाद कितनी गहरी है, कैसा मैटीरियल उसमें लगा है, पेमेंट में क्या दिक्कत हुई और जितनी भी इस प्रकार की बातें हैं उन सब को देखता है और वह सरकारी कर्मचारियों के नोटिस में उन्हें लाता है। जहां जरूरत होती है, उचित कार्यवाही भी वहां पर की जाती है और मैं समझता हूं कि इन तमाम बातों का एक अच्छा असर पड़ा है और उससे कम से कम वह शिकायत जो कि लोगों को अक्सर हुआ करती थी, अब नहीं होनी चाहिये। इन तमाम बातों के अलावा मुझे आखिर में, जैसा मैंने शुरू में कहा था यही कहना है कि सन्

[श्री गिरधारीलाल]

४७ में इस विभाग के पास करीब ९,००० मील सड़कें थीं, आज १४,००० मील के करीब सड़कें हैं और उम्मीद है कि २,००० मील सड़कें इस योजना काल में और बन कर पूरी हो जायेंगी। इन शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह माननीय सदन इन अनुदानों को, जैसे कि उसने तमाम और अनुदान स्वीकार किये हैं और जिनकी पूर्ति के लिये इन अनुदानों की बहुत जरूरत है, बिला हील हुज्जत के स्वीकार करने की कृपा करेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपकी आज्ञा से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी के द्वारा मांगी गयी धनराशि में कमी कर के एक रुपया करने का कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—चारों अनुदानों के सम्बन्ध में आप कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—जी हां, अनुदान संख्या ३६,३७,३८ तथा ५१ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, यह एक ऐसा कटौती का प्रस्ताव है कि जिस पर मैं यह समझता हूं कि कटौती पेश करते समय जरूर सोचना चाहिये और मैंने इस बात को सोचा कि जो धनराशि मंत्री जी विभाग द्वारा खर्च करने के लिये मांग रहे हैं उसे कम करके १ रुपया कर देने का मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी के विभाग को हम एक पैसा भी देना नहीं चाहते। स्पष्ट मतलब यही है। मेरे दिल में इन शब्दों का यही अर्थ है और इसीलिये मैं सदन से कहना चाहता हूं कि इस मुहकमे को एक भी पैसा लेने का हक नहीं है।

श्रीमन्, प्रश्न उठता है कि आखिर इस मुहकमे को एक भी पैसा पाने का हक क्यों नहीं है? सार्वजनिक निर्माण विभाग का मुख्य विषय है सड़क। श्रीमन्, मंत्री जी बहुत दिनों से इस विभाग के मंत्री रहे हैं शायद मुख्य मंत्री लोग बदलते गये हैं और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री की गद्दी बरकरार रही है। मुझे इस बात पर, उनकी कार्यकुशलता पर उनको मुबारकबाद देने की इच्छा होती है। लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि दुनियां में ऐसे भी लोग हैं जो इसी शरीर से चंद्रलोक तक जाने की इच्छा रखते हैं और वहां जाने के प्रयत्न में लगे हुये हैं श्रीमन्, यहां मंत्री जी एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिये हम को सड़क नहीं दे सकते। श्रीमन्, आप सोचें इस बात को। मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहूंगा कि दुनियां के लोग इस बात के कम्पटीशन में लगे हुये हैं कि पहले कौन जाय, कौन उस लोक पर पहले कदम रखें। परन्तु हम एक ऐसे बदकिस्मत वर्ग के लोगों में से हैं, ऐसे बदकिस्मत व्यक्तियों में से हैं, इस देश के और इस प्रांत के रहने वाले, कि जिस सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी के काल में और जो परमानेन्ट मंत्री हैं, एक तरह से इस तथाकथित समाजवादी सरकार के, तो श्रीमन् सोचें आप, मैं अगर यह विश्वास न करूं और इस कटौती के प्रस्ताव को न पेश करूं तो करूं ही क्या।

अब एक बात आती है अंत में कि आखिर यह सवाल पैदा कैसे हुआ? यह सब बातें क्यों आयीं? श्रीमन्, आप देखें कि मंत्री जी ने कल एक वक्तव्य के सिलसिले में इसी सदन में जवाब दिया कि मंत्री जी मिनिमम वेज कमेटी के रिपोर्ट नहीं जानते। उस पर मंत्री जी ने गौर नहीं फरमाया, मिनिमम वेज कमेटी की रिपोर्ट पर। उस मिनिमम वेज कमेटी की रिपोर्ट के जिसके मातहत मंत्री जी का कमरा साफ करने वाला आदमी भी आता है। जो कि सुबह जाता होगा, शाम जाता होगा, छोड़ दिया जाय और लोगों को। मंत्री जी के और जो दूसरे काम-काज है, जैसे फुलवारी ठीक करने का काम, अगर एक मिनट उसने देर कर दी तो उन्हें गुस्सा आजाता होगा। कहीं कोई गलती हो गई तो पीठ पर कौन कहे सिर पे बजता होगा। श्रीमन्, एक बात के बिना ख्याल किये हुये कि जिस पीठ पर जिस सिर पर वह गुस्सा उतारा जाता होगा उसके पेट में कुछ है कि नहीं है, यह ख्याल मंत्री जी को शायद नहीं होगा। आप के द्वारा मैं यह

निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर मिनिमम वेज कमेटी की रिपोर्ट कैसे लोगों के लिये है ? गांव में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिये, गांव में सड़कों पर काम करने वाले लोगों के लिये, सड़क बनाने वाले लोगों के लिये, ठेकेदारों के लिये, कंकड़ ढोने वालों के लिये, गाड़ी लादने वालों के लिये, कंकड़ कूटने वालों के लिये, ईंट जोड़ने वालों के लिये, यही लोग तो हैं मिनिमम वेज इन्हीं का इससे फायदा होगा । इस मौलिकता की ओर श्रीमन्, मैं, समझता था और मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मंत्री जी जैसे आदमी के ध्यान में यह सवाल पैदा नहीं होता है । इसी सदन में बार.बार यह सवाल पैदा होता है कि पिछले-पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये, अनुसूचित जाति के लोगों के लिये, सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित हैं या नहीं हैं । लेकिन जब यह सवाल पैदा हो कि इस मुहकमें के मंत्री जी जिन पर यह मुहकमा बेस करता है, और इस मुहकमें के मंत्री जी अगर उस रिपोर्ट को न जानें तो मैं नहीं समझता कि इस अनुदान का समर्थन करने वाला एक भी सदस्य इस सदन में कोई निकलेगा ? मेरा ख्याल है कि चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों सभी लोगों ने यह सवाल इस सदन में किया और बिना इस बात का ख्याल किये हुये कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, उसका क्या दृष्टिकोण है । प्रायः सभी लोग, चाहे उनका राजनैतिक दृष्टिकोण भिन्न रहा हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण भिन्न रहा हो, चाहे धार्मिक रहा हो, इस प्रश्न पर एक मत रहे हैं । इसलिये, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट उनकी नजर से नहीं गुजरी, उस बात पर ताज्जुब होता है और इसलिये और भी ताज्जुब होता है कि क्योंकि माननीय मंत्री जी बहुत पुराने मंत्री हैं मैं तो अभी दो दिन का नौसिखिया ही उनके सामने हूं । क्या माननीय मंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग एटेन्ड नहीं कीं ? इसको जब मैं सुनता हूं तो मुझे शक होने लगता है । श्रीमन्, आप भी एक कमेटी के अध्यक्ष थे और वह कमेटी ऐसे स्थान के लिये बनी हुई थी जिस स्थान का सम्बन्ध इस प्रान्त से ही नहीं, इस समूचे देश के एक ऐसे भू-भाग से है जो इस देश की और इस प्रदेश की नाक है और जहां पर इस देश और प्रदेश के ही यात्री नहीं जाते हैं, वरन् विदेशों के भी यात्री जाते हैं जिसको पहाड़ी इलाका कहते हैं, तीर्थ स्थान कहते हैं, जहां पर अनेक मोटर दुर्घटनाओं की चर्चा आये दिन हुआ करती है और जहां के लिये केन्द्रीय सरकार स्पेशल ग्रान्ट देती है । उसके लिये स्पेशल विभाग बने हुये हैं, पी०डब्लू०डी० की स्पेशल बेंचें खोली हुई हैं, डिवीजन्स बने हुये हैं । ताकि वहां का काम ठीक प्रकार से हो । मुझे शक होने लगता है कि उस कमेटी की रिपोर्ट भी माननीय मंत्री जी के सामने आई या नहीं ? मैंने उसको जानने की कोशिश की, मालूम हुआ रिपोर्ट अभी छपी नहीं है । मैं नहीं कह सकता कि उस रिपोर्ट में क्या है, मगर, श्रीमन्, उसमें एक बात जरूर है और वह यह कि मोटर दुर्घटनाओं के लिये मुख्यतः विभागों को जिम्मेदार बताया गया है एक परिवहन विभाग तथा दूसरा माननीय मंत्री जी का विभाग । इस समय मैं परिवहन मंत्री जी के विभाग को छोड़ देता हूं, इसी विभाग को लेता हूं ।

श्रीमन्, जो टार्गेट रखा गया वहां की सड़कों की बढ़ोत्तरी के लिये, मैं पूछता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह पूरा हो गया ? आखिर उसकी क्या विशेषता है ? इसी सदन में कई बार वह प्रश्न आ चुका है और पहाड़ के सदस्यों ने भी इस बात को बार-बार दोहराया है कि केन्द्रीय सरकार जब इस काम के लिये स्पेशल ग्रांट देती है तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कृपा करके कि ग्रांट का प्रापर यूटीलाइजेशन किस काम के लिये हुआ ? और जो टार्गेट रखा गया था, क्या उस टार्गेट तक मंत्री जी अब तक पहुंच पाये ? अब तक की जो प्रगति है, आगे की बात छोड़ दें, मैं उसी आधार पर आगे को भी आंकने की कोशिश करता हूं । श्रीमन्, भूत को देख कर ही भविष्य का अन्दाजा लगाया जा सकता है । मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि समूचे देश में क्या रूप है और अपने प्रदेश में क्या रूप है, कितनी तरक्की हुई ? इस सम्बन्ध में श्रीमन्, आप देखें कि १ हजार की जनसंख्या पर बंगाल में २२ मील सड़क बनी है और मद्रास में ५१, आंध्र में ४६, मैसूर में ५९ और अपने प्रदेश में १९ । कितनी तारीफ करें और अपने मंत्री जी के मुहकमे की

[श्री कल्पनार्थसिंह]

यह मुहकमा निहायत ही साधुवाद के काबिल है। यही नहीं, यह भी है कि जो अनुदान हमको केन्द्रीय सरकार से इस प्रदेश की तरक्की के लिये मिल सकता था हमारी जन-संख्या के आधार पर और हमारी मौलिक आवश्यकताओं को देखते हुये, वह भी हम नहीं प्राप्त कर पाये, उसका कारण क्या है, यह मंत्री जी बतला सकेंगे। उत्तर प्रदेश और प्रदेशों की बनिस्बत काफी पिछड़ा हुआ है। जो अनुदान केन्द्रीय सरकार से मिला, उसका प्रतिशत अगर देखा जाय तो आसाम को २८.५ है, केरल को ३२.२८, मैसूर को २०.३७ और उत्तर प्रदेश को १०.२६। अगर समुचित प्रतिशत लगाया जाय भारतवर्ष का जो दूसरे प्रान्तों को अनुदान इस काम के लिये दिये गये हैं, तो उसका प्रतिशत १३.९ है। क्या कारण है कि हम अन्य प्रदेशों की अपेक्षा हर मामले में पीछे हैं ?

अभी नियोजन विभाग की चर्चा पर सुनने को मिला कि उस मामले में जो औसत आमदनी है एक हिन्दुस्तान के नागरिक की, उसके मुकाबिले में उत्तर प्रदेश के नागरिक की आमदनी कम है। इसका क्या कारण है ? एक कारण जो मुख्य है वह मुख्य मंत्री जी के मुहकमे से भी संबंधित है। इसलिये कि सड़कें नहीं होंगी तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, यातायात नहीं बढ़ेगा, सड़कें नहीं होंगी तो प्रशासन ढीला होगा। सड़कें नहीं होगी तो सभ्यता कैसे चलेगी ? सभ्यता भी तो इन सड़कों पर ही चलती है। चाहे एयरवेज पर चलें, चाहे वाटरवेज पर चले, चाहे मंत्री जी के रोडवेज पर चले, लेकिन सभ्यता तो चलती सड़कों पर ही है। दुनिया के देशों में और अपने देश के दूसरे प्रांतों में, जब हमारी साख घटेगी तो हमारी सभ्यता भी घट जायगी और हमारी तरक्की भी घट जायगी। सामान्य प्रशासन या पुलिस प्रशासन सब चौपट हो जायगा। बहुत से सदस्य जानते होंगे कि अगर कहीं डकैती हो गई तो दरोगा जी कहेंगे कि घोड़े के पेट में दर्द हो गया और मोटर जाती नहीं थी इसलिये मौके की तहकीकात पर नहीं गया.....

श्री अध्यक्ष—लोग कह रहे हैं कि आप बहुत इत्मीनान से बोल रहे हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—यह इत्मीनान का विषय ही है। खास तौर से कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है। माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि मैं इस विभाग के सम्बन्ध में माननीय गोविंद सहाय के शब्द कोट करूं 'प्लन्डर विदाउट डेंजर'। क्या आप यही सुनना चाहते हैं ? या फिर राजाजी के शब्दों को इस्तेमाल करूं जो कि उन्होंने, जब वह मद्रास के मुख्य मंत्री थे, तब कहे थे....

श्री अध्यक्ष—आप दूसरों का ख्याल न कीजिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, रेफ्रेंस के लिये ही कह रहा हूं। मैं एनेमी नम्बर एक तो नहीं कहूंगा, लेकिन दूसरे नम्बर की बात पी० डब्लू० डी० के लिये उन्होंने जरूर कही थी और आज तो शायद एनेमी नम्बर एक होगा यह मुहकमा। चीनी आक्रमण के समय उत्तराखंड में किस प्रकार सड़कें बनाई गई, किस प्रकार यातायात के साधन दिये गये, क्यों नहीं इसके पूर्व इस स्ट्रेटेजी का ध्यान रखकर वहां का उत्थान किया गया ? मैं भी एक बार्डर जिले से आता हूं। जो देश अफीम के नशे में चूर रहते हुये बिना हमारी जानकारी के इतनी तेजी से बढ़कर हमारी सीमा में चला आवे और मंत्री जी का मुहकमा अपनी सीमा की रक्षा के लिये स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखकर कोई काम न कर सके तो फिर क्या कहा जाय ? श्रीमन्, इस सदन में ही जो छोटे छोटे भोंपे, जालीदार लगे हुये हैं, बहुत से माननीय सदस्य तो सोचते होंगे कि आखिर यह क्या हैं। कोई कहता है हीटर हैं, कोई कहता है कूलर हैं। मैं समझता हूं मंत्री जी के कारण ही ये भोंपे और डंडे आज भी ज्यों के त्यों पड़े हुये हैं।

श्रीमन्, मैं गोरखपुर जिले से आता हूं वहां पर एक बर्डघाट का पुल है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का वह पुल है। इस किताब में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। हो सकता है कि गलत हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है विभाग के वही इंजीनियर महोदय थे, जो इसके पहले बनारस में वरुणा का पुल बनाये और वह भी साफ हो गया। उनके कदम गोरखपुर में गये

और अभी पुल जुटने भी नहीं पाया था कि ठेकेदार को जिस दिन पेमेंट हुआ उसके दूसरे दिन वह कोलैप्स कर गया। अभी इनक्वायरी कमेटी बैठी हुई है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। कौन जिम्मेदार है, अधिकारी या ठेकेदार ? यह अभी तय नहीं हुआ, लेकिन ठेकेदार साहेब का पता गोल, ठीक है और कितना रुपया वहां खर्च किया जा रहा है पुल के को लैप्स करने के बाद ? ४०,००० रुपये खर्च करके नदी में एक ऐसी सतह बनाई गई कि उसमें लोहा और दूसरे सामान को बचाया जिसकी कीमत आती थी २०,२२ हजार रुपया। तो २० हजार को बचाने के लिये एस्टीमेट बना ४०,००० का। प्लैटफार्म जो बनाया वह बहा और ४० हजार और २० हजार दोनों गये। यह वह मुहकमा है कि जहां सूद भी गायब और मूल भी गायब। अभी वहां बाढ़ भी नहीं आई है। लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ खेलने का यह मुहकमा अभी भी साहस करता है। सवारी गाड़ियों पर उस पुल को उड़ाने के लिये डायनामाइट और दूसरे विस्फोट पदार्थ लाये जाते हैं। वे सवारी गाड़ी से लाये जाते हैं। पता नहीं, किराया किसका चार्ज होता है, माल गाड़ी का, या हवाई जहाज का या मोटर का। अभी एक पुल जौनपुर में बन रहा है जिसका बहुत जिक्र किया गया, चन्द्रबक का पुल। उसका भी पाया धंस गया। जाने दीजिये लखनऊ में ही क्या हुआ ? यहां भी गोमती, वहां भी गोमती, खखड़ा नाला का एक पुल हमारे जिले में है और वह पूरा भी नहीं हुआ कि ध्वस्त ! पारसाल देवरिया जिले में हाटा के पास एक पुल बना। गन्ना विभाग बनवा रहा था और बनाने वाले थे पी०डब्लू०डी० के आदमी। उसका छज्जा खोला ही नहीं गया था कि वह धंस गया और २ आदमी भी चल बसे। माननीय नेता सोशलिस्ट दल मौजूद हैं, उनसे पूछ सकते हैं। इस मुहकमे के लिये अगर कटौती का प्रस्ताव ेश न किया जाय तो और किसके लिये किया जाय, जिससे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, शांति, स्वाधीनता और अस्तित्व खतरे में हो।

श्री अध्यक्ष––ऐसे मुहकमे को तो बजाय कटौती करने के और अधिक धन देना चाहिये।

श्री कल्पनार्थसिंह––जितना रुपया इस विभाग को दिया जाता है उसे वह खर्च भी नहीं कर पाता है। रुपया भी उसे देना चाहिये जो खर्च कर सके। जहां पुराने और अनुभवी होने के बावजूद भी मंत्री जी रुपये को खर्च नहीं कर सके तो मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वह कैबिनेट छोड़ कर चले जावें, लेकिन यह मेरी प्रार्थना जरूर है कि वह कुछ अदला-बदली कर लें। मंत्री जी बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन किसी दूसरे मंत्री को अगर आने दें या अपने ही पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या डिप्टी मिनिस्टर को तरक्की दे दें तो कोई परेशानी नहीं होगी, वह फौज तो बढ़ ही रही है। इसलिये भी मैं कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

मैं इंजीनियर साहबान की बात करूं या कंकड़ कूटने वालों की बात करूं ? कहां से पहले शुरू करूं ? तो मंत्री जी ने अपने लैक्चर में शुरू किया वहां से शुरू करता हूं। २० साल हो गये काम करते इस महकमें में इंजीनियर बेचारे को, लेकिन वह अभी भी अस्थायी है। उनको हां–हुजूर से ही फुरसत नहीं मिलेगी। तुरन्त पत्ता गोल हो जायगा, १ महीने की तनख्वाह मिल जायगी या नोटिस मिल जायगी। बेचारे मां बाप ने पढ़ाया रुपया पैसा काट कर रुड़की इंजीनियरिंग कालेज में भेजा, वहां पढ़ाया और इंजीनियर साहबान के ठाठबाट देख कर समझा कि हम तो ंद्र के स्थान पर पहुंच गये। लेकिन जब उनके दिल में यह भावना घर करती है कि यह तो आकाशवृत्ति है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, तब उसे अनिश्चितता की वजह से परेशानी होती है। जिस दिन चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नाराज हो गया या मंत्रीजी के सलाहकार नाराज हो गये, उस दिन उसका पत्ता गोल हो जायगा। वह बेचारा परेशान रहता है, कमाने में, लूटने-खसोटने में जल्दी करता है

[श्री कल्पनाथसिंह]

क्योंकि कौन जाने, कब पत्ता गोल हो जाय ? उनका परसेंटेज होता है कि अगर तुम इतना परसेंट नहीं दोगे तो तुम्हें ज्यादा सजा भी नहीं देंगे तो पानी की लहर गिनते ही भेज देंगे । वह उसे रिश्वत नहीं कहते हैं, बल्कि दस्तूरी कहते हैं । जो जितना बड़ा है उसकी उतनी अधिक दस्तूरी होगी और जो छोटे हैं उन्हें उतना ही ेसा जायगा, वरना सलामी देना पड़ती है । मैं एक नहीं, १०१ इंस्टांसेज इस तरह की दे सकता हूं । अगर बांड कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसे पैनाल्टी के रूप में सजा नहीं दी जा सकती तो कहेंगे कि आगामी लेबर लगा लो, मस्टर रोल पर वह काम करेगा और उसकी हाजरी होगी घर पर । पैसा कहां जायगा ? ओवरसीयर साहेब की पाकेट में । बिल पास करेंगे इंजीनियर साहेब । तो नीचे से ऊपर तक एक भ्रष्टाचार का घर बना हुआ है । इस भ्रष्टाचार को सभ्यता की शक्ल दे रखी है । उसे भ्रष्टाचार न कहकर दस्तूरी कहा जाता है । कौन ऐसा आदमी है जो इस मुहकमे में कोई काम लेकर जाय और उसे सलामी न देनी पड़ती हो ?

छोड़िये, श्रीमन्, और सारी बातों को । मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जिले से मैं खुद आता हूं उसमें, बस्ती और देवरिया जिलों में अयोध्या से लेकर मिथिला तक एक सड़क जाती थी पुराने जमाने में । रामचन्द्र जी की जिस सड़क से बारात गई थी उसका नाम है राम-जानकी रोड । बुद्ध का भी उससे कुछ प्रसंग आता है । अवध और मिथिला के सम्बन्ध को भी यह महकमा अच्छी तरह से कायम नहीं होने देता है । श्रीमन्, आप और हम अवधवासी हैं और वहां से जो सम्बन्ध होने की बात है उसमें यह विभाग बाधक हो जाय, तो मैं कैसे इस विभाग की तारीफ करूं ? बस्ती जिले के भी माननीय सदस्य बैठे होंगे, पूछ लें आप उनसे । मैं भी स्वयं उस सड़क पर रहने वाला हूं । कोई हंसने के लिये मैं यह बात नहीं कह रहा हूं । उस सड़क के बारे में जब गोरखपुर जिले के अन्तरिम परिषद् ने प्रस्ताव पास करके हमारे चीफ इंजीनियर महोदय के पास भेजा डेढ़ साल पहले, तब उनका लैटर महीना २ महीना पहले ही पहुंचा है कि यह सड़क पानी से डूब जाती है । यहां सड़क नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वह बाढ़ का एरिया है । माननीय उग्रसेन जी मौजूद हैं, पूछ लीजिये, मैं गलतबयानी नहीं कर रहा हूं । वह उस इलाके के हैं । इस समय वह स्टार–ग्रिड फार्मूला कहां गया ? उस फार्मूले का कत्ल स्वयं मंत्री जी ने और उनके महकमे ने इस मौके पर कर डाला है । देवरिया, बस्ती और गोरखपुर जिलों के लोग यहां दोनों तरफ हैं । मेरी बात मंत्री न मानें तो वह अपनी ओर के लोगों से ही और इधर के लोगों को बुलाकर, मुझे छोड़ दीजिये, पूछ लें कि मेरी बात सही है या गलत । वह सड़क बननी चाहिये या नहीं । जिस तहसील में मैं रहता हूं वह बाढ़ के दिनों में घाघरा और राप्ती से घिर कर टापू बन जाती है । तहसील का हेड-क्वार्टर, मंत्री जी बता दें, किसी सड़क से कनेक्टेड है ? कौन सी पक्की सड़क है ? वहां टाउन एरिया से भी बड़े गांव हैं कैसे प्रशासन चलेगा ? यहां मैं देख रहा हूं कि हमारे शिक्षा उप मंत्री जी नहीं हैं । उनके दरवाजे पर होकर एक सड़क जाती है । और वे पिछले १० सालों से इस सदन के सदस्य हैं लेकिन वह सड़क भी नहीं बन पायी । अब वे उप मंत्री हो गये हैं अगर इसी बहाने माननीय मंत्री सड़क बनवा दें तो भी मैं उनका शुक्रगुजार हूंगा । जिस गोरखपुर जिले का पहले पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी नहीं हुआ था उसका एक डिप्टी मिनिस्टर तो हुआ ? इसी तहसील में बेलघाट ोआब का एक हिस्सा है । वहां भी सड़क नहीं है । वहां पर रहने वाले किसी विधायक का गांव भी पक्की सड़क से जुड़ा नहीं है । वहां बड़े-बड़े कस्बे हैं । ये बाढ़ में डूब जाते हैं और आने जाने का कोई साधन नहीं रहता, बर्डघाट और दोहरी घाट के घाट बन्द हो जाते हैं लेकिन जब दोहरी घाट का पुल बनाने को कहा जाता है तो मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है । यह मार्ग नेशनल हाइवे पर है और हिमालय की उस सरहद के पास है जिसको आज खतरा ेदा हो गया है । माननीय नरसिंहनारायण जी ने कई बार मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और इससे पूर्व भूतपूर्व माननीय सदस्य गौरीराम गुप्त जी ने भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई ।

दोहरीघाट वाले पुल के बारे में एक बड़ी मनोरंजक बात है। मंत्री जी कहते हैं कि पुल नहीं बनेगा। सड़क वहां मौजूद है। लेकिन मंत्री जी ने एक डिमार्केशन लाइन तैयार कर दी है और किसानों से कह दिया है कि इतनी जमीन में अगर जोता बोया तो खैरियत नहीं है। प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है लेकिन यह जमीन लेने की योजना किस योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है।

जमीन के मुआवजे में भी बर्डघाट पर जो तमाशा और भ्रष्टाचार हुआ है वह मामला भी हाईकोर्ट तक गया था। मंत्री जी को यह बात मालूम है लेकिन मंत्री जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

मंत्री जी कभी-कभी बाढ़ का जिक्र कर दिया करते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि बाढ़ वाला मंत्री कौन है–सिंचाई मंत्री हैं, सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं अथवा राजस्व मंत्री हैं। मेरे ख्याल से तीनों ही बाढ़ वाले मंत्री हैं जो प्रतिवर्ष हमारे यहां बाढ़ भेजते हैं, और उसके द्वारा हमें बरबाद करते हैं। मेरे पास इसका सबूत है कि मेरे जिले में नियोजन विभाग ने भौवापार-बेला बांध बनाना शुरू किया जिसमें आधी रकम तो अनुदान के रूप में सरकार द्वारा मिली और आधी रकम जनता ने श्रमदान द्वारा दी, जिस श्रमदान का जिक्र आपके लेखा-जोखा में है। लेकिन उस श्रमदान से बांधे जाने वाले बांध में कई हजार रुपये खर्च हो रहे हैं, इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी करना चाहें तो कर लें। लेकिन जब उनके इंजीनियरों ने देखा कि अब काम चलने वाला नहीं है और कोई गड़बड़ी हो जायगी तो मनोली बांध का बहाना लिया गया और उस बहाने से जनता और नियोजन विभाग द्वारा बनाये गये बांध को सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता की देखरेख में बनवा कर उसका सत्यानाश हो जाने दिया गया और माननीय मंत्री जी का मुहकमा इतना हावी है कि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता की एक न चली, वहां के लोकल एम०एल०ए० की एक न चली, नियोजन विभाग की एक न चली और जिलाधिकारियों की एक न चली और वह बंधा जो सब के परिश्रम से बनाया गया था उसे तोड़ फोड़ कर बहा दिया गया। जब वहां बाढ़ आती है और ऊपर तक पानी आ जाता है तब मंत्री जी का मुहकमा हल्ला करता है कि शहर डूबा, गांव डूबे और शहर तथा गांव को बचाने के लिये उस मुहकमे के लोग जुट जाते हैं जिसमें लाखों, हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं। हजारों का तो कोई हिसाब ही नहीं रहता। कितना बालू डाला गया, कितना लोहा आया, कितने कंकड़ व पत्थर लगे और वे सब बह गये। शहर बनाने के नाम पर मलौनी बांध का यह सारा तमाशा होता है। अब उस बांध से एक कैंची निकाली जायगी और वह बंधा भी बना रहेगा। इसका नतीजा यह होगा कि इनके घेरे में जो गांव पड़ जायेंगे उनके डूबने का खतरा पैदा हो जायगा। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है, उधर के बैठने वाले भी बहुत से सदस्य इस बात को जानते तो हैं लेकिन जब वोट देना होगा तो उधर ही दे देंगे। लेकिन जो सच्चाई है वह कहनी चाहिये, उसमें कोई हर्ज नहीं है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन दें कि वे इस मुहकमे से भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती व गड़बड़फिकेशन को खत्म करने की जिम्मेदारी लेते हैं। फिर अगले साल जब बजट आयेगा तब उस पर चर्चा होगी और देखा जायगा कि इस दिशा में क्या किया गया।

इतना ही नहीं, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। इम्पलाइज की बात ही आप देख लें। मेरा कहना यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के पैरा ३३ के अध्याय ३७ में यह लिखा हुआ है कि आकस्मिक श्रमिक प्रणाली को जहां तक सम्भव हो सके समाप्त किया जाय क्योंकि इस प्रथा के अन्दर न तो कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान रहती है और न नौकरी में संतोषप्रद सुविधायें ही प्राप्त होती हैं और अन्य स्थानों पर इस प्रकार के कर्मचारियों का होना असम्भव है। श्रीमन्, आप देखें कि जब योजना आयोग का यह मत है कि ऐसे कर्मचारियों के

[श्री कल्पनार्थसिंह]

बारे में जिन कर्मचारियों का जिक्र अभी माननीय मंत्री जी ने किया उसकी पूर्ति वे वर्कचार्ज कर्मचारियों को रख कर करते हैं जिनकी सारी जिन्दगी टेम्पोरेरी रहते हुए ही बीतती है। वर्क चार्ज्ड क्या बल्कि डेली वेजेज पर उनका एप्वायन्टमेंट होता है। वह जिन्दगी भर डेली वेजेज पर ही रहेंगे, जिस नींद वह सोयेगा उसी नींद मर जायगा, एक रात तो उस को आप परमानेंसी का सपना देखने का मौका दे दें। क्या वजह है कि मंत्री जी इन कर्मचारियों को मारना चाहते हैं? आप को एफीशियेन्ट वर्क तो जरूर चाहिये लेकिन उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई की, दवादारू की, बाल-बच्चों की रोटी और उनकी रोजी की कोई व्यवस्था न होगी, कोई गारंटी न होगी तो उसका क्या मन आप के काम में लगेगा।

माननीय मंत्री जी ने केपिटलिस्ट सोसाइटी की बात कही। मैंने कल आप के द्वारा पूछना चाहा था लेकिन वक्त नहीं मिला और मैं पूछ न सका लेकिन मैं आज मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह केपिटलिस्ट सोसाइटी जिसका कि मंत्री जी ने जिक्र किया यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार हुई है? जरा इसका हवाला मंत्री जी दे दें। योजना आयोग की बात मैंने आप से निवेदन की, इतना ही नहीं यह सुरक्षा विभाग के कर्मचारी जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं ३० दिन काम कर लेते हैं तो उन्हें भी अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भांति सुविधायें मिल जाती हैं। रेलवे में भी यदि इस तरह से कोई कर्मचारी काम करते हैं तो लगातार ६ मास काम करने के बाद उनकी नौकरी अस्थायी मान ली जाती है और डाक और तार विभाग में भी अगर आप देखें तो सामान्यतः आकस्मिक श्रमिक आदि दैनिक कार्य करने वाले कर्मचारियों का समय ३० दिन से अधिक नहीं होता और उसके बाद इस विभाग में भी उनको अस्थायी मान लिया जाता है लेकिन पता नहीं मंत्री जी का कौन सा महकमा है और कौन सा तरीका है कि कभी किसी को वह सुरक्षा देने को तैयार ही नहीं हैं? बार-बार इस पर जोर दिया जाता है लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगती, इसका कारण क्या है? मंत्री जी मार्केट रेट पर मजदूरी देते हैं, क्या आजादी के बाद यही देश के संविधान में लिखा है? क्या यही समाजवाद लाने का तरीका है? क्या गेहूं, चावल की तरह इसी तरह से आदमी की कीमत मार्केट वैल्यू पर लगाई जायगी? यह मंत्री जी का बताया हुआ फार्मूला है। न तो मंत्री जी मिनिमम वेजेज कमेटी ही बिठाते हैं कि जो इस विभाग की तमाम बातों पर विचार करती। मैं तो उनसे एक हाईपावर कमीशन बिठाने की मांग करता हूं वह इसको मंजूर करें, वह केवल यही विषय ले और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार आदि से उसका कोई वास्ता न हो, केवल उन कर्मचारियों के लिये वह बिठावें जिनको कि उनका हुकुम नामा पूरा करना है। मैं चाहता हूं कि इस तरह का कमीशन बनाया जाय जो उनकी कंडीशन आफ सर्विस की जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे। एक डिप्टी मिनिस्टर साहब के जिम्मे यह काम सौंपा गया था और एक जी०ओ० भी निकला था, पता नहीं जांच हुई या नहीं, क्या हुआ मैं नहीं कह सकता। बातें बहुत सी कहनी थीं लेकिन वक्त कुछ कम है। जो डिसिप्लनरी इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट को इस माने में तो माना जाता है कि जब मजदूरों को निकालना होता है, मेट, सुपरवाइजर, बेलदारों को जब निकालना होगा तो उस की सिफारिश को मान लिया जायगा लेकिन जब सुविधा देने की बात होगी तो वह लागू नहीं होगी। ऐसी हालत में एक ही हाथी के ४ दांत वाली कहावत इस विभाग पर लागू है। सेन्ट्रल वर्कशाप कानपुर में जब १९४७ में रोडवेज महकमा बना तो उसके बाद उन कर्मचारियों को काम करने के बाद रेगुलर बना दिया गया जो वर्क चार्ज में थे। आप ही के राज्य के एक विभाग में ऐसा हुआ है। इस महकमे को भी तो सोचना चाहिये कि उन लोगों को रेगुलर स्टाफ पर ले आये। राठौर साहब अब मोटर पर से सड़क पर चले आये वह अवश्य सलाह देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, कि सड़क के कर्मचारियों को जो कंकड़ तोड़ने वाले हैं, ईंटा ढोने वाले हैं, उनके दर्द की कहानी जरूर सरकार के दिमाग में जायगी और मुझे उम्मीद है अधिकारी इस पर खयाल करेंगे।

बार्डर एरिया, जिसका मैंने जिक्र किया, में प्राइवेट सेक्टर के लोग पहाड़ों में बर्फ काटने के लिये अलग से अलाउन्स देते हैं। लेकिन मंत्री जी के महकमे में इस तरह का कोई अलाउन्स नहीं।

इसका क्या कारण है। यही नहीं १२ मील एक मेट दौड़ता रहता है, ओवरसियर को भत्ता मिलता है, दूसरे अधिकारियों को भत्ता मिलता है लेकिन मेट बेचारे को ट्रांसफर पर भी कुछ नहीं मिलता, वर्क चार्ज के किसी आदमी को दूसरे जिले में भेजे जाने पर कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जाता। इसका क्या कारण है ? यह कौन-सा समाजवाद है ?

इतना ही नहीं, ओवर टाइम की भी बात मैं जानना चाहूंगा। हर महकमे में अगर अधिक काम करने का पैसा मिलता है तो मंत्री जी के महकमे में क्यों नहीं मिलता ? मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि उन लोगों पर जिन पर मंत्री जी का और विभाग के सारे अधिकारियों का बोझ लदा हुआ है, उनके ऊपर रहम करें और उन छोटे आदमियों पर रहम करके, दया करके, जो चिलचिलाती धूप में कंकड़ तोड़ते हैं, ईंटा ढोते हैं, उन पर दया करके अगर मंत्री जी हमारे सुझाव को मानेंगे कमीशन के नियुक्त करने का, भ्रष्टाचार के लिये एक स्पेशल एनफोर्समेंट स्क्वायड बनायें तो मेरा खयाल है जो भ्रष्टाचार रिवाज और दस्तूर बनता जा रहा है, जो आज हमारी नस-नस में व्याप्त होता जा रहा है वह समाप्त हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

(अनुदान संख्या ३६–सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं।)

(लेखा शीर्षक: ५०–सार्वजनिक निर्माण-कार्य और ५२–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत)

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री शराफत हुसैन रिजवी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––शिकायतें करना और सुझाव देना।
२	श्री छेदालाल चौधरी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों में बर्ती जाने वाली धांधली तथा खीरी जिले में उपरोक्त सार्वजनिक निर्माण कार्यों में उदासीनता की नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
३	श्री मैनेजरसिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।
४	श्री राघवेन्द्रप्रताप-सिंह, श्री भानुप्रतापसिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेमसिंह, श्री मुन्नूसिंह, श्री विजयसिंह, श्री बलबीरसिंह, श्री नवरंगसिंह तथा श्री चैतन्यराजसिंह।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने के उद्देश्य––सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
५	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कंकड़ की सड़कों की मांग करना।
६	श्री होरीलाल यादव	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य--फर्रुखाबाद में सकरावा, सौरिख, तिर्वा, सड़क के निर्माण में सरकार द्वारा दो तिहाई अनुदान न देने के संबंध में अन्तरिम जिला परिषद् के प्रस्ताव को अस्वीकृत करना।
७	श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य--सीमान्तक जिला चमोली और टिहरी-गढ़वाल की सीमा पर बहने वाली मन्दाकिनी नदी पर कई स्थानों में अभी तक बाबड़ के झूले लगे हैं, जिन पर हर वर्ष नर-बलियां चढ़ जाती हैं। इन स्थानों पर पक्के पुलों के निर्माण की मांग की अब तक उपेक्षा की गई है।

अनुदान संख्या ३७--संचार साधनों का सुधार

(लेखा शीर्षक: ५०--सार्वजनिक निर्माण-कार्य--केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता)

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री शराफत हुसैन रिजवी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--शिकायतें करना और सुझाव देना।
२	श्री तेज नारायण	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।
३	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभाग में पर्याप्त सुधार का सुझाव देना।
४	श्री राघवेन्द्रप्रताप-सिंह, श्री भानुप्रतापसिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेमसिंह, श्री विजयसिंह, श्री बलबीरसिंह, श्री मुन्नूसिंह, श्री नवरंगसिंह तथा श्री चैतन्यराजसिंह।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य--सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
५	श्री राजनाथ	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—गाजीपुर जनपद में सैदपुर तहसील के अन्तर्गत परगना शादियाबाद में संचार साधन नाम-मात्र को नहीं है। इसी पर शिकायती चर्चा करना।

अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्य-अधिष्ठान

(लेखा शीर्षक : ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्य और १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत)

क्र० सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय केंद्रीयकरण के विघटन की मांग करना।
२	श्री शराफत हुसैन रिजवी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—शिकायतें करना और सुझाव देना।
३	श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—गढ़वाल में सार्वजनिक निर्माण में यथार्थ कार्य नहीं हो रहा है।
४	श्री राघवेन्द्रप्रताप-सिंह, श्री भानुप्रताप सिंह श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेमसिंह, श्री मुन्नूसिंह, श्री विजयसिंह, श्री बलवीरसिंह, श्री नवरंगसिंह तथा श्री चैतन्यराज सिंह।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

[अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत
(लेखा शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत)

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री जे० पी० मिश्र	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक पया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति पर आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
२	श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री भानुप्रतापसिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेमसिंह, श्री मुन्नूसिंह, श्री नवरंगसिंह, श्री विजयसिंह, श्री बलवीरसिंह तथा श्री चिरंजीलाल ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ पये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
३	श्री शिवदानसिंह	मद (ख) मूल निर्माण कार्य संचार साधन के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—हाथरस, खैर और बेसवां गोरई की अधूरी सड़कों को पूरा किया जाने का सुझाव देना ।]

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—मान्यवर, मैं इस अनुदान का समर्थन करती हूं । मैं बहुत देर से अपने विरोधी भाई के भाषण को सुन रही थी और मैंने बहुत चेष्टा की कि तीन चार प्वाइन्ट ऐसे निकले जिन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और उत्तर दिया जाय । काफी देर चेष्टा करने के बाद मुझे दो ऐसे मसाले मिले । मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी क्योंकि मैं इस हाउस की नई सदस्या हूं और वह पहले के हैं....

कुछ सदस्य—वह भी नये हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—खैर, मुझे उनका पहला भाषण सुनकर ऐसा ही लगा । मुझे खुशी है वह मेरे कोलीग हैं ।

यह अनुदान एक बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है । इसमें ज्यादा हंसी, मजाक या मखौल का मौका नहीं होता । यह एक ऐसा अनुदान है जो कि सिर्फ पी० डब्ल्यु० डी० से ही संबंधित नहीं है परन्तु अपनी सरकार के जितने अंग हैं जैसे शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य आदि, किसी न किसी प्रकार उनसे घनिष्ट सम्बन्ध रखता है । यह तो एक एक्जीक्यूटिव विंग है । जो अधिकार और महकमों के पास हुए हैं उनको कार्यान्वित करना पी० डब्ल्यू० डी० का काम होता है । परन्तु इसका रवैया इतना खराब है कि इसको तुरन्त नेस्तनाबूद कर दिया जाय ऐसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा । मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगी, जैसा कि अभी गरीब भाइयों के नाम पर उन्होंने विनम्र निवेदन किया है वे उन्हीं गरीब भाइयों का ध्यान रखते हुए इस धूप में जो काम वे करते हैं उनका ध्यान रखते हुए क्या वह इस बात पर विचार करेंगे कि अगर यह महकमा खत्म हो जाता है तो हजारों की तादाद में जो लेबरर काम कर रहे हैं उनका क्या फ्यूचर होगा, अगर यह महकदा बन्द हो जाता है तो क्या बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जायगी, अगर यह महकमा बन्द हो जाता है तो हमारी जो पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं उनका क्या

[ ] कटौती के प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार उपस्थित किये हुये माने गये ।

हर्ष होगा ? मैं तो सोचती हूं कि अगर वह ब्रेक लगेगा तो इतने जोर का इम्पेक्ट होगा जिसमें हजारों आदमी दब जायंगे और बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने आयेगा। तो मैं यह निवेदन करूंगी कि इसको खत्म करने के पहले हम सब लोग एक मन से शान्तिपूर्वक विचार करें कि यह महकमा जो इतने महत्व का है उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। जो खामियां और कमियां हम महसूस करते हैं उनको दूर करें। इसमें दो राय नहीं हैं कि बहुत कमियां हैं।

जैसा कि आज कल का जमाना है इसमें यातायात का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और पी० डब्ल्यु० डी० का यातायात से एक घनिष्ट सम्बन्ध है। अभी एयर वेज इतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं। जहां तक रेलों का सम्बन्ध है हमारे यहां कोल की शार्टेज है, वैगन्स की शार्टेज है। जहां तक दरियाओं का सम्बन्ध है मेरे खयाल से एक जमाना वह भी आयेगा जैसे कि जर्मनी में राइन नदी है जिससे कि यातायात की बड़ी सुविधा होती है। हमारे देश को भी इस तरह की तैयारी करनी होगी। परन्तु वर्तमान स्थिति पर नजर डाली जाय तो सड़कों के अलावा कोई दूसरी सुविधा हमारे सामने नहीं है। तो इस सम्बन्ध में सारा महत्व सड़कों का ही है। पिछले दस वर्षों में हमने देखा कि १० हजार वर्ग मील सड़कें मेटल की बनी हैं। दिक्कत यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाई गयी तो प्रादेशिक सरकार ने ६० करोड़ का एस्टिमेट रखा। प्लानिंग कमीशन ने उसे घटा कर ३७ करोड़ कर दिया और केन्द्रीय सरकार के पास पहुंचा तो १८ करोड़ की सीलिंग फिक्स हुई और ७ करोड़ नई सड़कों तथा पुलों के लिये और ११ करोड़ चालू योजनाओं के लिये। आप बतलाइये जब हर एक आदमी चाहता है कि उसके कस्बे में, उसके गांव में, उसके शहर में उसके लिये जगह-जगह जो पुरानी सड़कें हैं उनके स्थान पर नई और अच्छी सड़कें बनाई जायं तो जाहिर है कि हमारे पास प्रायरिटी के अलावा क्या आधार है। जैसा कहा गया स्टार एंड ग्रिड फारमूला के अनुसार जहां सड़कें मौजूद नहीं हैं वहां सड़कों को लेना है। यह सही है कि केटेगरीज के आधार पर लिया जाय ए० बी० सी०। पहले ए पर ध्यान देंगे, मगर ज्यादा धन उपलब्ध होगा, तो बी पर आयेंगे, फिर सी पर आयेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आलोचना करने के पहले वास्तविक स्थिति पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिये।

सड़कों की कमियों के अलावा दूसरी खामी जिसका जिक्र किया गया इस विभाग के सम्बन्ध में वह करप्शन है। मैं भी समझती हूं कि एक आम चर्चा है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार इस विभाग में है। पिछली दफा उस साल इसी मौके पर माननीय मंत्री ने कहा था कि आप तरीका बतलाइये। अगर अपना बस चले तो सरकार खुद इसका इन्तजाम करे पर अभी इसकी क्षमता सरकार में नहीं है। दूसरा उपाय हमारे पास क्या है ? कोआपरेटिव के जरिये हो तो कोआपरेटिव्स के लिये टेक्निकल नो हाऊ की आवश्यकता पड़ती है जिसकी कमी है। रुपये की आवश्यकता पड़ती है यह भी अपने पास नहीं है। कोआपरेटिव्स से जो काम हुआ है वह थोड़ा कम में हुआ है। उस के संबंध में मंत्री महोदय ने पिछले साल सभी भाइयों को आमंत्रित किया था कि वह कोआपरेटिव समितियां बनायें, क्योंकि यह विभाग का कार्य नहीं कि सरकार कोआपरेटिव्स की स्थापना करे। विरोधी पक्ष के लोग या इस पक्ष के लोग ऐसी कोआपरेटिव्स तैयार करें जो स्वयं इस उत्तरदायित्व को लेने में अपना योग दें। मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद हमारे भाइयों ने कितनी मदद दी है। तो जब आप जानते हैं कि ठेकेदारी की प्रथा खराब है, उसके कई एक कारण हैं। एक तो उसको काम में उतनी दिलचस्पी नहीं होती जितनी कि सरकार ले सकती है। इसके अलावा उसमें रिश्वत का मामला भी आ जाता है। फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि जब कोई स्पेसिफिक केसेज हमारे सामने आयें तो तुरन्त सरकार के पास भेजना हमारा फर्ज ही नहीं बल्कि हमारा धर्म है। अगर हम उसको इस्टेब्लिश्ड फैक्ट मान कर समाज के अंग में ग्रहण कर लेते हैं तो उस के लिये हम लोग भी पाप के भागी हैं। मैं चाहूंगी कि एक हाई पावर कमीशन या कोई ऐसी कमेटी बनायी जाय जो विचार करे कि कैसे भ्रष्टाचार को हमारे बीच से हटाया जाय। अगर

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

भाई उग्रसेन जी आज्ञा दें तो मैं दो शब्द अंग्रेजी के पढ़ कर सुनाना चाहती हूं । सन् १९५८ में एक एकोनामी कमेटी बनी फार चेकिंग करप्शन । उसकी रिपोर्ट है--

"It, however, accepts the view that there should be greater emphasis on the desirability of exercising more rigid control in regard to this matter and more effective steps should be taken for the prevention of corruption in the P.W.D."

इसका मतलब यह है कि करप्शन है और उसको दूर करने के लिये हम लोगों को सुझाव करना है । और उसके लिये मैं यह कहूंगी, जैसा कि मैंने पहले भी एतराज किया था कि यह 'पिछड़ा हुआ' शब्द जो हम लोगों का प्रदेश आज माना जाता है यह हमारे स्वाभिमान के विरुद्ध है । इसी तरह इस करप्शन के खिलाफ हमको एक संघर्ष करना है और मेरा विश्वास है कि इस इंजीनियरिंग विभाग में हम लोगों के पास ऐसे लोग हैं जिनको देश के प्रति प्रेम है और वे सहयोग देंगे, मुमकिन है कि वे प्रयत्न कर भी रहे हों लेकिन अकेले होने के कारण हम लोगों के सहयोग की उनको आवश्यकता है । इसके लिये हम लोगों को पूरा प्रयत्न करना चाहिये और मुझसे जो कुछ होगा वह मैं करने के लिये तैयार हूं ।

तीसरी चीज यह है कि इस डिपार्टमेंट में जितना पैसा दिया जाता था उसमें से कुछ हिस्सा अमूमन लैप्स हो जाया करता था, यह एक बड़ी आम शिकायत इसके बारे में थी । मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि पिछली दो योजनाओं में सड़कों के लिये जो धन स्वीकृत हुआ था उसका ९५ फीसदी तो इस्तेमाल हो गया पर भवनों के लिये जितना रुपया दिया गया था उसमें से अवश्य कुछ लैप्स हुआ । उसमें दिक्कत यह है कि पहले तो डिजाइन बनाने में आपस में कुछ मतभेद हो जाता है । फिर जब किसी तरह से डिजाइन बन जाती है तो साइट का सलेक्शन होता है । फिर लैंड एक्वीजीशन की दिक्कत सामने आती है । उसके लिये एक सर्वे सर्किल बनाया गया जिसमें निर्णय किया गया कि बजट के अनुदान में लाने से पहले उस स्टीमेट का सर्वे कर लिया जायगा । उसके बाद इमारतों की डिजाइन के सम्बन्ध में भी इमारत का स्टैन्ड-डाईजेशन हो गया है जिसके आधार पर बहुत सी दिक्कतें दूर हो गयी हैं । इसके अलावा एक और आदेश जारी किया गया था कि साइट के सेलेक्शन में ज्यादा देर न होने पाये इसलिये विभाग अपनी जगह का पहले से ही प्रबन्ध कर लें । इस तरह से आशा की जाती थी कि इन तीनों बातों के आधार पर ८० , ९० फीसदी दिक्कत दूर हो जायगी । मैं आपकी आज्ञा से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इस पर वे थोड़ा-सा प्रकाश और डालें और बतलाने की कृपा करें कि इन चीजों के आधार पर कितना सुधार हुआ है और जनता को कितनी सुविधा उपलब्ध हुई है ।

एक बात टेम्पोरेरी और परमानेन्ट स्टाफ के बारे में कही गयी । यह सत्य है कि इस विभाग में ६० फीसदी कर्मचारी टेम्पोरेरी हैं और ४० फीसदी परमानेन्ट हैं, यह बड़ी शिकायत है । परन्तु जैसा कि सुनने में आता है, मैं निश्चित तौर से तो नहीं कह सकती पर रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि हमेशा इंजीनियरिंग विभाग में दुनियां के और मुल्कों में भी यही देखा जाता है कि जब बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लागू होते हैं तो टेम्पोरेरी लोग रख लिये जाते हैं और जब वह काम खत्म होता है तो धीरे-धीरे परमानेन्ट काडर बढ़ाया जाता है । फिर भी मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि परमानेन्ट काडर को बढ़ाने की चेष्टा करें । किसी भाई ने जिक्र किया था कि हम लोगों के यहां के रेट्स बहुत ज्यादा हैं । इस संबंध में मैं यह कहना चाहती हूं कि आप लोगों को शायद याद होगा कि माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उसने हर जगह से रेट्स मंगाये थे और उनको देखकर यह निर्णय हुआ था कि उत्तर प्रदेश के रेट्स ज्यादा नहीं है बल्कि इकोनोमीकल हैं । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारे यहां के रेट्स ज्यादा है । यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से एक छोटी-सी बात गांवों के संबंध कहना चाहती हूं । हम लोग जब गांवों में जाते हैं और वहां

के लोगों के दुखों को देखते हैं तो हमारे मन में यह होता है कि किसी तरह के क्रान्तिकारी कदम बढ़ा कर इन गरीबों के दुखों को दूर कर दें। कम से कम इतना तो कर दें हर एक गांव को कच्ची पक्की किसी भी तरह की सड़क द्वारा कनेक्ट कर दें जिससे उन लोगों को भी शहरों की फैसिलिटीज मिल सकें। लेकिन दिक्कत यह है कि एक औसत सड़क बनाने में कम से कम ६०–७० हजार की लागत लग जाती है और हमारी सरकार के हाथ बंधे हुये हैं। किस तरह से वह कर सकती हैं क्योंकि नई सड़कों को बनाने के लिये उसके पास केवल ७ करोड़ रुपया ही है। हर साल यह विभाग १०० मील लम्बी सड़क लेती है और १०० मील की सड़क जो श्रमदान द्वारा बनाई जाती है उसको ठीक करते हैं जिससे वह अच्छी हालत में रहे। इसलिये मैं अन्त में आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि जो भी कुछ रुपया इस अनुदान में रखा गया है उसको पास करें और पास करने के बाद एक कमेटी बनाकर जो कुछ भी इस विभाग में त्रुटियां या कमियां हैं उनको सब मिल कर, एक होकर दूर करने का प्रयास करें।

***श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं आपने आज मुझे सदन में इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। आज एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि इस विकास के युग में हर देश चारों तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमारा देश भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद आगे की ओर बढ़ रहा है लेकिन इतना होते हुये भी सरकारी रिपोर्ट है कि हमारा प्रान्त अन्य दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा बहुत पीछे है और वह जब कि हर एक प्रान्त आज आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ हैं और उनके अनुसार हमारे यहां का अनुदान कम नहीं है, यहां पर सरकारी साधन कम नहीं है, यहां पर भी वही विभाग है, वही सरकारी कर्मचारी और इसके साथ-साथ सारी सुविधायें भी प्राप्त हैं लेकिन इस पर भी हमारे प्रान्त के यातायात के साधनों में बहुत कमी है, सरकारी बिल्डिंग्स और पुल पुलियों की बहुत कमी है। जिस मात्रा में हमारे प्रान्त में यह बने हैं उसका एक नक्शा दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में मैं रखता, परन्तु इतना समय नहीं है। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को तथा माननीय सदस्यों को तराई क्षेत्र के इलाके में एक नक्शे द्वारा ले जाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इधर भी एक दृष्टि डालने की कृपा करें।

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वह नैपाल से मिला हुआ है जिसके लिये चारों तरफ से एक शोर मचा हुआ है। कहीं विस्फोट हो रहा है, कहीं आने जाने की सुविधा नहीं है तो हमारे लिये बड़ी भारी अड़चन पड़ रही है। नैपाल और हिन्दुस्तान का घनिष्ट लगाव है। हमारे यहां गोंडा में राप्ती नदी पर एक पुल बन रहा है। बड़ी कोशिश के बाद यह अवसर मिला है और वहां से जो एक सड़क जाती है तुलसीपुर होती हुई जरवा कोलबासा को, जहां से नैपाल जाने का रास्ता है, इस सड़क को देखने की जरूरत है। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव के दौरान में उधर गये थे लेकिन सड़कों की हालत खराब होने के कारण वहां के नेता गणों तथा कर्मचारियों ने उनको उस रास्ते से ले जाने के लिये वंचित रखा कि अगर देख लेंगे तो हमारा पत्ता गोल हो जायगा। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान पहाड़ों और तराई इलाके की तरफ ले जाना चाहता हूं। जो तुलसीपुर से चौधरी डीह को रास्ता गया है, बैल-गाड़ी जाने का भी कोई साधन नहीं है, २२,२२ स्थानों पर पुलिया बनने की जरूरत है। सड़कों की हालत यह है कि बरसात के दिनों में लंगोटी पहन कर नमक मिर्चा लाने के लिए शहरों को आना पड़ता है। मैं आपके सामने वहां के विकास कार्यों का नक्शा रखना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि आज एक स्थान दूसरे स्थान से सड़कों द्वारा मिलाया जा रहा है। वहां रियासत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुखदेवप्रसाद]

के जमाने में एक सड़क साइकिल और मोटर के लिए अलग थी और पैदल चलने के लिए अलग थी लेकिन इस समय आप देखें तो वहां क्या हालत है कि पैदल चलना भी दुश्वार है। चौधरी डीह से मथुरा को सड़क गयी है। उस पर कहीं पुलिया नहीं है। शिवपुरा ब्लाक है, कोंड़रीघाट को जो सड़क आती है उस पर पुलियों की बहुत कमी है। जो पुलियां पहले थीं उनको तोड़ दिया गया है। भगवान जाने क्यों तोड़ दिया गया है। वह वैसे की वैसी ही पड़ी हैं। एक हाथी के बराबर गहरा पानी भरा रहता है। सोच सकते हैं कि उस इलाके के लोग अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए कैसे आते जाते हैं। २२ मील तुलसीपुर पड़ता है। १६ मील महाराजगंज पड़ता है ३० मील बलरामपुर पड़ता है इतने बीच में कोई आने जाने का साधन नहीं है। मंत्री महोदय या किसी अधिकारी ने उस क्षेत्र की तरफ जाने की कोशिश नहीं की है, कि वहां जाकर देखें कि वहां के लोगों की हालत क्या है ?

वहां पर एक बन्धा बन रहा है चेतिया का। उसके बारे में कुछ प्रार्थना-पत्र भी दिये गये, जिला अफसरों से मिला, मगर बंधे का कार्य चल रहा है। ठीक है। लेकिन जब कि एक जगह पड़ी है, उसका सर्वे भी हुआ है, जहां चेतिया नाम का बन्धा है, लेकिन जंगल के किनारे है इसलिए वहां पर न बनाया जाकर गांव में आकर बनाया जा रहा है जहां पर हजारों लोग उजड़ रहे हैं। मैं चीफ इंजीनियर से भी मिला, जिले के अफसरों से मिला। मेरे पास सूचना गयी कि यह केवल इस कारण से हुआ कि वहां पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। वहां जंगल के पेड़ कट रहे हैं इसलिए कम खर्च करने के लिए गांव में आकर बन्धा बना रहे हैं। उनके रहने के लिए और घर बनाने के लिए हमने कुछ जमीन की मांग की तो यह कहा गया कि उसकी योजना बनाई जा रही है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बरसात आ रही है। उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई उद्योग भी नहीं है जिसके द्वारा अपना पेट पाल सकें। बहुत छोटे वर्ग के लोग हैं। तमाम जमीन जंगल के किनारे पड़ी हुई है। प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं। लोग घूस ले कर खा रहे हैं, कि जमीन दिलवा देंगे घर बनाने के लिए और खेती के लिए लेकिन एक बिस्वा जमीन नहीं मिली है। जहां पर हरिजन बस्ती बनी है वहां पर बाल है, कुछ पैदा नहीं होता है। अगर उनकी तरक्की के लिए वही जमीन बालू वाली है जिसमें कुछ पैदा नहीं होता, तो मैं तो समझता हूं कि इससे अच्छा यह होगा कि उनको आप कोई तरक्की इस तरह से न दें।

अब मैं उस बंधे के बारे में कहना चाहता हूं। आज बरसात आ गई है। उनके पास से जमीन चली गई है, घर नहीं है। तो अब-कब सरकार उसके बारे में सोचेगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस बंधे के बनाने में जितनी तेजी आप कर रहे हैं उतनी तेजी से बरसात के पहले वह बन नहीं पायेगा। इसके अलावा उन्हें जमीन और घर बनाने के संबंध में और जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भी पूर्ति के लिए जो कुछ और जितना कुछ हो सके वह आप कर दें क्योंकि हरिजनों के संबंध में चारों तरफ यह ढिंढोरा तो बहुत पीटा जाता है कि उनको बहुत अनुदान सरकार दे रही है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, यह वही जानते हैं।

इसके साथ-साथ श्रीमन्, मैं एक बहुत बड़े निर्माण कार्य के बंधे के बारे में कहना चाहता हूं जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। वह गिरगिट ही का बंधा है। मैंने उसके बारे में प्रश्न भी पूछा था लेकिन वह मेरे पास अस्पष्ट लिख कर वापस आ गया है। मैं नहीं समझता कि उसमें अस्पष्ट क्या बात थी। मैं दो मिनट और निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मैं नया सदस्य हूं। थोड़ा-सा समय मुझे और मिलना चाहिए। गिरगिट ही बांध के बारे में मैं कह रहा था। जिस समय यह बांध बन रहा था, करोड़ों रुपया उस पर खर्च हुआ और मैंने तो देखा कि मशीनरी के साथ-साथ बड़ी-बड़ी जगहों से न जाने कितने आदमी तुलसीपुर में आ गये थे जिनको देखने के लिए लोग जाते थे। लेकिन हालत यह है कि हर साल वह बंधा टूटता है। करोड़ों रुपया उसमें लगा, हजारों लोग बेघरबार हुए, खेत गये, सारी बातें हुईं, लेकिन श्रीमन्, इसके बाद जब वह बन कर तैयार हुआ तो हर साल टूटता है और हर बार लाखों रुपया उस पर खर्च होता है। मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि वह कब मजबूत होगा ? जिसकी शुरूआत

ही खराब हो, बालू की दीवार जिसकी हो, वह कभी मजबूत हो सकेगा यह सम्भव नहीं मालूम होता। उस बंधे को बनाने में जिन कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है जिन्होंने अपना खून पसीना एक किया है, उनके प्रति क्या ऐक्शन माननीय मंत्री जी ने लिया ? उनके ऊपर ऐक्शन लिया जावे क्योंकि इसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और यह जनता का रुपया है। तराई क्षेत्र का यह बहुत बड़ा कार्य है जिसको यह कह कर हमको टाल दिया जाता है कि इतना बड़ा कार्य तुम्हारे यहां हुआ है।

इसके अलावा खैरवान बांध, टंगनावर बांध और बनघोघवां बांध, न जाने कितने बांधों की वहां भरमार है जिनसे कोई लाभ वहां की जनता को नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह बांध नहीं थे तब जनता को बहुत लाभ होता था। जब से यह बांध हो गये हैं तब से उस क्षेत्र के इस विभाग के कर्मचारी कितना बड़ा अत्याचार वहां की जनता के साथ कर रहे हैं, कि जिसको कहा नहीं जा सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक मोहमडन दर्जी था उदईपुर का। उस के पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है, न बैलगाड़ी है। लेकिन उससे इस विभाग के एक आदमी ने अपने कपड़े सिलवाये और उसने जब सिलाई मांगी तो कहा, सिलाई ? उसने कहा हां, मैंने मेहनत की है, मेरे सिलाई के पैसे चाहिए। तो उससे कहा, अच्छी बात है मैं तुम्हें देख लूंगा। उसके बाद उस पर यह लांछन लगाया गया और कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है कि वह आदमी जो है वह बैलगाड़ी लिये हुए नहर की रोड पर जा रहा था जबकि उसके पास कोई बैलगाड़ी नहीं है और वह केवल दर्जीगीरी करता है और उससे अपना पेट पालता है। यही नहीं, जो जमीन नहर में और बन्धों में निकल गई है उसका मुआवजा भी उनको नहीं दिया गया है।

जो लोग सिंचाई अपने खेतों में करते हैं उनसे तो उसका पैसा वसूल होता ही है, जो नहीं करते, उनसे भी कहा जाता है कि तुम्हारे खेत में भी पानी गया है, तुमसे भी वसूली की जायगी। श्याम-लाल पतरौल एक वहां है, उनके बारे में बार-बार शिकायत जनता की आयी कि इनको यहां से ट्रांसफर कर दिया जाय लेकिन कोई ध्यान उस पर नहीं दिया गया। उस क्षेत्र में कोई विकास कार्य आज तक नहीं किया गया है। आठ साल से ऊपर हो गया कोई ब्लाक वहां नहीं बन सका है। कोई सहकारी भट्ठा नहीं लग सका है। तीस तीस मील से जनता मकान बनाने के लिए सामान नहीं ला पा रही है। अन्धाधुन्ध वहां मची हुई है। मैं तो कहता हूं कि उस क्षेत्र से भी किसी मंत्री को एक बार चुनाव लड़ा दिया जाय तो कम से कम उधर ध्यान तो चला जाय। मैं तो चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में किसी तरह से काम होना चाहिये। मैंने मुख्य मंत्री जी के बारे में सुना है कि उनके क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। मैं चाहता हूं उसी तरह से हमारे यहां भी काम होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष––आपका समय समाप्त हो गया।

(कुछ ठहर कर)

एक बात मैं निवेदन कर दूं। आज बजट संबंधित अन्तिम दिवस बहस का है और बहुत से माननीय सदस्य मेरे पास आये हैं कि जिनकी अभिलाषा यह है कि उनको एक मर्तबा तो बजट के सिलसिले में बोलने का अवसर मिले। इसको देखते हुये मैंने यह तय किया है––करीब-करीब ४० नाम हैं और २५० मिनट हमारे पास हैं––कि ५, ५ मिनट प्रत्येक सदस्य बोलेगा। मैं चाहता हूं कि महिलाओं को बोलने के लिये प्राथमिकता दी जाय और वह भी ५ मिनट बोलेंगी।

श्री रामायण (जिला देवरिया)––जो सदस्य अभी तक नहीं बोले हैं उनको पहले मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––जो रामायणराय जी कह रहे हैं उसको मैं मानता हूं कि जो अभी तक नहीं बोले हैं उनको बोलने का अवसर पहले दिया जाय।

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को मुबारकबाद देती हूं कि P.W.D. ने प्रान्त में शानदार तामीरी काम किये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आजादी के बाद सूबे की सरकार ने सड़कों के मामले में काफी तरक्की की है लेकिन हमारा हिन्दुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और उस मुल्क में सनाती, मआशी, आर्थिक तथा सामाजिक तरक्की के लिये यह जरूरी था कि मुल्क के अन्दर सड़कों का जाल बिछा होता लेकिन बदकिस्मती से विदेशी सरकार ने उस तरफ कभी अपनी तवज्जह नहीं की। मुल्क की तामीर का काम उन्होंने अपने मकसद को पूरा करने के लिये किया और सड़कें और पुल भी अपनी जरूरत के तहत तामीर कराये तब से आम जनता की भलाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आजादी के बाद कम्युनिकेशन बढ़ाने के तहत सन् ५१ में नागपुर प्लान में काफी सड़कों की तामीर का काम किया गया। उसके बाद पहले और दूसरे पंचसाला मनसूबे के तहत सड़कों के पुल बनाने का भी बहुत काम किया गया है। उत्तर प्रदेश का सूबा एक बड़ा सूबा है। उसमें आबादी रकबे के लिहाज से यह जरूरी है कि आमदरफ्त का जरिया काफी हो।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

चूंकि हमारे सूबे की सरहद ऐसे मुल्कों से मिलती है जिनसे बदकिस्मती से हमारे ताल्लुक उतने खुशगवार नहीं हैं जितने होने चाहिये इसलिये इन हालात को देखते हुये आमदरफ्त की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि सरकार ने इस तरफ काफी ध्यान दिया है और तीसरी पंचसाला मनसूबे के तहत सरकार ने सड़कों और पुलों की तामीर के लिये १८ करोड़ रुपया इसमें रखा है। इसमें ११ करोड़ पया, वह भी स्कीमों का शामिल है जो कि दूसरे पंचसाला मनसूबे के तहत पूरा नहीं हो सका है।

जिस तौर पर सूबे के दीगर अजला की तरफ तवज्जह की है उस तौर पर रामपुर की तरफ तवज्जह नहीं की गई है। रामपुर के उस इलाके की तरफ तवज्जह करना जरूरी है जो कि तरक्की याफ्ता नहीं है। वहां पर रामपुर–बिलासपुर सड़क के जरिये से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को मिला दिया गया है। उस तरफ रुद्रपुर का इलाका भी पड़ता है जहाँ पर तरक्की के बहुत काम हुये हैं, जहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई है। उस इलाके में काफी प्लानिंग के काम हो रहे हैं। इस इलाके में आम्दोरफ्त और आबादी रोजमर्रा बढ़ रही है इसलिये इस सड़क पर ट्रैफिक काफी हो गया है लेकिन सड़क चूंकि बहुत तंग है और इस पर खतरनाक किस्म के मोड़ हैं इसलिये आये दिन उस सड़क पर हादसे होते रहते हैं। जान और माल का बहुत नुकसान होता रहता है। चन्द रोज के बाद किसी न किसी हादसे की इत्तला मिलती रहती है। इन हादसों की तरफ प्रदेशीय सरकार को ध्यान देना जरूरी है। अगरचे इस सड़क को दोनों तरफ से चौड़ा करने के लिये मिट्टी डाली गई लेकिन तब भी जब तक इस सड़क को मुनासिब तरीके से दुरुस्त न किया जायगा, मिट्टी की पटरी को मैटिल्ड नहीं किया जायगा उस वक्त तक हादसे रुक नहीं सकते। इस सड़क पर एक पुल भी निहायत खतरनाक हालत में है। इस सड़क पर एक पुल है बिलासपुर के पास जो निहायत पुरानी हालत में है और बरसात में इस पर से flood का पानी गुजर जाता है। और उससे लोगों को आने जाने में दिक्कत पेश आती है। अगर इस पुल के चारों तरफ बांध बना दिया जाय तो रामपुर की जनता उस के लिये बहुत शुक्रगुजार होगी।

इसके अलावा एक रामपुर-शाहाबाद रोड है जो रियासत के जमाने में तामीर हुई थी तीसरी पंचसाला योजना में इस पर दो पुल तामीर किये जा रहे हैं। बरेली और बदायूं के दरम्यान जो पुल तामीर किया जा रहा है वह एक ऐसे रास्ते पर है कि जो रेल लाइन के जरिये मिला हुआ है। यह ठीक है कि जो हो रहा है वह तरक्की के लिये हो रहा है और उसे होना चाहिये, लेकिन इतनी गुजारिश मैं जरूर करूंगी कि अगर रामपुर और शाहाबाद के पास रामगंगा पर एक पुल तामीर कर दिया जाय तो उस पुल की अहमियत इन दोनों पुलों से किसी कदर कम न होगी। मर्जर के वक्त १ करोड़ ६० लाख पये की Govt. securities रियासत से प्रदेश के खजाने को मुन्तकिल हुई थीं मैं समझती, हूं कि वह इस पुल के लिये काफी होगा। शाहाबाद और आमला रोड भी कच्ची है उसकी हालत खराब है। उसे पक्की बनवा दिया जाय तो बेहतर

होगा और आज कल इस सड़क की अहमियत इसलिये भी जाहिर है कि वह दो डिप्टी मिनिस्टरान को मिलती है। अगर शाहाबाद–आमला सड़क को पक्का न बनाया गया तो मेरे ख्याल से रामपुर की जनता यह समझने में हकबजानिब होगी कि उसकी आवाज नहीं सुनी जाती। मेरी आवाज के पीछे रामपुर की जनता की आवाज है। वह जनता उन डिप्टी मिनिस्टर साहब की तरफ भी देख रही है जो वहां से आये हैं और उसी हल्के से मुंतखिब हुये हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे मेरी इस आवाज के दर्द और वजन को महसूस करेंगे। चूंकि हाउस का वक्त कीमती है....

श्री उपाध्यक्ष––आपका समय समाप्त हुआ।

बेगम किश्वर आरा––थोड़ा-सा और बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष––दूसरों को भी बोलना है।

बेगम किश्वर आरा––बस मुझे दो मिनट और बोल लेने दीजिये। यह सड़क एक ऐसे किले से होकर गुजरती है कि जिसके पीछे एक जबरदस्त तारीख है, एक ऐसी तारीख जिसका रिश्ता महाभारत से है और अगर गजेटियर आफ इंडिया का बयान अपनी जगह पर सही है तो यह कच्ची सड़क उस किले से गुजरती है जिसमें रानी द्रौपदी का स्वयंबर हुआ था और यहां पर ही खड़े हो कर अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था। लेकिन क्या यह भी तारीख की बात है कि आज भी इस सड़क की वही हालत रहेगी जो कि महाभारत के जमाने में थी? क्या आज भी उस पर वही सवारियां चलेंगी जो कि महाभारत के जमाने में चलती थीं? रामपुर का भी इस सूबे की सरकार पर कुछ हक है और उसका वही हक है जो कम से कम दूसरे जिलों का है। उत्तर प्रदेश के सूबे में रामपुर की बड़ी अहमियत है। जैसे इंसान के जिस्म और उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों को, कौन अक्लमंद आदमी यह गवारा करेगा कि वह अपने एक हाथ को सुखा दे और दूसरे को मोटा कर दे, एक आंख को रोशन कर दे और दूसरे को तारीक, दिमाग को तेज और तर कर दे और जिस्म को लागर और नहीफ। मुझे पूरा यकीन है कि यह सरकार कभी नहीं चाहेगी कि रामपुर का जिला पसमांदा और गैरतरक्कीयाफ्ता रहे क्योंकि अगर यह गैरतरक्कीयाफ्ता रहता है, या उसका कोई हिस्सा, तो यह उत्तर प्रदेश जैसे तरक्कीयाफ्ता सूबे के चेहरे पर एक बदनुमा दाग होगा। रामपुर के एवाम १२, १३ साल से इस सरकार की तरफ आंख लगाये बैठे हैं।

मैं मानती हूं कि हुकूमत की जिम्मेदारियां बहुत हैं और मसरूफियत बेइन्तहा हैं, लेकिन अब मैं बार-बार सरकार की तवज्जह दिला रही हूं। कहीं ऐसा न हो कि वह जिला जो सियासत, इल्म, तारीख और समाजी अहमियत में अपना एक खास मुकाम रखता था, मर्जर के बाद अपने बारे में मीर के इस शेर को दोहराये:

"फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं,
इस आशिकी में इज्जते सादात भी गयी।"

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)––आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में श्री कल्पनाथ जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा है, उसका मुझे समर्थन करना है। हमारे जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं वे अभी ३० तारीख को मथुरा गये थे, वहां उन्होंने जमुना के एक पुल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन करने हेतु जाने के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह काम बड़े अच्छे समय पर किया। लेकिन जो उन्होंने पुल के उद्घाटन के समय घोषणा की है कि उस पुल पर चलने वाले पैदल और साइकिल वालों को छोड़कर सब पर टैक्स लगेगा तो यह ऐसी चीज है कि जिस का मुझे विरोध करना है।

[श्री लखीसिंह]

उस पुराने पुल पर सैकड़ों आदमियों का खून हो गया, वहां सैकड़ों जानें गईं, बहुत से लोग मर गये और फिर अब उस नये पुल के बनने के बाद उस पर टैक्स लगे यह कहां तक उचित है। इसके कारण वहां पर त्राहि २ मच रही है। वह जिला एक तीर्थस्थान का जिला है। वहां टैक्स लगने से सारे देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा, सारे प्रांत पर पड़ेगा। इस कारण भी मुझे उस पर बोलना है। वैसे मैंने सन् १९५९ में सोशलिस्ट पार्टी के नेता डाक्टर राममनोहर लोहिया के साथ अगस्त के महीने में सारे प्रदेश का दौरा किया था। हम लोग रोडवेज की कार द्वारा गये थे। मैं उस समय इस प्रदेश की सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था। इस सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो कारगुजारी है, जो सड़कों की दशा है, जो सड़कों की बनावट है, वह मैंने अच्छी तरह से देखी। हम लोगों को उससे बड़ा क्षोभ हुआ।

यह बिलकुल ठीक है कि सड़कों की दशा दारुलसफा के आस पास बहुत अच्छी है। वह सड़कें इसलिये इतनी अच्छी बनाई जाती हैं कि जो कार में मंत्रीजी निकलें तो उनके पेट का पानी न हिले। मैंने कल दिल्ली में भी देखा। वहां नेहरू जी की कोठी के आस-पास ४–४ और ६–६ मील सड़क बहुत अच्छी और चौड़ी है और उसके दोनों ओर पेड़ लगे हुये हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। तो वहीं पर ऐसा क्यों है? देहातों में क्यों नहीं ऐसी सड़कें बनायी जा रही हैं?

मैंने सन् १९५९ में मुरादाबाद से लेकर बस्ती तक, गाजीपुर और मिर्जापुर तक दौरा किया था। सब जिलों को देखा था। सिवाय आम रोड के जो गांव के रास्ते हैं उनमें हमारी जो कार थी वह कई जगह फंसी थी और साथ ही साथ एक और नक्शा बताऊं आपको। उस मथुरा पुल पर तो मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से और जल्दी से उद्घाटन किया लेकिन राप्ती नदी का पुल बने हुये करीब एक महीना हो गया लेकिन मंत्री जी ने उसका उद्घाटन नहीं किया था। जनता बहुत परेशान थी। अगस्त का महीना था, इसलिये फिर मैंने ही उस पुल का उद्घाटन किया था। लोहिया साहब से उद्घाटन कराया गया। तो श्रीमन्, आप देखें कि हम लोगों ने मंत्री जी का काम बंटा लिया और उस पुल के उद्घाटन से जनता खुशी मनाने लगी। (लाल बत्ती होने पर) उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा है। श्रीमन्, लाल बत्ती बुझा दीजिये।

अब मैं मथुरा जिले की बात कहता हूं। मथुरा से सींख, मथुरा से सादाबाद, मथुरा से माट, अकबरपुर से अतरौली, मथुरा से अलीगढ़, इगलास होती हुई, आदि ऐसी सड़कें हैं कि अगर इन पर कोई बस जा रही हो और उसमें कोई गर्भवती स्त्री बैठी हो तो उसको तो अपनी जान बचाना ही मुश्किल हो जाय। इतनी खराब हालत है उन सड़कों की। फिर कैसे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने निर्माण किया, तीर मारा।

८ सड़कें ऐसी हैं जो जरूर बननी चाहियें। कोसी से शेरगढ़ १३ मील, जेंत से शेरगढ़ १४ मील, छाता से सहार १० मील, जेंत से सहार १२ मील, कोसी से हसनपुर १२ मील, कोसी से कामर ८ मील, छाता से बरसाना १० मील, चौमहा से सेई ७ मील, इन सड़कों का बनना निहायत जरूरी है। मैं कहता हूं कि आप अइयाशी की सड़कों को मत बनाइये, मगर जो जरूरी सड़कें हैं इनको आप जरूर बनवाइये। आप डामर को भी मत बनवाइये, आप कच्चे कंकड़ की ही बनवा दीजिये और उसको पुख्ता बनवा दीजिये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जरूरी सड़कों को नहीं बनवायेंगे, तो आप यह दावा नहीं कर सकते कि हमने निर्माण का कार्य किया। मेरे ही क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में कंकड़ की सड़कें जरूर बननी चाहियें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अगला चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हुआ।

*श्री रामलाल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ने उनको बोलने का अवसर दिया जो अभी तक नहीं बोले हैं। हमारा जैसा आदमी तो आपका आभारी होगा जो हमेशा पिछली सीट पर बैठा करते हैं। आज इस सदन में सार्वजनिक निर्माण विभाग को धनराशि देने के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है। मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान प्रदेश के उस पूर्वी अंचल की ओर दिलाना चाहूंगा जहां पर यू०पी० और बिहार की सड़कें मिलती हैं। आप को मालूम है कि हमारे प्रदेश में आजकल कोयले का अकाल-सा पड़ गया है। एक भी ऐसी सड़क नहीं है जो इन दोनों प्रदेशों को मिलाती हो। केवल दो तीन मील की सड़क इन दोनों प्रदेशों को मिलाने नहीं देती। मैं आप को बताऊं कि बिहार में काफी कोयला भरा पड़ा है। लेकिन चूंकि वहां से यहां तक कोई सड़क नहीं है इस कारण वहां से कोयला यहां नहीं आ पाता। देवरिया से बघौच घाट तक सड़क बनी है लेकिन बघौच घाट से कटया जो ४ मील का क्षेत्र है, वहां कोई पक्की सड़क नहीं है। हालांकि कटया से सोमपुर तक पक्की सड़क है। अगर वह ४ मील की पक्की सड़क और बना दी जाय तो बिहार और यू० पी० ही नहीं आसाम की सड़क से भी उसका सीधा संबंध हो जायगा और उससे काफी सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी। गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद आदि ऐसे जिले हैं जहां रेलवे वैगन न मिलने के कारण कोयला आसानी से नहीं पहुंच सकता। दूसरी बात जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा वह यह है कि जहां लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आप खर्च करने जा रहे हैं, आप यह अवश्य ध्यान रखें कि राज्य कर्मचारी उसे ठीक से खर्च कर रहे हैं या नहीं। आम शिकायत यह है कि इस विभाग में सीमेंट की जगह पर बालू मिला दी जाती है, ईंटें खराब डाली जाती हैं और निर्माण इतना खराब होता है कि इमारतें जल्दी विध्वंस हो जाती हैं। धनराशि का देना तो जरूरी है, क्योंकि बिना रुपये के काम नहीं चल सकता लेकिन यह देखा जाय कि वह ठीक से खर्च किया जाय।

मुझे ५ मिनट का समय दिया गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं और आप से आशा है कि बाद में भी अवसर देंगे। अब आप दूसरे भाई को अवसर दें।

*श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज बोलने का समय दिया। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम देश में और सूबों से सड़क के मामले में बहुत पिछड़े हुये हैं और मैं तो खास तौर से ऐसी कांस्टीट्युयेंसी से आया हूं जहां एक फुट भी पक्की सड़क नहीं है, जबकि मेरी कांस्टीट्युयेंसी नैपाल बार्डर की ४९ मील लम्बाई को टच करती है। मंत्री जी पारसाल भिनगा पधारे थे और उनके पधारने के सम्बन्ध में जो सड़क का इंतजाम किया गया और पानी वगैरह डाला गया तो ५–६ दिन तक जिस प्रकार की हालत सड़क की रही और जिस पर मुझे भी चलने का अवसर मिला, उसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और वह सुख मैं बहुत दिन तक याद रखूंगा जो ५–६ दिन हम लोगों को हुआ था। वह ऐसी कांस्टीट्युयेंसी है जो सरप्लस है। गल्ले में, लकड़ी में, हड्डी, चमड़ा, घी इन सब चीजों में सरप्लस है। मैन-पावर भी काफी है, लेबर की कोई प्राब्लम नहीं है और नैपाल के बोर्डर को भी टच करती है। अगर मंत्री महोदय वहां की जनता की सुविधा को भुला भी दें तो कम-से-कम डिफेंस प्वाइंट आफ व्यू से जरूरी है कि उसको बहराइच तक कांस्ट्रैक्ट कर दिया जाय। एक स्कीम है जिसमें भिनगा से बहराइच तक सड़क पी०डब्ल्यू०डी० बना रहा है, लेकिन ६ वर्ष में ६ मील बन सकी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुन्नूसिंह]

मैं थोड़ा और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर एक पुल का निर्माण हो रहा है राप्ती पर जो शायद इस वर्ष पूरा हो जायगा, लेकिन वह पुल ठेके पर दे दिया गया और बनने के साथ वह क्रैक हो गया। उसका इम्तहान वगैरह लिया गया और शायद फिट डेक्लेयर कर दिया गया। तीन महीने से काम हल्का हुआ है, मैं नहीं जानता क्या बात है। शायद ठेकेदार और इंजीनियर में खट पट है और ओवरसियर की गैर हाजिरी की वजह से विशेष तौर से विलम्ब है। वह सड़क आगे जाकर एक मील पर पानी के बहाव से कटती है, जिस पर पिछले साल एक बांध तक बन गया था, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस बांध में जो कुछ हुआ था वह मैं अगर कहूं तो शराफत से बहुत गिरी हुई बात होगी, इसलिये मैं उसका जिक्र ही नहीं करना चाहता हूं।

मेरी दरख्वास्त है मंत्री महोदय से आपके द्वारा कि वहां का तमाम कच्चा माल जो बेकार खराब होता है जो लाने और ले जाने में ज्यादा पैसा खर्च होने की वजह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उसको ध्यान में रखते हुये इतनी कृपा करें कि उसके लिये जरा जल्दी करा दें तो वहां की जनता को भी सुविधा होगी और सरकार को भी कच्चा माल प्राप्त होता रहेगा। अगर कुछ नहीं तो २०,००० टन कच्चा माल कागज के कारखाने का वहां से कलकत्ता जाता है जिसका सिर्फ कार्टेज उस सोहेलवा फारेस्ट से तुलसीपुर रोड तक ३ रुपया मन होता है। जिस रास्ते पर २० पहाड़ी पुल पड़ते हैं, उनके बनने का तो सवाल ही नहीं है। एक बात और है। उस बार्डर एरिया में हथियाकुन्ड, बनघोघवा जलसरोवर, तकिया जल-सरोवर, मोतीपुर, रामपुर हिंडोला, मच कहवा इन बांधों में से कुछ तो बन चुके हैं और कुछ का निर्माण कार्य जारी है। इन बांधों के बनने के बाद भी ऐसा लगता है कि यदि अच्छी सड़कों से इनको कनेक्ट न किया गया तो किसानों के सामने जो दिक्कतें आती रहती हैं उनमें कोई कमी नहीं होगी। जब वह बांध बन रहे थे तबका मैं एक किस्सा सदन के सामने रखना चाहता हूं। इत्तफाक से ऐसा हुआ कि एक दिन शाम को कुछ आदमी लकड़ी काट रहे थे, मुझे उनको देखने के लिये जाना पड़ा। रामपुर हिंडोला बांध बन रहा था। कुछ हल्की बारिश भी हो रही थी। एक आदमी यह कहता हुआ आया रऊफ साहब कहां हैं। मैंने पूछा क्या बात है। तो लोगों ने कहा कि ये रऊफ साहब एजेन्ट हैं, चार रुपये बोरी में सीमेन्ट बेचते हैं, हजार दो हजार बोरी की भी जरूरत हो तो वह मिल जायगी। तो आप गौर करें इतना नैतिक पतन है। अगर यही हाल जारी रहा तो इस देश का कैसे कल्याण होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं शिकायत नहीं करता। मुझे अफसोस है कि यहां ऐसी बातें होती हैं जिससे न सिर्फ हमारा सिर नीचा होता है बल्कि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वह जान पाने पर जब क्वैरी करने लगते हैं तो शर्म से हमारी गर्दन झुक जाती है। कारण यह है कि उस इलाके में कोई उच्च कर्मचारी जा नहीं सकता क्योंकि रास्ते का कोई साधन नहीं है, सड़कें बड़ी खराब हैं। राप्ती का वहां पर बहुत ही खराब रोल है, उससे बहुत नुकसान पहुंचता है। नदी का रास्ता बदलते रहने के कारण दो तीन मील तक बालू ही बालू हो जाती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से पीपे का पुल बनाया गया है किन्तु उससे कोई विशेष सुविधा नहीं होती। दिक्कत यह है कि दो मील इधर बालू और दो मील उधर बालू, ट्रक और मोटरें जा नहीं सकतीं, नतीजा यह होता है कि कोई पहुंच ही नहीं पाता। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार उस पिछड़े हुये इलाके की तरफ विशेष ध्यान दे। धन्यवाद।

*श्री गंगाधर (जिला चमोली)---उपाध्यक्ष महोदय, पी० डब्ल्यू० डी० और पहाड़ी के लोगों का बहुत बड़ा सम्बन्ध है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहाड़ के लोगों को, चाहे वे इधर के हों या उधर के, उनको बोलने का समय मिलना चाहिये ताकि वहां की दिक्कतें रखी जा सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—मौका मिलेगा ।

श्रीमती बृजरानी (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यबाद देती हूं। मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । पिछले १५ सालों में अगर देखा जाय और समझा जाय, तो कम काम नहीं हुये हैं । लेकिन चूंकि बहुत बड़ी तादाद में हमारी दिक्कतें थीं और काफी समय से समारा देश गुलाम रहा ऐसी हालत में १५ सालों में सारा देश हरा भरा हो जाय यह सम्भव नहीं है । आज हर जगह यातायात और निर्माण कार्यों की जरूरत है । यहां पर बोलने वाले भाइयों ने अपने अपने जिले की मांगें रखीं । मैं भी अपने जिले कानपुर और अपने क्षेत्र बिठूर की कुछ समस्यायें सदन के समक्ष रखना चाहती हूं और कुछ मांग रखना चाहती हूं । हमारे यहां बिलहौर मुरलीधर जी का क्षेत्र है । हमारे यहां बिलहौर-नानामऊ–रसूलाबाद सड़क का कार्य पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ लेकिन उसकी गति धीमी है। मैं प्रार्थना करूंगी कि तीसरी योजना में वह सड़क पूरी हो जाय । हमारे बिठूर क्षेत्र में एक सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है। कल्याणपुर और टीकरा के पास एक पांडव नदी पड़ती है जिसकी वजह से २० मील घूम कर आना पड़ता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उस पुल को बना नहीं सकता है अगर पी० डब्ल्यू० डी० उस पुल को बना दे तो ५ मील का फर्क पड़ जायगा । माननीय निर्माण मंत्रीजी इस पंचवर्षीय योजना में अगर इस पुल को बनवा देंगे तो उनका बड़ा उपकार होगा । जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिलों के लोग गरीब हैं उसी प्रकार से कानपुर में इस पांडव नदी के किनारे के लोग बहुत गरीब हैं ।

इसी प्रकार हमारे यहां एक बेला रोड है जो कानपुर को चौबेपुर से मिलती है । बीच में सोमन एक गांव पड़ता है जहां पर लोगों ने श्रमदान से सड़क को बनाया था । वहां पांडव नदी पर एक पुल बहुत पुराना बना हुआ है । वह बहुत खराब हो गया है । अंतरिम जिला परिषद् ने उसके बारे में प्रस्ताव पास करके भेजा था कि उस पुल की सरकार मरम्मत कर दे । अगर इस पुल की मरम्मत कर दी जायगी तो आने जाने वालों को सुविधा हो जायगी और मरम्मत में पैसा भी कम खर्च होगा । अभी तक उसके बारे में सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला ।

एक सड़क जो अरौल से मकनपुर जाती है, पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क है । मकनपुर में जानवारों का एक मेला लगता है जिसकी वजह से एक डेढ़ महीने तक वह सड़क बहुत ज्यादा चलती है, उसकी भी मरम्मत की बहुत आवश्यकता है । मैं आशा करती हूं कि निर्माण मंत्री जी उसको भी बनवाने की कृपा करेंगे ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कल्पनाथ सिंह जी की तरफ से, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं पी० डब्ल्यू० डी० के वर्क चार्ज कर्मचारियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । ११–१२ जुलाई, १९५७ में भी गुलजारीलाल नन्दा की अध्यक्षता में त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया था । निम्नतम वेतन के सिलसिले में उस सम्मेलन ने सर्वसम्मति से यह पास किया कि किसी भी विभाग के मजदूरों का निम्नतम वेतन १२५ रुपया होना चाहिये । लेकिन बड़े दुःख की बात है कि आज १९६२ में, जब कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है मजदूरों के निम्नतम वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई । आज वर्ग ४ के मजदूरों की तनख्वाह कहीं ३० रु० है, कहीं ४० रु० है और कहीं ३५ रु० ही है । इस असमानता को देखते हुए मैं समाजवाद का वादा करने वाली इस सरकार को क्या कहूं, जब इस किस्म की असमानता एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में दिखलायी देती है । उस रोज श्री कमलापति त्रिपाठी कह रहे थे कि दो आना समाजवाद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं ।

[श्री रघुवीर]

धिक्कार है ऐसे समाजवाद को कि अंग्रेजों के जमाने में मजदूरों को जितनी तनख्वाह मिलती थी आज १५ वर्ष के बाद समाजवाद के युग में भी उतनी ही तनख्वाह मिलती है ।

इसके अलावा वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों के बारे में दो चार शब्द मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये, दूसरी यह कि जो कई सालों से अस्थायी चल रहे हैं उनको स्थायी किया जाय । तीसरी बात यह है कि इन कर्मचारियों के लिये दवादारू का भी प्रबन्ध होना चाहिये ।

यदि ओवरसियर के पास घोड़ा है तो उसे साढ़े ३७ रुपये यात्रिक भत्ता दिया जाता है और मोटर साइकिल होने पर उसे २५ रुपये यात्रिक भत्ता दिया जाता है और उसी सड़क पर जो गरीब बेचारा मेट है जो १२–१२ मील साइकिल पर चलता है उसे एक पैसा भी यात्रिक भत्ता नहीं दिया जाता है । यह बड़े ही दुख की बात है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मेट को भी यात्रिक भत्ता देने की कृपा करें ।

तीसरी बात यह है कि आज इस विभाग में जिस किस्म का भ्रष्टाचार फला हुआ है उसे कहा नहीं जा सकता । इस विभाग के उच्च अधिकारियों का व्यवहार छोटे कर्मचारियों के साथ नादिरशाही का है । जिस तरह से तलाव व नदी की बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं उसी तरह से इस विभाग के उच्च अधिकारियों की नादिरशाही खुलेआम देखने में आती है । वे छोटे-छोटे कर्मचारियों से अपने बंगले पर प्राइवेट काम कराते हैं । सरकारी काम से उनको मुक्त करा देते हैं और वे बेचारे अस्थायी होने के कारण बंगले पर उनकी हुकूमत बजाते हैं । क्योंकि वे भी डरते हैं कि अगर कहीं हुकुम उदूली हो गयी तो जो ३० रुपये की सर्विस है वह भी खत्म हो जायगी । इसलिये इस विभाग के उच्च अधिकारियों की नादिरशाही हमेशा चलती रहती है और वे बराबर प्रयत्न करते रहते हैं कि ये कर्मचारी स्थायी न हों बल्कि अस्थायी ही रहें । वे सोचते हैं कि अगर ये स्थायी हो जायेंगे तो वे उस रूप में सरकारी नियमावली के अनुसार कार्य करना व रहना शुरू कर देंगे और फिर उनका काम नहीं कर पायेंगे । इसलिये वे इन मजदूरों के मनोबल को बिल्कुल कुचल कर रखना चाहते हैं ।

मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि यह सरकार इन सरकारी आफिसरों के हाथ में खेलती है । उसमें इतनी बुद्धि, और विवेक व ज्ञान नहीं है कि वह इनकी चीजों को पकड़े और पकड़ कर कह सके कि तुम यहां गलती कर रहे हो । यह सरकार उन आफिसरों के इशारे पर नाचती है फिर न मालूम कैसे यह अपने को समाजवादी सरकार होने का दावा करती है । मैं कहता हूं कि यह समाजवादी सरकार नहीं बल्कि पूंजीवादी सरकार है जो अपने को पूंजीवादी प्रणाली के अन्तर्गत चलाते हुये समाजवाद का नारा देती है । इससे मुझे बड़ा दुख है । उस रोज श्री कमलापति जी ने कहा था कि दो आना समाजवाद की तरफ सरकार का सुझाव है लेकिन जरा आप देखें कि इन कर्मचारियों की तनख्वाह क्या है जो आज सारे देश का निर्माण करने वाले हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जो सामने कर्मचारी बैठे हुये हैं ये नक्शे बनायेंगे या कंकड़ व पत्थर खोदने के लिये कहने पर वह काम भी करेंगे इस तरह से वे निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं । वे बंगले में बैठ कर नक्शे बना सकते हैं लेकिन निरीह गरीबों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

श्री मोहनसिंह (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस विभाग के संबंध में जो भ्रष्टाचार वगैरह की बातें चलीं उन के संबंध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वैसे तो कहने को बहुत कुछ था, ५ मिनट का समय है इसलिये इस अनुदान के विषय में केवल २–४ बातें ही मंत्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं ।

जब हमारे यहां अंग्रेजी राज्य था तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में काफी समय लगता था और रास्ते हमारी पहाड़ी प्रदेश में बहुत ऊबड़खाबड़ थे । लेकिन अपनी सरकार के आने के बाद जो सड़कों की सुविधायें हुई और जो पैदल मार्ग और मोटर मार्ग

बनाये गये हैं उस के लिये हम सरकार के बहुत आभारी हैं और मंत्री जी और विभाग के अधिकारियों के भी आभारी हैं जिन्होंने पर्वतीय इलाके की कठिनाइयों की तरफ ध्यान दिया और वहां के लोगों की तकलीफें रफा कीं। मुझे आशा है कि आगे भी वह इसी तरह जिन सड़कों और पुलों आदि की वहां जरूरत है उनकी तरफ वह ध्यान देंगे।

मेरा निर्वाचन क्षत्र पिथौरागढ़ और चमोली क २ बार्डर जिलों के बीच म पड़ता है। वहां पर एक रास्ता है बैजनाथ ग्वालदम, यह बैजनाथ ग्वालदम मार्ग बड़ी मुद्दत से कर्णप्रयाग तक पक्का नहीं बना है और मार्ग के पुलों की हालत खराब है और आगे का कर्णप्रयाग का रास्ता भी अभी ठीक नहीं बन सका है। बोर्डर जिला होने की वजह से यह एक अहम रास्ता है। इस पर जल्द से जल्द पुल बनने चाहिये। इसको पक्का और चौड़ा मार्ग बनाने की बड़ी जरूरत है।

इसके अलावा कपकोटसामा तजम रोड भी बोर्डर क्षत्र से संबंध रखती ह, म चाहता हूं कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाय और इसको शीघ्र पक्का करा दिया जाय। कपकोट की यह सड़क श्रमदान से बनी थी अल्मोड़ा जिले के करुड़ ब्लाक में जो श्रमदान द्वारा मार्ग उंगोली बनी थी वह वजूला जो कि अब वन विभाग के प्रबन्ध में है। इस बैजनाथ से आने वाली वजूला सलानी रोड पर, इस इलाके, में सीसा, मैगनेसाइट और सोप स्टोन की खानें हैं, इस को सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने हाथ में ले ले तो उस इलाके की जनता आप की बहुत आभारी होगी और साथ ही वहां पर जो खनिज पदार्थ दबे पड़े हैं जांच के लिये वहां पर ज्योलाजिस्ट के आने जाने में सुविधा होगी और राज्य के आय के साधन बढ़ेंगे।

इसके अलावा बाड़छीना गणई, गंगोली मोटर मार्ग का भी निर्माण करने की आवश्यकता है। इस मार्ग के निर्माण के लिये बहुत दिनों पहले चर्चा चली थी, विभाग ने शायद कुछ सर्वेक्षण भी किया था और पिथौरागढ़ जिले से भी अब कोशिश हुई है। मैं चाहता हूं कि इसको बाड़छीना से गणई, गंगोली (Gongoli) बेरीनाथ तक बनवा दिया जाय। इसके बनने से वहां के रहने वाले आप के बड़े आभारी होंगे।

इसके अलावा पिंडारी ग्लेशियर तक भी एक सड़क की बड़ी मांग है और वहां तक जाने वाले पर्यटकों, यात्रियों को बड़ी दिक्कत होती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोग जानते हैं कि उसके सर्वे की एक बार चर्चा चली थी, हमने श्रमदान द्वारा ४ फिट मार्ग गोड़ीगाड़ कर्मी तक निर्माण भी किया है। कपकोठ, गोरीगाड़, कर्मी पिन्डारी मार्ग बनने से बड़ा लाभ होगा, इसको विभाग जल्द से जल्द बना दे तो टुअरिज्म वहां पनपेगी और जनता का आर्थिक स्तर अच्छा हो जायगा और उन को आराम भी मिलेगा और साथ ही जिले व प्रान्त के लोगों को भी काफी लाभ होगा। अल्मोड़ा–बागेश्वर मोटर मार्ग के निकट सरयू नदी, स्थान बेडुलिया पर एक पुल की आवश्यकता है। पट्टी से बल्ला, पल्ला, कमस्यार, अठगांव, रीठागाड़ और खरई पट्टियां जहां मिलती हैं वहां सरयू में बेडुलिया पर एक पुल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बरसात में लोग आते जाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि अगर एक पुल इस स्थान पर बना दिया जाय तो अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग का अधिक सदुपयोग हो सकता है।

इसी तरह से पट्टी अठगांव म एक कुलूर नदी है वहां पर भी स्थान गणई के निकट पुल की आवश्यकता है। अगर उस पुल को भी बनवा दिया जाय तो लोगों को काफी सुविधा होगी और लोगों की जो जानें बरसात में जाती हैं वे न जायंगी।

टेहरी, और गढ़वाल, जो ननीताल और अल्मोड़ा से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। इसलिये वहां की जनता की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि उन जिलों में जहां जहां जरूरी सड़कें और पुल बनाने की आवश्यकता हो उनको बनवा दिया जाय। इन जिलों में अधिक हिस्सा बोर्डर एरिया का है।

[श्री मोहनसिंह]

गरुड़ म जो ब्लाक क क्वाटर बने है वह जगह गांव वालों की गोचर भूमि थी। उस समय विभाग ने आश्वासन दिया था कि इस गोचर भूमि में क्वार्टर बन जाने दें और पास में जो नदी है उस पर पुल बनवा देंगे जिससे वहां के लोग उस पार अपना गोचर भूमि इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन वह पुल अभी तक नहीं बना है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि सम्भव हो तो छानबीन करके उन गांव वालों की चरागाह की जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिये एक पुल का निर्माण गरुड़ गंगा पर करा देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, म आपका आभारी हूं जो आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया। मैं समझता हूं सार्वजनिक निर्माण विभाग देश की उन्नति के लिये बड़ा आवश्यक विभाग है। किसी भी प्रदेश की उन्नति के लिये यातायात के साधन अधिक होना आवश्यक है। जो अनुदान आज पेश है, मैं समझता हूं, उसमें यातायात की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये उतना नहीं दिया गया। आज प्रदेश में ऐसे जिले और क्षेत्र भी हैं जो अभी तक अविकसित हैं और आपकी वेलफेयर स्टेट की कल्पना का स्वप्न भी उनको देखने को नहीं प्राप्त हुआ है। जो तालिका हमको मिली है उसको मैंने देखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सड़कों के लिये जो रुपया रखा गया है वह बहुत कम है। यातायात पर ध्यान कम है। जब कि इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। प्रदेश का पूर्वी अंचल पहले से ही पिछड़ा रहा है मैं खास कर मंत्रीजी का ध्यान फैजाबाद जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। उस फैजाबाद जिले में टोंस नदी पर सरयू के पुल के अतिरिक्त ५० मील तक कोई दूसरा पुल नहीं है। जलालपुर बसखारी--टांडा रोड को मिलाने के लिये जलालपुर पर एक पुल बनाने की आवश्यकता है। यह तीनों कस्बें फैजाबाद के पूर्वी अंचल में हैं और पुल बना कर सड़क को मिला दिया जाय तो इससे फैजाबाद जिले के पूर्वी भाग को बहुत बड़ा साधन उपलब्ध होगा। माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष हम लोगों ने लिख कर भेजा इन तीनों इंडस्ट्रियल सेंटर्स को मिलाने के लिये १५ मील की एक सड़क तथा टोंस नदी पर पुल का निर्माण कराना आवश्यक है। जलालपुर कस्बा टोंस नदी से मिला हुआ है और पुल बनाने से काफी साधन उसे उपलब्ध हो जाते हैं।

जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा भ्रष्टाचार क बारे म मेरा भी यही विचार है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है और माननीय मंत्री महोदय बावजूद माननीय सदस्यों के कहने पर भी कोई ध्यान उस पर नहीं देना चाहते। नौकराशाही के चंगुल में फंसे हुए हैं और नौकरशाही उनके सर पर चढ़ कर बोल रही है। हम लोग अगर उनका ध्यान किन्हीं मामलों की तरफ दिलाते हैं तो उनका कोई ध्यान उस तरफ नहीं जाता। आज इस विभाग के कर्मचारियों के वेतन में भी बड़ी असमानता है और उस असमानता को दूर करने के लिये मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें और उस भ्रष्टाचार को, जो फैला हुआ है, दूर करने का प्रयत्न करें। १५ परसेंट का कमीशन ठेकेदार से लिया जाता है और उसके फलस्वरूप बरसात में हाल की ही बनी हुई पुलिया रामगढ़-जलालपुर रोड पर गिर गयी थी।

श्री श्रीराम (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिये और विरोधी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोधी दल की तरफ से बहुत सी बातें इस विभाग के संबंध में कही गयीं। श्री कल्पनाथसिंह ने कहा कि उनको इस विभाग से खतरा है और इसलिये इस विभाग को ही खत्म हो जाना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है, उसे दूर होना चाहिये। सरकार को जरा कड़ी निगाह इस संबंध में रखना चाहिये कि जिले के अधिकारी और कर्मचारी तत्परता तथा मुस्तैदी से कार्य करें।

इस विभाग से सम्बन्धित देश का सारा सार्वजनिक निर्माण कार्य है और देखा यह जाता है कि कर्मचारीगण निजी स्वार्थ साधन के लिये भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो जाते हैं। ठेके जो ठेकेदारों को दिये जाते हैं उनमें कहीं कहीं ऐसा जरूर है कि एक निश्चित धनराशि अधिकारियों से तै हो जाती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विरोधी पक्ष कोई रचनात्मक दृष्टिकोण न रख कर केवल आलोचना करे। उसे रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और सुझाव रखना चाहिये भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये। भ्रष्टाचार सिर्फ सदन में या सदन के बाहर आलोचना करने से ही दूर नहीं हो सकता। हमारे समाज में खामियां हैं और हमें समाज को इस काबिल बनाना है कि वह भ्रष्टाचार से दूर रहे। आज जो अधिकारी हैं उनमें से बहुत से हमारे भाई हैं, लड़के हैं या संबंधी है। इसलिये अगर इस सदन के सदस्य ही यह निश्चय कर लें कि वे अपने संबंधी को तथा जिस गांव में वे रहते हैं वहां के किसी आदमी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे तो भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। सरकार कानून बनाती है भ्रष्टाचार दूर करने के लिये लेकिन वह कानून कैसे लागू हो सकता है? जब कोई भ्रष्टाचार का केस पकड़ा जाता है तो सबूत नहीं मिलता। इस सदन के माननीय सदस्यों को चाहिये कि जहां कहीं भ्रष्टाचार के केस पकड़े जायें उनमें वे दिलचस्पी लें और इस बात की कोशिश करें कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों को दंड मिले।

दूसरी चीज विरोधी पक्ष की ओर से यह कही गयी कि बहुत से कर्मचारी अस्थायी ह। बात यह है कि यह डिपार्टमेंट ऐसा है कि कहीं कहीं थोड़े दिनों का काम रहता है। इसलिये अस्थायी कर्मचारी तो रहेंगे ही लेकिन जहां पर इस नेचर के कर्मचारी हों जिन्हें ज्यादा दिन तक काम करना हो तो उन्हें स्थायी अवश्य करना चाहिये।

चूंकि समय कम है इसलिय जनरल बातें न कह कर अब अपन जिल की ओर म मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा। मेरे जिले में एक सड़क जबरैला से मौरावां तक है जो बहुत खराब हालत में है। उसे मंत्री महोदय ने अपने विभाग में ले लिया है जिसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन इस सड़क पर एक जबरैला का पुल है जिसके कम चौड़ा होने की वजह से हर साल सई नदी की बाढ़ से हजारों रुपये का नुक्सान होता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि या तो यह पुल चौड़ा किया जाय या पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा जो सड़क पुनर्निमित की जाय उसको ऊंचा किया जाय ताकि बाढ़ की समस्या हल हो सके।

श्री उपाध्यक्ष––अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री श्रीराम––दो मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––जी नहीं, ६–७ मिनट आपको वैसे ही हो चुके ह।

***श्री चतन्यराजसिंह** (जिला अलीगढ़)––श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय चूंकि सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिये मैं ट्रेजरी बेन्चेज के द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं माननीय कल्पनाथजी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। इस डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके मुताल्लिक काफी माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। इसलिये उस पर मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं। मुझे तो सिर्फ यह निवेदन करना है कि जैसे जैसे किसी देश की सभ्यता, उसकी संस्कृति डेवलप होती है वैसे वैसे रोड्स की भी तरक्की होती है। जितनी सोसाइटी तरक्की करती है उसी हिसाब से लोग तरक्की करते हैं और जैसे-जैसे इवोल्यूशन आफ ट्रांसपोर्ट होता है वैसे ही वैसे रोड्स की तरक्की होती है। प्राचीनकाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चैतन्यराजसिंह]

में भारतवर्ष में सड़कें बहुत अच्छी थीं परन्तु अब बहुत खराब हो गई ह जिसके संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है ।

श्रीमन्, यह भी जाहिर है कि आजकल हमारे प्रदेश पर चीनी आक्रमण का हमेशा डर बना रहता है । अल्मोड़ा और टेहरी-गढ़वाल के पास उनकी चौकियां हैं और हमारी केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार बड़ी इच्छुक है कि हमारे ट्रांसपोर्ट इस पहाड़ी क्षेत्र में अच्छे हो जायं जिससे हम लोगों को डिफेंस में बहुत सहूलियत हो जाय और यू० पी० गवर्नमेंट को मालूम है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में अच्छी सड़कें न होने के कारण बाबूगढ़ का मिलिटरी फार्म, जो प्रदेशीय सरकार को दे दिया गया था, उससे वापस ले लिया गया है और इसका कुछ अंश एक्सपेरीमेंट के लिये दे रखा है और जो सहारनपुर का फार्म था वह भी वापस ले लिया । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारी पंचवर्षीय योजना में काफी धन इस काम पर खर्च करने के लिये दिया जाय ।

इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि जो धन दिया जाता है वह पूरा इम्पलीमेंट नहीं हो पाता है और काम पूरे नहीं होते हैं । हमारा टार्जेट १६,५५३ मील लम्बी सड़कें बनाने का था दूसरी योजना में और यह विभाग केवल १४,४९० मील लम्बी ही सड़कें बना पाया जबकि बाम्बे प्लान में ५,००० मील लम्बी सड़कों का कोटा और प्रदेश को मिला था । लेकिन जब आप अपना टार्जेट ही पूरा नहीं कर पाये तो इसको कैसे बना पायेंगे, मान्यवर, यह भी सरकार से निवेदन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में २९२ करोड़ में से केवल १६.१४ करोड़ रुपया ही इस विभाग को मिला और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ४९७ करोड़ रुपये में से केवल १८ करोड़ रुपया ही मिल सका है । हम लोग भ्रष्टाचार पर तो बहुत ज्यादा जोर देते हैं लेकिन इधर ध्यान नहीं देते हैं । मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी प्रादेशिक प्लानिंग कमीशन से दरख्वास्त करें कि १८ करोड़ रुपया बहुत कम है और पहाड़ी क्षेत्रों में हमें बहुत सी सड़कें बनानी हैं क्योंकि डिफेंस के लिये उन की आवश्यकता है । रानीखेत और बरेली में कोई सड़क नहीं है । इसलिये इस रकम को बढ़ाया जाय और वह केन्द्रीय सरकार से या प्रदेश के प्लानिंग कमीशन से लेने का प्रयास किया जाय क्योंकि यह हमारी हिफाजत का मामला है ।

श्रीमन्, एक चीज और अर्ज करनी है, चाहे विरोध पक्ष के हों या सरकारी पक्ष के हों, सब लोग इस विभाग में करप्शन की बात बहुत करते हैं । हमें इसके बेसिक रूप को ढूंढ़ना है । यह ठीक है कि हमारे मंत्री जी को इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं, तीन तीन चीफ इंजीनियर हमारे प्रदेश में हैं, बहुत से एस० ई० और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां का टौप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन जो मामूली कर्मचारी हैं टैम्पो-रेरी सर्विस के हैं । उनको एक महीना का नोटिस दे कर निकाला जा सकता है, जब किसी के सर्विस की सिक्योरिटी नहीं है, तो वह अपना पूरा मन लगा कर कैसे काम कर सकता है ? जहां तक असिस्टेंट इंजीनियर्स का सवाल है उनको बासिज्म से फुरसत नहीं मिलती है ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त ।

*श्री सुरन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे निर्माण मंत्री ने जो अनुदान पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । पिछले समय जब तक हमारा मुल्क गुलाम रहा हमारे देश में कोई निर्माण-कार्य नहीं हुआ । विदेशी शासक तो अपनी शासन सुविधा के लिये निर्माण-कार्य करते थे हमारी सुविधा के लिये कोई निर्माण-कार्य नहीं करते थे । जब से हमारा देश आजाद हुआ हमने प्लान बनाये । पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई । हमने इन योजनाओं के अन्तर्गत काफी निर्माण-कार्य किया, पुल बनाये हैं, सड़कें बनायी हैं, बांध बनाये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं । उनको प्राथमिकता दी जाती है । शेष काम बाद में किये जायेंगे । हमारे सामने बहुत सी दिक्कतें आती हैं । लोहा आदि सामान समय पर नहीं मिलता है जिसकी वजह से जितना काम करना चाहिये उतना नहीं कर पाते हैं । जैसे हमारे बरेली जिले में रामगंगा प्रोजेक्ट चल रहा है । मैं एक मरतबा बरेली गया था । मैंने वहां के काम करने वालों से पूछा कि पुल में क्यों देर हो रही है तो उन्होंने कहा कि कुछ गर्डर वगैरह अमेरिका से इम्पोर्ट करने थे, वह इम्पोर्ट नहीं हो सके । इसलिये देर हो रही है । इसी तरह से शाहजहांपुर में खन्नौत नदी का पुल है । उसका भी निर्माण हो रहा है ।

मुझे मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर भी आकर्षित करना है । मेरे क्षेत्र में एक रोड है फतेहगंज से ले कर दातागंज तक, वह बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं तीन जिलों से हो कर जाती है । कोई भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इस सड़क की ओर ध्यान नहीं देता है । इसलिये मेरी प्रार्थना माननीय निर्माण मंत्री से है कि वह इस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत ले लें ताकि मेरे क्षेत्र में एक पक्की रोड हो सके । वहां बरसात के दिनों में रास्ता ब्लाक हो जाता है । अगर वह रोड ले लें तो केवल दो एक पुलियां बनानी पड़ेंगी । जमीन अक्वायर करने की जरूरत नहीं है । दोनों तरफ सड़क के दरख्त लगे हुए हैं । इसके लिये मंत्री जी से बार बार प्रार्थना करूंगा कि उस रोड पर ध्यान दें । मैंने पंचवर्षीय योजना की किताब भी देखी, उसमें भी उसका कोई जिक्र नहीं पाया । मेरा निवेदन है कि पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर में सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों का निर्माण होना बहुत जरूरी है । इनको प्राथमिकता दी जाय ।

पहले हमारे पास इतने रोड नहीं थे । अब काफी रोड्स बन गये हैं जिससे आवागमन की सुविधा काफी बढ़ गयी है । हमारे विरोधी भाइयों ने शिकायत की कि निर्माण-कार्य सुस्त हो रहा है । काम तो बराबर हो रहा है और पूरे प्राविन्स भर में काम हो रहा है । बहुत सी पक्की सड़कें बनी हैं, बहुत-सी सड़कों पर तारकोल डाला गया है, कुछ काम श्रमदान से भी हुआ है । इसलिये काम तो हो रहा है और आगे भी होता रहेगा । तृतीय पंचवर्षीय योजना में काफी काम की गुंजायश है । हम लोगों को चाहिये कि दोनों पक्ष के लोग निर्माण के कार्य में बराबर सहयोग दें । जब तक हम अपना सहयोग नहीं देंगे तब तक काम अच्छी तरह से नहीं हो सकता है । देहातों में सड़कों के निर्माण के लिये मिट्टी का काम हमको श्रमदान से कर लेना चाहिये । उसके बाद अथारिटीज से कहना चाहिये कि हमने क्ले वर्क कर लिया है अब आप कंकड़ वगैरह डालिये । अगर ऐसा किया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा । सड़कों के लिये जमीन देने में थोड़ी-सी दिक्कत लोग पैदा करते हैं । अक्वायर करते समय जो जमीन काश्तकारों की ली जाती है उसमें बहुत से पेटीशंस हो जाते हैं कि हमारे फार्म की जमीन उसमें पड़ गई है और इस तरह की बातें कही जाती हैं । तो मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जो सड़कें पहले से हैं पहले उनको पक्का कर दिया जाय, उसके बाद नयी सड़कों के लिये जमीन ली जाय ।

श्री बेदराम (जिला एटा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । श्रीमान् जी, आज के जीवन में यातायात का अत्यन्त महत्व है । यातायात के अभाव में दूकान वगैरह भी नहीं खुल सकतीं न उचित दामों पर किसान का कच्चा माल ही फरोख्त हो सकता है तथा आज के समय में सुरक्षा भी संभव नहीं है जब तक कि पहुंचने के उचित मार्ग न हों । परन्तु खेद है कि हमारा सार्वजनिक निर्माण विभाग उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार कार्य नहीं कर सका है ।

अब मैं अपने क्षेत्र सोरों शूकर, जो कि प्रांत का ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान का तीर्थ स्थान है उसको सोरों सहावर सड़क की ओर ले जाना चाहता हूं जिस पर कि पहली

[श्री बेदराम]

पंचवर्षीय योजना में कंकड़ पड़ा था परन्तु वहां से फिर कंकड़ उठा लिया गया और जो अमांपुर सड़क तीसरी योजना में बनाई जा रही है उसके तो द्वितीय योजना में तैयार हो जाने का निश्चय था लेकिन वह भी आज तक नहीं बन पायी है और अब भी बन रही है । अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सोरों सहावर सड़क जिस पर कि इतनी खाई है कि डकैत भी इसमें ठहर सकते हैं, अगर उसको आप पक्की न करा सकें तो कम से कम उस पर मिट्टी डालकर एक सा कराने का तो आश्वासन दिया जाय । और भी हमारे जिले में बहुत सी सड़कें पड़ी हुई हैं । जिला एटा में पटियाली के पास बूढ़ी गंगा पर पुल बनाने की अविलम्ब आवश्यकता है । दो वर्ष पूर्व पटियाली हिन्दू महासभा सम्मेलन का प्रस्ताव आया था । उत्तर में १९६१-६२ के लिये आश्वासन दिया गया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

सम्पूर्ण तराई क्षेत्र में एक इंच भी पक्की सड़क नहीं है । पुल तक नहीं बनाया जाता जिससे कि जनता को नदी पार करने में सुविधा हो जावे जबकि इस क्षेत्र के लिये डाकखाना, रेल, पुलिस, विकास खंड, जिला कचेहरी, तहसील आदि सभी विपरीत दिशा में स्थित हैं । अतः मेरी मांग है कि मंत्री जी अपने उत्तर में आश्वासन दें कि पटियाली के पास बूढ़ी गंगा पर पुल इसी वर्ष में बनकर तैयार हो जायगा ।

इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की तो यह हालत है कि कंकड़ पड़ जाता है लेकिन फिर उठवा लिया जाता है । अतः मैं माननीय कल्पनाथसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष जी, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान का समर्थन तथा विरोधीदल के कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । कार्यों के विवरण की जो यह पुस्तिका मिली है इसमें मुख्य पृष्ठ पर मुर्दा अजायबघर का यह चित्र अंकित है । उसको देखने से मालूम होता है कि इंजीनियरिंग विभाग में अच्छे कार्य कर्त्ताओं की कितनी कमी है । अभी सन् १९६१ में जो फ्लड आया तो उसके बेसमेंट में पानी भर आया । बिल्डिंग में कहीं और पानी नहीं आया । केवल बेसमेंट में पानी आया । वह इसलिये कि उसमें मैटीरियल इतना खराब लगा था और कोई उसको देखने वाला नहीं । उसमें दरवाजे वगैरा ऐसे लगे हैं कि जिस उद्देश्य से भवन का निर्माण हुआ है वही पूर्ण नहीं होता । मुर्दा अजायबघर इस भवन में उठकर आना था लेकिन अजायबघर की अलमारियां जो छतरमंजिल में रखी हुई हैं वह उन दरवाजों के भीतर से होकर अन्दर जा ही नहीं सकती हैं । इसलिये हमें यह प्रतीत होता है कि हमारे यहां के पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के अधिकारी जो प्रशिक्षित और शिक्षित कहे जाते हैं कितने अप्रशिक्षित और अनुभवहीन दिखाई पड़ते हैं ।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नागपुर योजना के अनुसार हमारे यहां १६,५५३ मील सड़कें बनानी चाहिये थीं लेकिन मार्च सन् १९६१ तक वह योजना पूरी नहीं हो पाई थी । हमें यह भी देख लेना है कि हमारे यहां पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में कितनी खामियां हैं और कार्यविधि कितनी दोषपूर्ण है । हमारे यहां पर इन्क्वायरी करने का तरीका इतना खराब है कि राप्ती नदी के ऊपर जो गोरखपुर-सहजनवां को मिलाने के लिये रोड ब्रिज बन रहा था वह ब्रिज टूट गया लेकिन जो इन्क्वायरी कमेटी बैठी, वह इन्क्वायरी करने गई और इन्क्वायरी की भी परन्तु उसने यह काम स्थानीय इंचार्ज सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर का ट्रांसफर बिना किये ही आरम्भ कर दिया जब कि यह कार्य ट्रांसफर के उपरान्त ही करना चाहिये था । इस बात से यह प्रतीत होता है कि जो कमेटी वहां पर इन्क्वायरी करने के लिये गई वह एक तरफा अपना फैसला देगी । अतः सदन को यह मेरा सुझाव है कि जब कभी इस तरह की जांच की जाय तो उस विभाग के जो अफसर उससे एफेक्टेड होते हों उनका वहां से तुरन्त ट्रांसफर कर दिया जाय ।

एक खास और जरूरी सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जो १० हजार से ज्यादा के काम अपने प्रदेश में चल रहे हैं और जिनको पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा किया जा रहा है उनके निरीक्षण हेतु एक नान आफिशियल कमेटी ७ सदस्यों की बनवाई जाय । जिस समय काम पूरा हो जाय उस समय सब एस्टीमेट, पुराने कागजात तथा सब रिकार्ड साथ लेकर वह कमेटी उस स्थान पर जाय और जाकर निरीक्षण करे और निरीक्षण करने के बाद ही पेमेंट हो । मेम्बरान को नान टैक्निकल कह कर मेरे इस सुझाव की अवहेलना नहीं की जा सकती । सदन के सभी मेम्बर्स को इन्क्वायरी करने का अधिकार मिल सकता है । यह बात मैं इस आधार पर कहता हूं कि जब डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और अंडर सेक्रेटरीज नान टैक्निकल हैं और जब वह कागजात की देख-रेख कर सकते हैं और उनकी रिपोर्ट पर आदेश दे सकते हैं तो हमारे सदस्यों को, जो स्थान स्थान को अपनी आंखों से देखते हैं, जन सम्पर्क रखते हैं, उनको ऐसा अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता ? प्रदेश में सदस्यों द्वारा किये गये कार्य सरकार के सामने हैं । मैं समझता हूं कि वे सदैव राष्ट्रीय और प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं । इसलिये मैं यह समझता हूं कि विभाग के इंजीनियर और सेक्रेटरीज से ज्यादा अच्छा काम वे कर सकते हैं । अतः मैं जोरदार तरीके से इस चीज को प्रेस करूंगा कि एक कमेटी ७ सदस्यों की जरूर बनाई जानी चाहिये इस विभाग के कामों की छानबीन करने के लिये ।

ठेकों के पेमेन्ट के विषय में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । जो पेमेन्ट विभाग के द्वारा होता है उसमें बहुत देर की जाती है । सरकार को कोई ऐसा टाइम फिक्स कर देना चाहिये कि फलां काम का पेमेन्ट इतने दिन में हो जायगा । अगर ऐसा निश्चित हो जाय कि इस स्टेज पर पेमेन्ट होगा तो ठेकेदार को जो रुपया इधर उधर देना पड़ता है वह न देना पड़े और जो बिल्डिंग मैटीरियल में कमी आती है और काम खराब होता है वह भी न हो । जब उसको यह मालूम हो जायगा कि इतने समय में उसको पेमेंट मिल ही जायगा तो उसको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलेगा । अगर पेमेन्ट के लिये कोई स्टेज फिक्स हो जाय कि इतने दिनों में पेमेन्ट होगा तो उससे भ्रष्टाचार दूर होगा क्योंकि ठेकेदार को मजबूर होकर मैटिरियल की क्वालिटी गिरानी पड़ती है । वह खुद खाता है और दूसरों को भी इसी वजह से खिलाता है । यदि वह ऐसा न करे तो उसका काम नहीं हो सकता है ।

एक टाउन प्लानिंग जो इसी पी० डब्ल्यू० डी० के साथ थी उसको अब अलग कर दिया है । मैं जोरदार आवाज में यह मांग करूंगा कि इस विभाग की इन्क्वायरी सी० आई० डी० को दी जाय क्योंकि जहां जहां से भी पब्लिक नक्शे प्लानिंग सेक्शन में पास करने के लिये भेजती है उसमें बहुत देर लगती है । जब तक कई बार उस आफिस का चक्कर न लगाये तब तक कोई सुनवाई नहीं होती है ।

अन्त में, मैं लखनऊ के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं । जो बांध इस समय बन रहा है यहां पर गोमती की बाढ़ को रोकने के लिये उसके लिये मेरा यह नम्र सुझाव है कि गोमती पर जो एन० आर० का पुल दिलकुशा के पास है वह और चौड़ा कर दिया जाय । यदि पानी का आउट लेट ठीक हो जाता है और उसके निकलने का रास्ता ज्यादा हो जाता है तो बाढ़ का अन्देशा कम रहेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं जो हमारे मंत्री महोदय ने उपस्थित किया है ।

***श्री शिवचरण** (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग की ओर से जो पुस्तिका बाटी गयी है उसके अनुसार विभाग के वर्तमान काम को देखते हुए मैं आगरा जिले को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवचरण]

चन्द सड़कों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित कराना चाहता हूं। पहले तो जिस तहसील से मैं चुन कर आया हूं उस ओर प्रकाश डालना चाहता हूं। तहसील एतमादपुर में दाऊजी जाने वाली कच्ची सड़क जो मथुरा जिले से संबंध रखती है, अगर उस पर बहरामपुर पर पुल बना दिया जाय तो खतौली, जो उस तहसील में पड़ता है वहां के लोगों को आने जाने में सुविधा हो जायगी। उस पुल के बन जाने से वहां के कर्मचारियों को भी बड़ी आसानी हो जायगी। फर्रुखाबाद से कोटला जाने वाली जो ९ मील की सड़क है उस पर रोज हजारों आदमी आते जाते हैं। वहां चूड़ियों के कारखाने हैं और कोटला के आसपास न जाने कितने नौजवान बेकारी की हालत में घूमते हैं इसलिये कि सिरसा और सेंगर नदी की बाढ़ से वह सारा इलाका गरकी में आ चुका है। वर्षा होने पर उस सड़क पर नदियों का पानी आ जाता है और यातायात बंद हो जाता है और वहां का जनजीवन मौत का शिकार बनता जा रहा है। सराई नाई से जलेसर जाने वाली कच्ची सड़क का निर्माण अगर हो जाय तो उससे उस इलाके का बड़ा लाभ होगा। सरकार कहती है कि ५,००० और २,००० वाली आबादी के कस्बों तक सड़क होनी चाहिये। खंडा, चावली आदि में आबादी ४ या ६ हजार के करीब है। इस के अलावा कुबेरपुर से बरहज जाने वाली सड़क का निर्माण हो जाय तो भी हजारों आदमियों की जान बच सकती है और वहां के बहुत से लोगों को सुविधा प्राप्त हो सकेगी। खतौली से सेमरा जाने वाली सड़क ५ मील की दूरी पर है और दोनों कस्बे ६,७ हजार की आबादी के हैं। जब बरसात होती है तो ३,४,५ मील में दो तीन महीने रास्ता बंद रहता है। सड़कों पर पानी चलता है। इस पुस्तिका में मंत्री जी ने लिखा कि सभी सड़कों का विकास होना चाहिये। लेकिन चूंकि यातायात बहुत अधिक हो गया है इसलिये कंकड़ द्वारा कुटी हुई सड़कें जो पहले ५ साल तक चलती थीं अब उनकी देख-भाल की जरूरत हर साल होगी। इस हिसाब से उसका निर्माण १९६७ या १९७२ के बाद ही संभव हो सकेगा। यदि सरकार इन सड़कों का निर्माण अपने हाथ में लेती है तो उस क्षेत्र की जनता को वह बड़ी सुविधा प्रदान कर सकेगी। इन सड़कों की तरफ सरकार कभी ध्यान नहीं देती। यदि सराई नाई वाली सड़क पर मुड़ो जहांगीरपुर पर पुल बन जाय तो वहां के निवासी अपना जीवन अच्छी प्रकार से बिता सकते हैं। खांडे को जाने वाली यह सड़क है। हसनपुर आदि के निवासियों ने अंग्रेजों को भगाने के लिये १९४२ में अपना पूरा पूरा सहयोग दिया था। उनकी आज हालत गंभीर है।

एक माननीय सदस्या किरावली तहसील से चुन कर आयी हैं, लेकिन वह शायद ही बोलें उनकी बात मैं कह दूं कि अछनेरा से रायवा होती हुई जाने वाली सड़क की हालत क्या है। जैसा माननीय सदस्य लक्ष्मीसिंह जी ने कहा था, यदि कोई गर्भवती उस पर निकल जाय तो डबल नुकसान हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

श्री शिवचरण—एक मिनट और। पेहनर से राजा खेरा जाने वाली सड़क, जहां से विद्यावती जी चुन कर आयी हैं, वहां के लोगों का जन जीवन खतरे में पड़ गया है। मैं आशा करता हूं कि इन सड़कों का निर्माण इसी साल कर दिया जायगा। यदि ऐसा न हुआ तो मुझे भय है कि एतमादपुर के इलाके की देहाती जनता सोसलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कोई सक्रिय कदम उठाने के लिये बाध्य न हो जाय।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो पुस्तिका बटी है, उसे देखने से मालूम हुआ कि प्रदेश में सरकार ने काफी काम किया है। लेकिन कई ऐसे जिले हैं जिनको तीसरी योजना में एक मील सड़क भी नहीं मिली। उदाहरण के लिये मैं फैजाबाद जिले का जिक्र करता हूं। वहां योजना काल में एक फर्लांग सड़क भी नहीं रक्खी गई है।

पता नहीं क्यों ? सरकार यह दलील देती है कि जिन जिलों में सड़कें अधिक हैं वहां और सड़कें नहीं दी जायगी। किन्तु जैसे अंग्रेजों ने लखनऊ से बनारस को मिलाने के लिये, जो सड़कें बनाई, उन के बीच के जिलों में पड़ने के कारण क्या उन जिलों को नई सड़कों से वंचित करना वांछनीय है ? ऐसा करना उनके साथ अन्याय होगा। सरकार का यह भी आइडिया है कि जहां ५ या दो हजार की आबादी हो, उन कस्बों तक सड़क होना अनिवार्य है। पश्चिमी जिलों में तो बड़े बड़े गांव हैं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत कम गांव होंगे जिनकी आबादी ५ हजार हो। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले को उस जिले की आबादी के हिसाब से सड़कें एलाट की जायं। यदि ऐसा न किया गया तो पूर्वी जिले सड़कों से वंचित रह जायंगे। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं, वहां पी० डब्ल्यू० डी० की एक मील सड़क भी नहीं है और न सरकार की ऐसी स्कीम है कि वह उस क्षेत्र को कुछ सहायता करे। वहां की जिला अन्तरिम परिषद् ने जहांगीर गंज से सुल्तानपुर तक की सड़क को प्राथमिकता दी थी, किन्तु सरकार उसे बदल कर दूसरी सड़क बनाने जा रही है। सरकार में परिषद् के प्रस्ताव की अवहेलना भी की जाती है मैं चाहूंगा कि नीचे के प्रस्ताव को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। इसके अतिरिक्त आज मेरे जिले में पुल भी नहीं हैं। खास तौर से उस इलाके में जो आजमगढ़ से मिला हुआ है। इलेक्शन के दौरान में कर्मचारियों को मालूम हो गया कि वहां पुल की आवश्यकता है और ८ दिन के लिये वहां लकड़ी का पुल बनाकर काम चलाया गया। जब वहां पर कुछ लोग चुनाव कार्य के लिये गये और जब एक सरकारी बस उस पुलिया पर से गुजरी कि वह पुलिया टूट गयी और सरकारी कर्मचारियों को पानी से होकर गुजरना पड़ा तथा बड़ी परेशानी हुई। मान्यवर आये दिन उस क्षेत्र में चोरी और डकैतियां आदि पड़ती रहती हैं। वह जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती आदि जिलों का बार्डर है। अगर वहां पर पुल नहीं होगा तो वहां सरकारी आदमी जरूरत पड़ने पर नहीं आ जा सकेंगे और वहां पर सुरक्षा आदि का भी प्रबन्ध नहीं हो पायेगा। आपको गांवों की तरफ पहले ध्यान देना चाहिये वहां के रास्तों की तरफ पहले ध्यान देना चाहिये तभी आप सुरक्षा कायम रख सकेंगे। टांडा के पास श्रमदान द्वारा एक सड़क को बनाया गया मगर सरकार से उसके लिये कोई इमदाद नहीं मिली।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मेवालाल (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो बोलने का आज अवसर मिला है उसके लिये मैं आपका बहुत अभारी हूं। मान्यवर, मैं वजीरेआजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्षेत्र से आता हूं। अगर मुझे दो चार घंटे का समय मिलता तो मैं कुछ उस क्षेत्र की हालत के बारे में बताता मगर आपने ५ ही मिनट दिये हैं। मैं माननीय कल्पनाथसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारे क्षेत्र सोरांव में सड़कों की वह दशा है कि जहां बरसात में ही नहीं, बल्कि सूखे के दिनों में भी चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। नहर का पानी जब खोल दिया जाता है तो वहां भर जाता है। व्यापार तो तबाह हो ही रहे हैं, किसान जो हैं जिन्हें अपनी खेती की चीजों को लेने के लिये इधर उधर आना जाना पड़ता है, बाजार आदि जाना होता है, वे लोग भी नहीं आ जा पाते। आज १५ साल हिन्दुस्तान को आजाद हुये हो गये मगर पंडित जी के क्षेत्र की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। इलेक्शन के टाइम पर कल्याणपुर से बहादुरगंज होते हुये सड़क की मांग जनता ने की थी, उसके लिये पेपर में भी निकलवाया गया था। माननीय सिंचाई मंत्री जी भी वहां गये थे और उन्होंने आश्वासन दिया था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक वह कार्य नहीं हुआ। केवल अफवाह ही उड़ा दी गयी है कि वहां कार्य होगा। मेरा निवेदन है कि इस सड़क को जल्दी बनवाने की कोशिश की जानी चाहिये।

[श्री मेवालाल]

इसके अलावा श्रंगवेरपुर एक वह स्थान है जहां पर भगवान रामचन्द्र जी वन जाते समय टिके थे। वहां पर एक मन्दिर में शान्ता देवी की मूर्ति है जहां पर सप्तमी के दिन एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। वहां पर इलेक्शन के टाइम पर माननीय मुख्य मंत्री तशरीफ ले गये थे और उन्होंने वहां सड़क बनवाने के लिये आश्वाशन दिया था, मगर वह पूरा नहीं हुआ। मुझे दुख होता है कि जब ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई आश्वाशन देते हैं और वह पूरा नहीं होता और इलेक्शन के टाइम पर वोट पाने के लिये झूठे वायदे किये जाते हैं। मुझे यह सुन कर बड़ा दुख होता है। मैं प्रमाण देने के लिये तैयार हूं। पी० डब्ल्यू० डी० के मंत्री जी अगर थोड़ी तकलीफ गवारा करें तो मैं हालत दिखला सकता हूं उस क्षेत्र की। श्रीमान् जी, जहां शान्ता देवी का मन्दिर हाल ही में टूट गया है उसमें थोड़ी लागत की जरूरत है, सरकार ने वायदा किया और मुख्य मंत्री जी ने भी हाल में ५०० रुपया इलेक्शन के टाइम में दे भी आये, लेकिन वह अभी नहीं बन रहा है। दूसरी बात यह है कि रामवारा रोड वहीं पर है जहां रामचन्द्र जी टिके थे। वहां का मन्दिर, धर्मशाला और सड़क की दयनीय दशा है और आप ताज्जुब करेंगे कि वह हिन्दुस्तान में मशहूर जगह है, धार्मिक स्थान है। मैं उसके लिये निवेदन करूंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जरूर बनेगा। इसके अलावा मोटर पर कछार में हमारे मंत्री जी गये थे, एक भवन का निर्माण किया है, ईंटें भी गिरी हैं, लेकिन समस्या यह है कि पंडित जी के प्राइवेट सेक्रेटरी को वहां से खड़ा कर रहे हैं और प्रचार चल रहा है, लेकिन वहां पर आपस में फूट डाल कर जो ईंटा पड़ा हुआ है उसको रुकवा दिया है। सिंचाई मंत्री ने आश्वासन दिया है कि नहीं हटाया जायगा। लेकिन कछारी इलाके की जनता को तकलीफ है। वहां जो पुल १५ साल से टूटा हुआ है, लालबहादुर शास्त्री और पंडित जी वहां से खड़े होते हैं, उसके लिये कई लाख रुपया मंजूर भी हुए हैं, लेकिन वोट ले लेने के बाद चुपसार कर सरकार बैठी हुई है और जनता में त्राहि त्राहि मची हुई है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मेवालाल---एक मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप बैठिये। श्री गणेशप्रसाद।

श्री लखपतराम शर्मा---मुझे एक निवेदन करना था कि अध्यक्ष महोदय ४० सदस्यों के लिये स्वीकृति दे गये हैं कि उनको समय मिलेगा बोलने के लिए, तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि वे ४० सदस्य बोल सकें।

श्री उपाध्यक्ष---मैं ५ मिनट देता हूं, कभी ६ मिनट हो जाता है। अब आप विराजिये।

श्री प्रेमसिंह---मुझे भी दो मिनट दे दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष---आप विराजिये।

श्री गणेशप्रसाद (जिला गोरखपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का अनुगृहीत हूं कि आपने इस अनुदान पर मुझे बोलने का सुअवसर प्राप्त कराया। मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस अनुदान का जोरदार समर्थन करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांस गांव तहसील, गोरखपुर जिले में ऐसी तहसील है जहां रेल एक इंच भी नहीं है और प्रान्तीय सड़क एक पक्की बनी हुई है। बाकी सारी सड़क कच्ची पड़ी हुई है, यद्यपि वे सारी सड़कें गैर जिलों को गोरखपुर जिले से मिलाने वाली है। उदाहरण के लिये कौड़ीराम से गोला रोड को कहता हूं जो गोरखपुर को आजमगढ़ से मिलाती है। दूसरी सड़क कौड़ीराम से गजपुर रोड से देवरिया जिले से गोरखपुर जिले को मिलाती है। और तीसरी बांसगांव से माल्हनगर, घुरियापार होकर नरगड़ा होकर कम्हरिया जाती है जो गोरखपुर जिले को फैजाबाद जिले से

मिलाती है। चौथी सिकरीगंज से बेलघाट होकर कूरी बाजार को जाती है। वह गोरखपुर जिले को बस्ती जिले से मिलाती है।

इसके अतिरिक्त एक सड़क सदर तहसील में जैतपुर से पिपरौली बाजार होकर वोकटड के पास गोरखपुर से बस्ती रोड को मिलाती है। छठवीं फरेंदा से नौतनवा जाने वाली सड़क जो आगे नैपाल राज्य के बुढ़वल तक जाती है, बहुत ही खराब हालत में है। इसी प्रकार निचलौल से टूटी वारी जाने वाली सड़क भी गोरखपुर जिले को नैपाल राज से मिलाती है। खराब दशा में है। और आठवीं टूटी बारी से नौतनवां तक बार्डर की सड़क भी खराब है। इन सब को पक्की करा दी जाय। एक सड़क वजनी से माल्हनपार असिलामार होकर गोपालपुर जाती है उसे पक्की करा दी जाय। इन शब्दों के साथ में अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विषय पर चर्चा चल रही है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि दो पंचवर्षीय योजनाओं में पुलों, सड़कों और अन्य कार्यों में अच्छी प्रगति हुई है। प्रगति ही नहीं यहां तक कहते हैं कि हमने उस राम राज्य की सीमा को भी पार कर लिया है। इस राज्य के लिये श्री तुलसीदास जी ने कहा था "मांगी नाव न केवट आना" यानी राम के राज्य में इतने पुल नहीं थे इसलिये केवट के आने की जरूरत थी, किन्तु आज इतनी सड़कें, नदी पर पुल बन गये हैं कि लोग बिना नावों और केवट के ही नदियों को पार कर सकते हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात उसी तरह से है जिस प्रकार हम घुसना झोपड़ी में चाहते हैं, लेकिन ऊंट पर चढ़कर। हम यहां समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं किन्तु बड़े-बड़े कारखाने, पुल और सड़कें बना कर, यह कहाँ तक सम्भव हो सकता है। हमें झोपड़ी में घुसने के लिये ऊपर चढ़कर नहीं, पैदल जाना होगा। मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक जिले में जो छोटी-छोटी सड़कें हैं जिनका सम्बन्ध गांवों को इन बड़ी सड़कों और पुलों को मिलाने से है, उनपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि जब तक गांवों को बड़ी सड़कों, पुलों से नहीं मिला दिया जायगा तब तक देहात की स्थिति दिन-ब-दिन आवागमन के अभाव से गिरती ही जायगी। मिसाल के तौर पर मैं बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मैंने अध्यक्ष मंडल कांग्रेस कमेटी, हैदरगढ़ एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य की हैसियत से सरकार को लिखा था कि हैदरगढ़ क्षेत्र की हैदरगढ़ से शिवगढ़ (बछरावां) जाने वाली सड़क और हैदरगढ़ से महाराजगंज जाने वाली सड़क ऐसी है जिनको पक्की करने के लिये सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिये। इस पर सरकार से आश्वासन भी मिला था कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय उनपर बिचार करेंगें, किन्तु विचार करना तो दूर रहा, तहसील भर में किसी भी सड़क का नम्बर नहीं आया, जिसको पक्की करने की योजना स्वीकार की गयी हो। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हैदरगढ़ से महाराजगंज सड़क दरियाबाद, रायबरेली, डलमऊ तक जाती है, वह ऐसी सड़क है जिस पर हजारों की संख्या में लोग लोधेश्वर महादेव जी पर जल चढ़ाने के लिये डलमऊ गंगा नदी को जल भरने पैदल कांवर लेकर जाते हैं। वे जिन यातनाओं को सहन करते हैं उनको देखकर हैरान हो जायेंगे। सड़क पर कमर भर के गढ़े हो गये हैं। हैदरगढ़ से सुबेहा तक जाने वाली सड़क की खराबी की वजह से जो मोटर लारियां चलती हैं वह रास्ते में ही फेल हो जाती हैं। बरसात में ३–४ महीने गाड़ियां भी बन्द हो जाती हैं। यह सड़क भी पक्की होनी चाहिये। बाराबंकी के लिये देवीगंज होते हुये सुबेहा तक जो सड़क जाती है वह पक्की होनी चाहिये जिस पर राड़ीनाला पड़ता है, घाटमपुर के पास कोई पुल नहीं है। बरसात में बाराबंकी हैदरगढ़ से सुबेहा क्षेत्र का संबंध टूट जाता है।

[श्री रामकिशोर]

सुबेहा क्षेत्र के लिये गोमती नदी, इस राड़ीनाले पर पुल न होने के कारण एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर पुलों की व्यवस्था होनी चाहिये। छुंदरौली से गूढ़ा रायबरेली तक १८ मील श्रमदान मार्ग को पक्का बनाया जाय। मैं अधिक समय न लेकर यही निवेदन करूंगा कि हमें बड़ी-बड़ी सड़कों के साथ-साथ तृतीय योजना में इन छोटी-छोटी सड़कों को भी महत्व देना है जो कि छोटे-छोटे गांवों को बड़ी-बड़ी सड़कों से मिलाती हैं। तभी हमारे देश में, समाज में और ग्रामीण क्षेत्रों में एक सुख समृद्धि का वातावरण उत्पन्न होगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं देखता हूं कि कांग्रेस की तरफ से जब दूसरे साहब बोल रहे हैं तो १०, १२ आदमी खड़े हो जाते हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---अगर आप लिस्ट से नाम पढ़ दें तो अच्छा हो। वैसे लिस्ट की परम्परा हमारी पद्धति के विरुद्ध है। अगर आप इसे बन्द कर देंगे तो सदन की बहुत सेवा करेंगे।

***श्री शीतलप्रसाद** (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं इस विभाग को धन्यवाद इसलिये देता हूं कि हमारे जिले में सरजू नदी पर इसने पुल बनवाना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे हमारे जिले का और इस राज्य का पूरा हित तभी हो सकता है जबकि घाघरा नदी पर भी एक पुल बना दिया जाय। सरजू और घाघरा को पार करके जो सड़क आसाम को गई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिये।

हमारे क्षेत्र में सरजू और घाघरा नदियों का किनारा करीब ३०,३५ मील लम्बा-चौड़ा है। हमारे क्षेत्र के शुरू ही में एक नाला कहिये या नदी कहिये, ढकिया नाला के नाम से पड़ता है लेकिन वह इतना भयंकर है कि बरसात में उसे पार करना असम्भव हो जाता है। जब जमींदारी थी तो उस नाले पर अयोध्या के राजा की ओर से पुल था लेकिन सन् ३७ में सैलाब में वह गिर गया और वहां की सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० में न देकर जिला बोर्ड को दे दिया गया। वह पुल आज तक नहीं बन पाया है। हम लोग जब जनता से कहते हैं कि हमारी सरकार जनता के हितों में ही उसके टैक्स को खर्च करती है तो उसका जो उत्तर हमें जनता से मिलता है उससे हम लज्जित और निरुत्तर हो जाते हैं। तो माननीय मन्त्री जी उस पुल को अविलम्ब बनवाने की कृपा करें।

नाले के उस पार लगभग डेढ़ लाख जनता बसती है। वहां के लिये ६ मील का फासला है। वहां सड़क बनने से इन डेढ़ लाख मनुष्यों के आने-जाने का मार्ग सुगम हो सकता है। सैलाब के जमाने में वहां की जनता को हर तरह की राज्य की ओर से सहूलियत पहुंचाई जा सकती है। सैलाब के जमाने में वहां पुल न होने से अधिकारी बहुत देर से पहुंच पाते हैं और केवल छोटे अधिकारी, जैसे ए० डी० ओ० या कानूनगो ही पहुंचते हैं। इस प्रकार वहां के बाढ़-पीड़ित लोगों का संकट दूर नहीं हो पाता है।

हमारी तहसील में एक सड़क ३५ मील लम्बी करनैलगंज से नवाबगंज तक है जिसे इस विभाग ने बनवा दिया है और उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन टेढ़ी एक नदी या नाला है जो बहुत भयंकर है। उस पर पुल था और अब किसी तरह से उसकी मरम्मत हो गई है, लेकिन उस पर ट्रक पास नहीं होता है, बसें तो होने लगी हैं। हमारे यहां का गन्ना नवाबगंज शुगर मिल को पहुंचाया जाता है जिसके लिये गोंडा होकर नवाबगंज जाना पड़ता है। इस प्रकार ३२, ३४ मील का फासला बढ़ जाता है। अगर वहां पुल बन जाय तो केवल १८ मील की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंजिल रह जाती है और थोड़े किराये में किसानों का गन्ना आसानी से नवाबगंज फैक्ट्री में पहुंचाया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से पुनः प्रार्थना करूंगा कि उस क्षेत्र के लिये अवश्य ध्यान दें।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जबकि समय का अभाव है और ऐसे अवसर पर जो आपने मुझे बोलने का समय दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आज के वाद-विवाद से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारी सरकार के वर्तमान प्रशासकों ने जो तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाई है, जिसमें आगे चल कर सड़कों का और ऐसे ही अन्य कार्यों का विवरण दिया गया है, उसमें बहुत से पिछड़े हुए इलाकों को छोड़ दिया है, जहां कि वास्तविक आवश्यकता है। यह समझ में नहीं आता कि उनकी क्या मंशा और विचार धारा है, और क्यों उन्होंने उन पिछड़े हुए इलाकों को छोड़ा है। मैंने पहले भी बताया था कि ५० लाख रुपये के लगभग कर के रूप में वहां के क्षेत्र से सरकार को प्राप्त होता है। वहां की केवल १० मील की सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० ने अभी तक नहीं बनवाया है। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बतलाया, आजकल वह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० से लेकर अन्तरिम जिला परिषद् को दे रखी है। बार-बार वहां के मेम्बरों ने सरकार के मन्त्री जी से कोटला-फीरोजाबाद सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० में लाने के लिये कहा लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। खेती और सिंचाई के लिये हमारी सरकार वहां अच्छे साधन उपलब्ध कर रही है। ट्यूबवेल बन रहे हैं परन्तु किसानों की पैदावार सही कीमत पर बिकवाने के लिये आवागमन की निहायत जरूरत है। कोटला वह स्टेट है जहां के श्री किशोर पाल सिंह १९३१ में इसी असेम्बली में थे और एजूकेशन मिनिस्टर थे। उस समय वह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० में थी लेकिन अब उसको पी० डब्ल्यू० डी० से निकाल दिया गया है। वहीं पास में एक फतेहाबाद है उसके और फिरोजाबाद के बीच में जमना नदी पड़ती है। और अगर इसके बीच में सड़क बन जाय तो दोनों शहरों में आना जाना हो जाय और बहुत अच्छे सम्बन्ध हो जायं, एक दूसरे को प्रोडक्शन आ जा सके। इसमें सरकार का जो खर्चा होगा उससे अधिक उसको आवागमन से मिल जायगा क्योंकि वहां से बहुत लोग आते जाते हैं और बहुत सा सामान भी आता है।

जमना ब्रिज से लेकर शिकोहाबाद तक के इलाके को पिछड़ा हुआ इलाका घोषित किया जाय क्योंकि उस क्षेत्र में जमना के ऊंचे-ऊंचे खार हैं जिनमें मल्लाह लोग रहते हैं। वे बहुत गरीब हैं, उनका जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। पहले उनको क्रिमिनल ट्राइब्ज माना जाता था लेकिन अब उनको विमुक्त जातियों में माना जाता है। अतः इस क्षेत्र को सरकार पिछड़ा हुआ क्षेत्र मान कर वहां की तरक्की करे और आवागमन के साधन वहां जुटाये।

श्री नित्यानंद पांडेय (जिला कानपुर)---जो अनुदान अभी पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं तथा उसकी प्रशंसा करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी इसके सम्बन्ध में बहुत सी ऐसी बातें कही गयी हैं जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने इस बात को भी नहीं देखा कि १४ सालों में क्या-क्या हुआ है। अगर किसी को दिन में सूर्य के प्रकाश में भी नहीं दिखाई देता है तो उसमें भगवान सूर्य का क्या दोष है? जितनी योजनायें चलाई गई हैं अगर उनको कोई आदमी न देखे तो क्या किया जाय।

अब मैं अपने जिले के बारे में मन्त्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक सड़क जो रसूलाबाद से झींझक को जाती है, वह दूसरी पंचवर्षीय

[श्री नित्यानंद पांडेय]

योजना में पूरी हो जानी थी लेकिन पिछले साल इंजीनियरों ने उस पर मिट्टी नहीं पड़ने दी। जानबूझ कर विभाग के अधिकारियों ने देर लगायी। यह सड़क बहुत जरूरी है।

एक सड़क झींझक से मंगलपुर तक जाती है जो पहली सड़क से मिल जाती है। यह मंजूर की हुई सड़क है। इसको दूसरी और तीसरी योजना में प्राथमिकता दी गयी है। मन्त्री जी ऐसी कार्यवाही करें जिससे इन सड़कों का शीघ्र निर्माण हो सके।

जब पिछले वर्षों में माननीय कमलापति जी सिंचाई मन्त्री थे, वे हमारे यहां पधारे थे। उन्होंने उस समय कहा था कि जो कैनाल रूरा से बिबियापुर जाती है उसको अगर पी० डब्ल्यू० डी० चाहे तो वे दे देंगे। माननीय मन्त्री जी उसको सिंचाई विभाग से मांग लें और उस सड़क को बनवा दें। अगर वह सड़क बन जायगी तो झींझक से रूरा-बिबियापुर तक आवागमन का साधन हो जायगा और लोगों को बहुत आसानी हो जायगी। कानपुर जिला सड़कों के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। शहर की चकाचौंध में ग्रामीण क्षेत्र की मांग धूमिल हो गयी है और कोई उसकी परवाह नहीं करता। यह कोई अत्युक्ति नहीं है और इसीलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर जिले में जिन सड़कों का निर्माण हो रहा है वे सड़कें शीघ्र ही बनायी जायं। इसके साथ ही रिहन्द डैम पर एक पुल बनाया जायगा, जहां पुराना पुल है उसे तोड़ कर उसके पास ही नया पुल बनाने की स्कीम है। वह ऐसी स्कीम है जिससे गांव के लोगों के घर गिरेंगे, उनकी उपजाऊ भूमि चली जायगी और निर्माण के नाम पर एक प्रकार से उनका विनाश सा-होगा।

श्री काशीनाथ—श्रीमन्, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि सूरज के प्रकाश में भी किसी को दिखलायी न दे तो इसमें किसी का क्या दोष है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि उनके कहने के मुताबिक जब सारे निर्माण कार्य हो चुके हैं या हो रहे हैं तो फिर वे क्यों बोल रहे हैं, क्या उन्हें भी दिन में नहीं दिखलायी देता है?

श्री उपाध्यक्ष—आप भी कह चुके, अब बैठिये।

श्री नित्यानन्द पांडेय—श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टेक्निकल नाम पर विभागीय इंजीनियरों द्वारा जो उस पुल का निर्माण वहां हो रहा है उससे उस कस्बे व गांव का बड़ा ह्रास होगा और इसके साथ ही जिन लोगों ने इस उम्मीद में अपनी दूकानें वहां बना ली थीं कि कभी यहां से सड़क निकलेगी, उन सब की दूकनें खत्म व बर्बाद हो जायंगी। रसूलाबाद और झींझक के बीच में जो मिन्दा का पुरवा है वहां की उपजाऊ भूमि उस सड़क व पुल के अन्दर चली जायगी जिससे वहां के लोगों का बड़ा नुक्सान होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है, माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है, कि वे अपने विभाग के इंजीनियरों को यह सुझाव दें कि वे पहले पुल को तोड़ने की कोशिश न करें। उन्हें तो इस तरह के आदेश उनको देने चाहिये ताकि लोगों में किसी तरह की गड़बड़ी, असन्तोष व क्षोभ न पैदा हो।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि समयाभाव में भी आपने मुझे समय दिया और उस कटौती के प्रस्ताव पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी को एक ही बात बतला रहा हूं कि प्रत्येक विभाग के कर्मचारी जब दौरे पर जाते हैं तो उन्हें प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में लिखित रूप से रिपोर्ट देनी चाहिये कि वहां क्या-क्या चीजें बन रहीं हैं या किन-किन-चीजों की जरूरत है, यदि ऐसा वे करते होते तो शायद ऐसी दिक्कतें न आतीं जो आज इस कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलते हुए बतलायी गयी हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भाई शालिगराम जी, शिवकुमार जी, बहुगुणा जी, डाक्टर जवाहरलाल जी, इतने जी हो चुके, लेकिन उस क्षेत्र का बिलकुल ख्याल नहीं किया गया। वहां किसी सड़क की ओर या आवागमन के साधनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि एक सड़क भरवारी से करारी होते हुए कौशाम्बी को जाती है। उसके बीच में एक ससुर खदेरी नदी पड़ती है जो बरसात के दिनों में इतना उग्र रूप धारण कर लेती है कि वहां के लोगों को सेंटर बाजार भरवारी तक जाने के लिये ८–१० मील का चक्कर करना पड़ता है। तो मेरी मांग है कि ससुर खदेरी नदी पर एक पुल बनवा दिया जाय नेवारी के पास भरवारी–करारी रोड पर।

उसके बाद फिर मैं यह मांग करता हूं कि कटरा गुलाब सिंह से म्योहर, करारी, पश्चिम शरीरा-शाहपुर रोड पर जहां सरकारी बस नहीं चलती हैं प्राइवेट बसें चलाने की इजाजत दी जाय और जो यह कच्ची सड़क है इसे पक्की करवाने की कृपा करें।

इसके अलावा राजापुर जहां श्री तुलसीदास जी का जन्म स्थान है, यमुना नदी के उस किनारे पर, इस किनारे पर इलाहाबाद है और उस किनारे पर बांदा है, महेवाघाट–राजापुर के बीच में पीरों का पुल बनवा दिया जाय तो राजापुर मंडी से लोगों को इलाहाबाद तक गल्ला लाने में बड़ी सुविधा हो जायगी। इलाहाबाद में बांदा से बहुत अधिक गल्ला आता है। इसके अलावा टेवा से पश्चिम शरीरा–शाहपुर सड़क बनवाने की व्यवस्था की जाय। तहसील के हेडक्वार्टर तक आने-जाने का कोई साधन नहीं है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। सरकार को चाहिये कि इसकी जांच कराये, और लोगों को चारों तरफ आने-जाने के रास्ते उपलब्ध कराये। इस क्षेत्र में कौशाम्बी और पबोसा पहाड़ी ऐतिहासिक स्थान हैं, जिनको देखने के लिये देश के चारों ओर से लोग आते-जाते हैं। इस ओर भी मन्त्री जी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इन चीजों की ओर ध्यान दिया जाय।

श्री काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)––उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)––उपाध्यक्ष महोदय, आप से पहले अध्यक्ष जी ने यह कहा था कि आज महिलाओं को प्राथमिकता दी जायगी, इसलिये आप कृपा कर उनको बुलवायें।

श्री उपाध्यक्ष––उनको भी अवसर दिया जायगा।

***श्री काजी जलील अब्बासी**––उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मन्त्री महोदय, ने पेश किया है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यों तो इन १५ वर्षों में हमारे प्रदेश के हर विभाग में तरक्की हुई है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, और मेरा ख्याल यह है कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग इस दौड़ में सब से आगे रहा है। अगर आप आज सूबे में जा कर देखें तो जहां गढ़े थे वहां पर सड़कें मौजूद हैं और जहां पर कि कोई भी यातायात के साधन नहीं थे वहां पर पुल बनाकर सुगम साधन बनाये गये हैं और यह तरक्की साफ-साफ निगाहों के सामने नजर आ सकती है और इस पर किसी बहस की गुंजायश नहीं है और हर आदमी इसको मान सकता है कि इस तरह का काम इस विभाग ने किया है। इस विभाग ने अपने कार्य द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, वैसे तो हर दिशा में कांग्रेस सरकार ने तरक्की की है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जिला जो प्रान्त का सब से बड़ा जिला है वह जरा बदकिस्मत रहा है। हमारे जिला बस्ती में इत्तिफाक से जो कुछ काम हुआ है वह उस बड़े जिले को देखते हुए बहुत कम है और शायद मन्त्री महोदय खुद इस बात को मानेंगे। हमारे हल्के में अब तक सिर्फ १६ मील की एक सड़क डुमरियागंज साउथ में बनी है जो निगाहों के सामने हम बतला सकते हैं और जो कुछ काम किये हैं वह भी पूरे नहीं हुए हैं। इसके अलावा और कोई काम इस १५ साल के जमाने में हमारे जिला बस्ती में नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काजी जलील अब्बासी]

डमरियागंज के नजदीक चिरवा के पुल की तरफ मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां कि जब भी मन्त्री जी जाते हैं तो उस की तरफ उन का ध्यान आकर्षित किया जाता है, वह मेरे क्षेत्र में नहीं है लेकिन वह हमारे जिले का बहुत अहम पुल है, और इस के जरिये नैपाल की सरहद से यातायात का साधन जुड़ जाता है।

इसके अलावा हमारे यहां की एक छोटी-सी सड़क और है जिसका अनुरोध भी किया गया। अभी २७ तारीख को एक जलसा हुआ था उस में मन्त्री जी को वह जगह दिखाई गई उन्होंने, बड़ी कृपा की, यह एक छोटा सा पुल है और एक छोटी सी सड़क का काम है। यह भानपुर-सिधौली, डुबारी बस्ती का ८ मील का क्षेत्र है जिसमें यह सड़क बननी चाहिये। इन स्थानों को यह सड़क जोड़ सकती है। इस की तरफ मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है और उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में भी आप के द्वारा मन्त्री जी का ध्यान इस छोटी सी सड़क की तरफ आकर्षित करूंगा। देखने में तो यह छोटी सड़क है लेकिन यह यातायात का बड़ा साधन पैदा करेगी, यह एक बहुत ही अहम सड़क है, यह कई अहम सड़कों को जोड़ने वाली सड़क है और सिर्फ एक पुलिया बनने से काम हो सकता है और जनता को काफी सुविधा हो सकती है।

इसके अलावा हमारे क्षेत्र का सब से बड़ा सवाल और सब से महत्वपूर्ण सवाल है, वह है चन्द्रदीपघाट का मामला, डुमरियागंज—चन्द्रदीपघाट-मसकिनवा-अयोध्या रोड के बनने से यातायात के बड़े साधन खुल जाते हैं और लोगों को काफी आराम पहुंचेगा। पिछले ५—७ साल से बराबर प्रस्तावों द्वारा और तरह-तरह से मैंने हर तरीके से इस विषय में कोशिश की है कि इस को प्राथमिकता दी जाय। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका, जहां तक पता चला है शायद आ नहीं सकी हालांकि बहुत कोशिश की गई। उस सड़क की महानता बहुत है क्योंकि उसके बन जाने से हमारे जिले को ही नहीं बल्कि गोंडा, फैजाबाद और करीब के जिलों को फायदा पहुंचेगा।

हरैया तहसील के अन्दर एक रामजानकी रोड है जो ५२ मील की सड़क है और गोरखपुर-बस्ती को हरैया तक जोड़ती है। मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उसका सर्वे हो गया है और छावनी से वह १० मील सड़क बनने वाली थी लेकिन सर्वे होने के बाद अब शायद यह आदेश हो गया है कि खलीलाबाद की तरफ से बनायी जायगी। इसके माने यह हैं कि छावनी तक पहुंचते-पहुंचते ५ साल या उससे भी ज्यादा वक्त बीत जाय। इसलिये मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप पुनः विचार करके रामजानकीरोड को छावनी की तरफ से बनवाने का आदेश करें। जो बातें मैंने अपने क्षेत्र के बारे में रखी हैं उनकी ओर मन्त्री जी ध्यान देने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कहा जाता है और शायद ठीक ही कहा जाता है कि जैसे मनुष्य के शरीर में कुदरत ने शिराओं का जाल बिछा रखा है, जिसके सहारे खून सारे शरीर में दौरा करके शरीर के अंग, प्रत्यंग को ताजगी देता है उसे स्वस्थ और जीवित रखता है। उसी तरह देश की तरक्की के लिये, उसके विकास के लिये, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो या सांस्कृतिक हो, सब के लिये सड़कों की बड़ी भारी आवश्यकता है। सड़कों पर मनुष्य ही सफर नहीं करते बल्कि विचार भी सफर करते हैं और बड़ी तेजी से करते हैं। आज के जनतन्त्र के युग में नये और स्वस्थ विचारों को सुन्दर गांवों में बसने वाली जनता तक पहुंचाने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि गुलामी के जमाने में जो हीन भावनायें गांव में आ गई हैं, जो देश और समाज के प्रति उदासीनता उनमें आ गई है उसको दूर करना है जिससे वह देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें और अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकें तथा देश की तरक्की में सहायता दे सकें।

सरकार ने जो पुस्तक बांटी है उसमें ऐसा लिखा है कि गांवों की भलाई और उनकी तरक्की के लिये कितना ही काम कर दिया जाय लेकिन पक्की सड़कों को अगर ५ मील

तक उन तक नहीं पहुंचाया जाय तो उनके विकास में बाधा पड़ेगी। यह बात सही है और ऐसा मालूम पड़ता है कि जहां तक सड़कों के महत्व का और प्रदेश को उनकी आवश्यकता का प्रश्न है सरकार इस ओर पूरी तरह सचेत है। परन्तु इस ओर जो प्रगति हुई है उसको देखने से मालूम होता है जिस गहराई के साथ इस बात को महसूस करती है उतनी तेजी से सरकार ने कदम नहीं बढ़ाया। १४ साल के अन्दर केवल ५,००० मील लम्बी सड़कें बनायी गईं। १९४७ तक ९,३८७ मील लम्बी सड़कें प्रदेश में थीं। और १९६१ तक १४,४९६ मील लम्बी सड़कें बनीं जब कि स्टार और ग्रिड फारमूले के अनुसार १६,५५३ मील लम्बी सड़कें बननी चाहिये थीं। स्टार और ग्रिड फारमूले के अनुसार जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे भी २,००० मील के करीब की लम्बी सड़कें रह गईं। लेकिन यह फारमूला १९४७ में बना था जो कि उसके बाद १९५८ में बम्बई में एक और फारमूला बना उसके अनुसार १९६१ तक प्रदेश में सड़कों की लम्बाई २१,००० मील होनी चाहिये। इस फारमूले के हिसाब से ७ हजार मील की कमी रही। और आगे योजना में तो बहुत थोड़ी लम्बाई सड़कों की बनाने के लिये रखी गई है। इससे तो जो जिले रह गये हैं उनमें बड़ी निराशा फैल गई है।

जहां तक इस फारमूले का सवाल है मैं कह देना चाहता हूं वह भी ईमानदारी के साथ नहीं बरता जाता। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर पहले से ही स्टार ऐंड ग्रिड फारमूला के हिसाब से लम्बी पक्की सड़कें मौजूद थीं। उनमें फिर भी बराबर काम होता रहा है। उनमें सड़कों की लम्बाई बढ़ गई। कानपुर, बिजनौर, प्रतापगढ़, बनारस, जौनपुर, लखनऊ, आदि ऐसे जिले हैं कि वहां फारमूले की परवाह तक नहीं की गई और जिनके हाथ में सत्ता थी या जिन व्यक्तियों की उन पर पहुंच थी उस क्षेत्र में सड़कें बनती गईं। जो जिले पीछे हैं उनका भी खयाल करना चाहिये था। अलीगढ़ जिला ऐसा है जहां स्टार ऐंड ग्रिड फारमूला के हिसाब से ३३४ मील पक्की सड़क होनी चाहिये वह ३२४ मील की लम्बाई तक ही बन सकी और निर्धारित लक्ष्य में भी १० मील सड़क की कमी रह गई।

मुझे याद है सन् १९४७ में श्री डी० डी० अग्रवाल, उप-सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग जब जिले में सड़कों की प्राथमिकता की योजना लेने के लिये अलीगढ़ गये थे तो जिला प्लानिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से हाथरस, गोंडा कच्ची सड़क को सर्व–प्रथम पक्की बनाये जाने की प्राथमिकता दी थी परन्तु कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने हाथरस–गोंडा को बदल कर अतरौली–कासगंज सड़क रख दी और हाथरस–गोंडा का आधा हिस्सा ही बन पाया बाकी १० मील की लम्बाई बनने से रह गई लिहाजा जो १० मील का हिस्सा बाकी रह गया है स्टार ऐंड ग्रिड फारमूले के अनुसार कम से कम उसे शीघ्र ही पूरा कर दिया जाय। गोंडा में विकास खंड का कार्यालय है और गोंडा जिला और तहसील दोनों के हैडक्वार्टर से कटा हुआ होने के कारण सड़क का यह बाकी बचा हुआ हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है।

*श्री रामशंकर रविवासी (जिला लखनऊ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने जो अनुदान सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं जोरदार विरोध करता हूं।

यह लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। कहने को बड़ी तरक्की की लेकिन अच्छी सड़कें केवल शहर के अन्दर जैसे हजरतगंज के अन्दर हैं (व्यवधान)। बहुत से भाई जो सामने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामशंकर रविवासी]

बैठे हुये हैं वे वह समझ रहे हैं कि हमें ही सारी जानकारी है और हम ही सब कुछ जानते हैं, दूसरा कुछ नहीं कह सकता। मेरी आवाज इस वक्त खराब है क्योंकि मेरी तबियत ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर किसी को तकलीफ है तो उस पर रहम कीजिये। शांति से उसे सुनिये।

श्री रामशंकर रविवासी—मेरी आवाज साफ नहीं है उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। लखनऊ में ही जितना कार्य हुआ है वही सराहनीय कार्य हुआ है ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारी सूबे भर में जो सार्वजनिक कार्य हुआ है सड़कों तथा इमारतों के बारे में वह सब सराहनीय है। उत्तर प्रदेश ने जितना कार्य सार्वजनिक निर्माण-कार्य में किया है उतना और किसी विभाग ने नहीं किया। यहां की सड़कों की हालत १५ साल पहले क्या थी? धूल उड़ा करती थी। एक भी सड़क ठीक नहीं थी लेकिन जब से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इधर ध्यान दिया है तब से हमारे प्रदेश की सड़कें बहुत सुन्दर व अच्छी हैं। मैं लखनऊ के देहाती क्षेत्र से चुन कर आया हूं। शहर में तो अवश्य बढ़िया सड़कें हैं लेकिन देहात की हालत बहुत खराब है। मेरा निवेदन है कि एक सड़क जो नगराम-निगोहां को मिलाती है वह महत्वपूर्ण है। और वहां की जनता की यह बहुत दिनों की मांग रही है कि नगराम से गंगानगर तक जो ८-१० मील का टुकड़ा है उस सड़क को अगर सरकार बनवा दे तो वह जनता और सरकार दोनों के लिये फायदेमन्द होगी। वह सड़क सुल्तानपुर—रायबरेली, कानपुर—उन्नाव, इन सड़कों को मिलाती है। वह बहुत ही सुन्दर स्थान है और वहां करीब दस हजार की आबादी है। वहां अस्पताल हैं, हाई स्कूल हैं और रोजगार के भी अच्छे साधन हैं, वहां चावल की पैदावार अच्छी होती है। इन सब बातों को देखते हुये उस सड़क का बनना बहुत जरूरी है।

लखनऊ इस प्रदेश की राजधानी है। इसे विदेशों और दूसरे प्रदेशों के बहुत से लोग देखने के लिये आते हैं। इसलिये सरकार को इसे बहुत सुन्दर ढंग से बनाना चाहिये। मैं मुखालिफत तो नहीं करता लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग का जहां अच्छा काम हुआ है वहां उसमें गलतियां भी हुई हैं। आज आये दिन बाढ़ आती है। यहां बड़े-बड़े मकान बनाये गये लेकिन पिछले दो साल से जो बराबर बाढ़ आती है तो हाय तोबा मचने लगती है। इस लखनऊ को ऊंचा उठाने की ओर अगर किसी ने ध्यान दिया है तो हमारे मुख्य मन्त्री जी ने....

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री प्रेमसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे समय दिया है और अब मैं अपना भाषण शुरू करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आशा है आप दो ही मिनट में खत्म कर देंगे।

श्री प्रेमसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० के क्या माने हैं? यह तो मैं समझ ही सकता हूं कि आप इतने अक्लमन्द हैं कि उसके माने जानते होंगे इसलिये मैं न बतलाऊं, लेकिन फिर सोचता हूं कि बतला ही दूं। पी० डब्ल्यू० डी० के माने हैं 'प्लन्डर विदाउट डेंजर"। यह तो मेरा अर्थ है, आप इससे कितना सहमत हैं यह मैं नहीं कह सकता। यही हो रहा है आज।

कुछ सदस्य—इसकी हिन्दी कीजिये।

श्री प्रेमसिंह—इसकी हिन्दी है गरीब का खून ऐसा चूसा जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है और बिना खतरे के। इस डिपार्टमेंट को मिनिस्टर लूटते हैं और सारे कर्मचारी लूटें, कोई खतरा नहीं है। इसका यह और खुलासा अर्थ है। इसका सबूत यह है कि

जब आप मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त आपकी माली हालत क्या थी और अब क्या है। बहरहाल, आपके ऊपर चोट नहीं है, सारे मिनिस्टरान के ऊपर है। इसी प्रकार आपके ओवरसियर और इंजीनियर्स जब नौकरी पर लगे थे उस समय उनकी माली हालत क्या थी और अब क्या है इसकी जांच होनी चाहिये। आज कैसी है, सदन को बताऊं। एक दफा इसी सदन में माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने क्या कहा था, पता है, उन्होंने कहा था कि इस सदन में सारे अफसरों की वह इंक्वायरी कमेटी बनायेंगे लेकिन वह इंक्वायरी आज तक नहीं बनी, इंक्वेन्ट्री बनाई जाय। अब पता नहीं, वह कहां बन रही है और कब बनेगी।

दूसरी बात श्रीमन्, आप इस विभाग में ११ साल से मन्त्री हैं। आपने क्या खास खास काम किये यह सदन को बतायें। मैं यह कह सकता हूं कि इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जितना किसी और विभाग में नहीं है और आप इस भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके इसको जल्दी से जल्दी खत्म कीजिये। मन्त्री जी ईमानदारी से बतायें कि आपका काम धाम अच्छा चल रहा है या बुरा। जब देखिये घर में तेल मालिश होती है। जब हम जाते हैं तो सुना जाता है कि तेल मालिश हो रही है। आपकी हो या न हो हमारी तो हो ही जाती है। आज गरीब जनता का खून चूसा जा रहा है। जमींदारों के लिये कहा जाता था कि वे गरीबों का खून चूसते हैं। लेकिन अब बताइये कौन गरीब जनता का खून चूसता है?

इधर सारे प्रदेश की सड़कों की हालत ऐसी हो गई है जैसी कि गर्भवती स्त्री उधर चली जाय तो मुमकिन है उसको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेशनल हाई वेज की सड़कें ऐसी अवस्था में हैं कि उनका जिक्र करना बेकार है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, इंटर स्टेट रोड्स के लिये क्या कहूं माशे अल्ला। आपकी सड़कें ऐसी हैं कि आज बनीं और कल टूटीं। यह क्यों हो रहा है? करप्शन होता है, सीमेंट खराब होती है या बालू ज्यादा मिला दी जाती है। यह मुझे नहीं मालूम हम आपके करीब ही रहते हैं तो कम से कम वह सड़क बनवा दीजिये जिससे हमें धूल न आये। यह सदन को बतायें कि ये पुल, इमारतें और सड़कें क्यों जल्दी टूट जाते हैं? मैं वजह बताऊं। जितना रुपया लगना चाहिये उनके ऊपर वह उन पर नहीं लगाया जाता है। वह जाता कहां है? मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूं क्योंकि अक्लमन्द को इशारा ही काफी होता है। खुलासा बता दूं। कांग्रेस का जो चुनाव फंड है उसमें और मन्त्री जी के चुनाव में चला जाता है वरना ठेकेदारों से काम क्यों कराते हैं? क्यों नहीं उनको खत्म कर देते? अगर मेरी बात सही नहीं है तो क्यों नहीं करप्ट आफिसर्स को निकाल देते? उनको खत्म कीजिये तो करप्शन भी खत्म हो जायगा। इसलिये रखे हुये हैं कि एक दूसरे को हक पानी पहुंचता रहे। मैं नहीं चाहता कि किसी की रोजी जाय लेकिन आटे में नमक के समान खायें। यह न हो जिसका मैं रिप्रेजेंटेटिव होकर आया हूं वहां जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा तो क्या कहूंगा? वे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं तो कहूंगा कि मैं उल्लू बन रहा हूं। इस समय सदन में लाल बिजली जल गई है। दोपहर को यहां सदन में जो बिजली जलती है उससे क्या अर्थ निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री प्रेमसिंह—इस विभाग में यदि श्री जगदीशप्रसाद चीफ इंजीनियर न होते तो सब कायापलट हो जाती। श्रीमन्, अभी तो जिन्दा हूं। जब समय समाप्त हो जायगा तो बात दूसरी है। नारायण।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। जैसे उद्योग है, हमारे छोटे बड़े उद्योग तभी पनप सकते हैं जबकि हमारे यहां यातायात के प्रचुर साधनों का निर्माण सम्पन्न हो तभी हमारे यहां की गरीबी दूर हो सकती है। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस विभाग के द्वारा बड़ी तरक्की हुई है। बहुत से पुल एवं भवनों का निर्माण हुआ, सड़कें बनायी गयीं। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो हमारा लक्ष्य रखा गया है यह भी उत्साहवर्द्धक है। इस योजना-काल के अन्दर हमारे यहां और भी कार्य होंगे।

मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, अपने जिला टेहरी-गढ़वाल के सम्बन्ध में यह कहना है कि हमारे यहां बहुत सी सड़कें बनी हैं यह मैं मानती हूं। लेकिन इस समय चीन से हमले का खतरा है। इसलिये हमारा जिला अन्य पर्वतीय जिलों की तरह अरक्षित-सा हो गया है। वहां पर द्रुतगति से सड़कों के निर्माण का काम होना चाहिये जिससे दो-दो मोटरें सड़क पर साथ-साथ निकल सकें। दूसरी बात मुझे यह भी कहनी है कि इस विभाग के कार्य जैसी तेजी से होने चाहियें उतनी तेजी से नहीं हो पा रहे हैं। हमारे मन्त्री महोदय को सड़क एवं पुलों का निर्माण द्रुतगति से करवाना चाहिये।

हमारे गढ़वाल में तीन-चार साल से बहुत सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं। उन दुर्घटनाओं के कारण स्थानीय लोगों को तो आने-जाने की असुविधा होती ही है, बाहर से जो यात्री वहां आते हैं उनको भी बड़ा कष्ट होता है, और इसका असर स्थानीय जनता की रोटी-रोजी पर पड़ता है, इन दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी निर्माण विभाग पर है। इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि इस विभाग का काम करने का तरीका बहुत सन्तोषप्रद नहीं है। अन्य विभागों में जैसी प्रगति हो रही है वैसी प्रगति इस विभाग के कर्मचारियों के कार्य में नहीं हुई है। इंजीनियर को अब काम की देख-रेख करने, सही नक्शे तैयार करने की फुर्सत नहीं रह गई है, उसका काम अब एक आफिस के बाबू जैसा हो गया है। जो अलाइनमेंट का काम है वह ओवरसियरों का न रहकर वर्क एजेन्ट का काम हो गया है। उससे हमारी सड़कों का अच्छे ढंग से अलाइनमेंट नहीं हो पाता। इससे खराब, कच्ची और ऊबड़-खाबड़ सड़कें बनती हैं। जिन पर दुर्घटनायें हो जाती हैं।

ठेकेदारों द्वारा जो कार्य होता है सभी को मालूम है कि वह मजबूत नहीं होता, मेरा प्रस्ताव है कि स्थान-स्थान पर एक ऐसी सहकारी समिति बनायी जाय जिसके द्वारा सार्वजनिक निर्माण का कार्य किया जाय, जिससे काम पक्के हों और टिकाऊ भी हों।

इसके अतिरिक्त हमारे यहां अभी तक लगभग सभी नदियों पर मुख्यतया मन्दाकिनी पर बावड़ के पुल लगे हैं जिसके कारण हर वर्ष बहुत से लोगों की जानें समाप्त होती हैं। उन झूलों के बजाय पक्के पुल बनने चाहिये। यह हमारा आग्रह रहा है, पर निर्माण विभाग खामोश बैठा है।

मुझे यह भी कहना है कि ठेकेदारों से काम ले लिया जाता है और काम पूरा होने के बाद बांड भराया जाता है। यह उनके साथ अन्याय है। समय पर उनसे बांड भराया जाना चाहिये और स्वीकृत टेंडर में जो देर हों उनके अनुसार भुगतान होना चाहिये, लेकिन आज मनमानी से बिल बनाया जाता है और ठेकेदार को भुगतान का बहुत-सा पैसा विभाग वालों को देना पड़ता है।

हमारे क्षेत्र में एक सड़क का जो अलाइनमेंट हुआ था वह घनसाली से भीरी तक था लेकिन अब उसका तिलवाड़ा तक अलाइनमेंट रखा गया है। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से आग्रह है कि जैसा पहले अलाइनमेंट हुआ था घनसाली से भीरी तक वही रखा जाय। क्यों

कि बदले हुये अलाइनमेंट के अनुसार चार-पांच पट्टियों के लोग बिलकुल अलग पड़ जाते हैं। इसलिये मेरा आग्रह है कि जो पहले अलाइनमेंट था उसके अनुसार सड़क को बनाया जाय।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सीमेंट वगैरह की पहाड़ पर बड़ी शिकायत है। हो सकता है और जगहों पर भी हो, लेकिन पहाड़ों पर इसके सम्बन्ध में यही शिकायत है कि काले बाजार में ठेकेदार लोग या अन्य लोग उसको ले जाकर बेच देते हैं जिससे कि निर्माण का काम ठीक से नहीं हो पाता है और निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारी इस बात को चाहते भी हैं क्योंकि उसमें उनको फायदा है। तो मैं नम्र निवेदन करती हूं कि जो सीमेंट वहां जाती है इंजीनियर लोग उसके सदुपयोग की देखरेख करें जिससे कि जिस काम के लिये वह आती है उसी काम में वह खर्च हो ताकि निर्माण कार्य ठीक ढंग से हो। मैं पुनः आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री कल्पनाथ सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है। समय भी कम है। सब से पहले तो मैं आपको बहुत अधिक धन्यवाद देता हूं कि आपने अनेक बार उठने बैठने के बाद मुझे समय दे दिया और वह भी इत्तफाक से।

पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में क्या कहूं? प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है, दूसरी पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो गई। तीसरी शुरू होने जा रही है लेकिन हमारे हाटा निर्वाचन क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बन पायी। एक सड़क जो बन रही है कैप्टेनगंज से हाटा तक वह मदरहा ग्राम तक अभी पहुंची है। सन् ४८ से वह सड़क बन रही है। मेरा ऐसा ख्याल है कि जब तक वह हाटा तक पहुंचेगी तब तक हाटा तक वह बिगड़कर भी ठीक हो जायगी क्योंकि दोनों काम साथ-साथ चालू हो गया है। राज्य मार्ग नम्बर २८ जो बना है इसकी भी हालत खराब ही है एक तरह से। पता नहीं कैसे बनती है कि मजदूर हमेशा तोड़ते-खोदते दिखाई देते हैं। जिस पुल का निर्माण होता है वह भी अच्छी तरह से नहीं बनते हैं। पुष्ट नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं। सीमेंट कहीं ठेकेदार बेच देता है, कहीं कोई उठा ले जाता है। एक अजीब तमाशा मचा हुआ है। मैंने एक मस्टर रोल भी पकड़ा है। इंजीनियर और ओवरसियर जो हैं वह लोग जो काम कराते हैं, उसमें फर्जी नाम भर कर के असली जो होता है उसको गायब कर देते हैं और दूसरा पेश करके पैसा बना लेते हैं और उसका बटवारा कर लेते हैं। पता नहीं, इंजीनियर, ओवरसियर, ठेकेदार कितने उसमें खाते हैं। एक तमाशा बना हुआ है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बाद सब से ज्यादा भ्रष्टाचार इसी मुहकमें में दिखाई पड़ता है, काम जो होता है वह मजबूत नहीं होता। मैंने देखा देवरिया में निगम नगर एक बना हुआ है। एक दिन मैं वहां खड़ा था, तब तक एक अलमारी टूटकर उसका सिरा नीचे गिरा। एक चपरासी को चोट आयी। इस इस तरह से मकानात बनते हैं, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं। सब की दशा दो तीन-साल बाद सोचनीय हो जाती है। जहां तक खर्चे का सवाल है खर्चा आप करें, टैक्स लगायें; लेकिन जिस तरह से समुद्र का पानी भाप बन कर फिर बादल बन जाता है और पहाड़ से टकराकर मानसून बनकर बारिश होती है जिससे कि किसान खुशहाल होता है और बाकी जो पानी होता है वह नदियों के जरिये बह कर फिर समुद्र में पहुंच जाता है, उसी तरह से टैक्स का मामला है। अनुदान आप मांग रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस टैक्स का अच्छी तरह से सदुपयोग हो जिससे जनता यह समझे कि हमारा काम हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है तो जनता को टैक्स देने में तकलीफ महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आपका विरोध होगा ही निश्चित रूप से।

[श्री बांकेलाल]

बर्ड घाट पर गोरखपुर में जो पुल बन रहा है उसमें तमाम पैसा बर्बाद हुआ। अन्त में एक पाया डेढ़ लाख का गिरकर बर्बाद हो गया। अब उसकी जांच हो रही है या क्या हो रहा है? कितना पैसा कौन रिश्वत ले रहा है, कितनी सीमेंट बिक गई, कितनी ईंट गायब हो गई? एक तमाशा मचा हुआ है। जब हम लोग कुछ कहने के लिए खड़े होते हैं तो कोई कहता है कि सूरज ही नहीं दीखता। अगर सूरज दिखाई नहीं देता है तो आप अपने क्षेत्र का रोना क्यों रोते हैं। जब आप जानते हैं कि सब जगह रोशनी ही रोशनी है तो फिर क्यों इस तरह से रोना रोते हैं और अन्धेरे की शिकायत करते हैं। अगर जरा सी संस्कृत पढ़ ली तो कह दिया कि सूरज ही नहीं दिखाई देता है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि उधर के सदस्य उन गलतियों को बतायें कि जहां उनको गड़बड़ी मालूम होती हो। अगर आप सरकार की गड़बड़ी को बताते हैं तो यह कांग्रेस सरकार और जिन्दा रह सकती है। जो गड़बड़ हो उसके लिये सरकार को सही सलाह दीजिये। अगर आप सही सलाह नहीं देंगे तो ज्यादा दिन तक आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। आज आप बहुमत में हैं जो बहुमत चाहेगा वही होगा और उसको ही अपने बहुमत से आप पास करा लेंगे, लेकिन जनता जो कहती है उसको भी आपको सुनना चाहिये। हम तो यह चाहते हैं कि यह पाप का घड़ा जल्दी से भर जाय और यह सरकार जल्दी से यहां से हटे। हम देखते हैं कि वह सब जल्दी से ही हो रहा है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने देख लिया कि कितना काम हुआ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी हम देख रहे हैं कि कितनी सड़कें बन रही हैं। हमारे यहां एक सड़क हाटा से में सही होते हुये पिपराइच तक जाती है, दूसरी सड़क पिपराइच से मंसूरगंज जाती है। तीसरी सड़क हाता से झांगा पैकाली होते हुये पिपराइच जाती है और चौथी सड़क पिपराइच से जगदीशपुर गोदरवार होते हुये कैप्टनगंज जाती है। इन सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को चलना मुश्किल है। लाखों रुपये के बैल हर साल मरते हैं। बरसात के दिनों में सारी सड़कें पानी से भर जाती हैं और उन दिनों पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। आपने जो ये योजना बनाई उससे उस इलाके को क्या लाभ हुआ? किसानों पर आप टैक्स लगाते हैं तो लगाइये लेकिन वह यह भी सोचते हैं कि अगर टैक्स देकर भी उनका लाभ नहीं होता है तो इस टैक्स से क्या लाभ होने वाला है, जिस टैक्स से उसको कोई लाभ नहीं होता है। उससे तो यही होगा कि ठेकेदार और इंजीनियर के महल बनेंगे। हमारे मंत्री महोदय तो रईस आदमी हैं उनको क्या कठिनाई हो सकती है। तो फिर जो टैक्स जनता पर आप लगायें उससे उस जनता का क्या लाभ होगा? अब जनता भी आपको समझ गई है:—

सीरत अगर बुरी है तो बेकार हुस्न है।
नजरों पर क्या चढ़ेगा जो दिल से उतर गया।।

हम तो यह समझते हैं कि सरकार हमारी नजरों से उतर गई है, लेकिन जनता की नजरों से भी सरकार उतर जायेगी। जब हमारी ही नजर से सरकार उतर गई तो फिर जनता की नजरों पर क्या चढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं कल्पनाथसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री गुप्तारसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि बहुत से सदस्यों की यह राय है कि इस अनुदान पर बहस के लिये सदन का समय १ घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अभी मैं एक सदस्य को बोलने के लिये बुला चुका हूं। उसके बाद आप कहियेगा।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

यों तो यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे शरीर के अन्दर रक्त का संचार करने वाली धमनियां होती हैं, अगर यह धमनियां बेकार हो जायं और अपना काम न करें तथा इस पर ध्यान न दिया जाय तो सारा शरीर सूख जाता है या लकवा हो जाने का डर रहता है । उसी प्रकार बिना सड़कों के निर्माण के विकास कार्य पंगु हो सकता है। हमारी सरकार ने नागपुर योजना को प्रतिपादित करने के लिये काफी प्रयत्न किया है। करीब-करीब लक्ष्य के नजदीक पहुंच चुके हैं। आज १४,४८४ मील लम्बी सड़कों का निर्माण कर चुके हैं। लेकिन हमारी सरकार शहरी एरिया को बैकुण्ठ बनाने में जितना संलग्न है उतना देहात की तरफ वह नहीं जाती। देहात पिछड़ा है, आप वहां पहुंच नहीं पाते और सरकारी कर्मचारी भी वहां तक अपनी कार ले जाने में विवश हैं। मेरे ख्याल में अगर देहात का इसी प्रकार तिरस्कार किया गया तो वहां का विकास, वहां का उत्पादन, सब ढेर हो जायगा। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। वह रायबरेली का अत्यन्त पिछड़ा हुआ एक देहाती क्षेत्र है। कानपुर और इलाहाबाद की सड़क अगर छोड़ दी जाय तो मेरे क्षेत्र में कुल ४–४ मील सड़क के दो टुकड़े हैं, और कहीं भी सड़क नहीं है। आप जानते हैं कि उस क्षेत्र के निवासियों ने १९४२ में और उसके पहले भी जो कुर्बानी और बलिदान किये हैं उनको इतिहास नहीं भूल सकता। सरेनी में १९४२ में गोली चली थी और ५ आदमी मारे गये थे तथा अनेकों घायल हुए थे। वहां जाने के लिये परिषद् की कृपा से एक नाले पर पुल का निर्माण तो हो गया है लेकिन सड़क नहीं बनी है। बेहटा से भोजपुर, जो कि महावीरप्रसाद जी द्विवेदी का जन्म स्थान है, तक सड़क का निर्माण हो जाना आवश्यक है। मेरा क्षेत्र गंगा जी के किनारे है। कानपुर से इलाहाबाद तक एक भी पुल गंगा पर नहीं है और हरिद्वार से गंगा सागर तक भिटौरा, जिला फतेहपुर और रालपुर, जिला रायबरेली जैसा संकरा गंगा का घाट कहीं भी नहीं है। वहां इस पार और उस पार के लोग खड़े होकर बात कर सकते हैं और दोनों ओर सड़कों का निर्माण हो चुका है और पक्के घाट बने हैं। बहुत थोड़ा रुपया खर्च करके यहां पर पीपों का पुल का निर्माण हो सकता है। अगर सरकार कृपा करे तभी यह कार्य हो सकता है और इससे बांदा, फतेहपुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, राबरेली आदि का जबरदस्त सम्बन्ध हो जायगा और लालगंज, जो एक बड़ी मंडी है, से उनका सम्बन्ध जुड़ जायगा, यह रायबरेली से बहुत करीब है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। एक सड़क पर १९४६ में मिट्टी पड़ी थी आज भी वह उसी दशा में है। यह सड़क गुरबक्सगंज से खिरौं-सरैनों होती हुई भोजपुर पहुंचती है। उस पर कंकड़ पड़ जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री काशीनाथ––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान पर इस आदरणीय सदन में जिस ढंग से बहस चल रही है, शायद उसी ढंग से यह विभाग भी काम करता है। जितने सदस्यों ने अपनी बात कही है शायद सभी ने अपने-अपने क्षेत्र में यहां पुल बने, वहां सड़क बने, इसी तरह की बात कही, लेकिन मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि किसी जनतांत्रिक राज्य में किसी भी विभाग को एक सुनिश्चित नीति के अनुसार काम करना होता है। इस विभाग की नीति क्या है, मैं जानना चाहता हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले में अभी पिछले दिनों एक सड़क बन रही थी एक माननीय सदस्य के क्षेत्र में। जब वह हार गये एलेक्शन में और उस क्षेत्र से दूसरे माननीय सदस्य चुने गये तो वह सड़क दूसरे सिरे से बनना शुरू हुई। श्रीमन्, किसी जनतांत्रिक राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम ठीक ढंग से होना चाहिये। इस बारे में उसकी दृष्टि समय के साथ बदलनी चाहिये। सब से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस प्रदेश की चारों कोनों पर, प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा की दृष्टि से आवागमन के साधन दुरुस्त होने चाहिये और इस दृष्टि से देखा जाय तो इस प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को छोड़कर उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्से आवागमन के सड़क, पुल आदि साधनों से बिल्कुल रहित हैं। पूरब में उत्तर प्रदेश

[श्री काशीनाथ]

बिहार को छूता है और जो गंगा और घाघरा से बिल्कुल अलग है, वहां पर किसी तरह के पुल नहीं हैं। कुचियारघाट पर जहां नावों के पुल से काम लिया जाता है वहां पुल की बहुत आवश्यकता है। सब से अधिक वह सड़क जो बक्सर से बलिया को मिलाती है, अगर औसत लगाया जाय आवागमन का तो श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश में उसका पहले नम्बर का स्थान होगा। उसी तरह से बिहार से जो सड़क उत्तर प्रदेश को मिलाती है जो बलिया में है उसका निर्माण नहीं हो पाया है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बुन्देलखंड और ग्वालियर के इलाके में भी कुछ नहीं हुआ है। यह हिस्सा बिल्कुल अछूता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रदेश के चारों हिस्से इसी तरह से हैं। उत्तरी इलाका भी पिछड़ा हुआ है।

इस विभाग को यह दृष्टि भी अपनानी चाहिये कि जो तीर्थ स्थान हैं या जो आम दिलचस्पी के स्थान हैं वहां भी आवागमन के साधन या डाक-बंगलों आदि का निर्माण किया जाय। जिस प्रकार से वे कर्मचारियों के लिये बनाते हैं, उसी प्रकार से चित्रकूट, सारनाथ आदि में आप उनका निर्माण करें तो उससे आम जनता को सुविधा मिल सकती है और जो जंजीर के पाखाने आप कम्यूनिटी डेवलपमेंट्स की तरफ से प्रदर्शित करते हैं अगर वे देहातों में बनाये जायं तो उससे लोगों को काफी सुविधा मिल सकती है।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा डाक बंगले अधिक खर्चीले बनाये जाते हैं। उनमें कटौती होनी चाहिये। उनमें राज्य का पैसा फिजूल-खर्ची में जाता है और जो उनका इन्तजाम करने का तरीका है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिये। वे बंगले सरकारी अफसरों के लिये या मंत्रियों के लिये सुरक्षित रहते हैं। यह नियमावली गलत है। उनको सर्वसाधारण के लिये, जो पैसा दे सके खोल दिया जाना चाहिये और उसमें ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

श्री काशीनाथ—दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस विभाग में जितने नौकर हैं, उन सब में घूंसखोरी की एक प्रथा चल रही है। उनका एक हिस्सा बंधा होता है। ठेकेदार ओवरसियर को देता है, ओवरसियर इंजीनियर को देता है, इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को देता है। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय विचाराधीन है वह बड़ा गम्भीर है और यह ऐसे विभाग से सम्बन्ध रखता है जिस पर हमारे देश का निर्माण निर्भर करता है। मैं अपने अनुभवी और योग्य मंत्री जी से यह जरूर कहूंगा कि मेरा तजुर्बा टेहरी जिले के बारे में यह रहा कि इस विभाग में नैतिकता की गिरावट काफी आ गई है और बहुत से आरोप इस विभाग पर इस जिले में लगाये जा रहे हैं। अभी हाल ही में कान्ट्रैक्टर्स और इस विभाग के बीच झगड़ा हुआ और कान्ट्रैक्टर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहां धरना दिया। उस अवसर पर हम भी समझौता कराने के लिये वहां पहुंच गये थे। उस समय जो जो बातें हमको कान्ट्रैक्टर्स से सुनने को मिलीं उनसे यही पता चलता है कि इस विभाग में काफी गड़बड़ी है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इसके लिये इन्क्वायरी करायें और अगर वे ऐसा करेंगे तो कुछ गम्भीर बातें वहां पायेंगे।

हम यह देखते हैं कि पहाड़ों पर जो स्ट्रेटेजिक जिले हैं वहां पर अच्छे एक्सपीरियेन्स्ड इंजीनियर्स नहीं भेजे जाते हैं जिसके कारण वहां काम अच्छी तरह से नहीं हो पाता । अगर वहां पर अनुभवी इंजीनियर्स जायें तो वहां काम भी अच्छा हो और झगड़ा भी न हो । आज अगर वहां पर तरक्की नहीं होती है तो उससे देश के लिये बड़ा खतरा पैदा हो सकता है । इसलिये इस तरफ माननीय मंत्री जी को अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

श्रीमन्, वहां पर जो पी० डब्ल्यू० डी० के गैंग्स हैं और उनमें जो लोग काम करते हैं उनको ४५ रुपया वेतन मिलता है जब कि कान्ट्रैक्टर लोग अपने लेबरर्स को ३ रुपया और ४ रुपया रोज तक देते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि आपको अच्छे आदमी काम के लिये नहीं मिल पाते हैं और जो मिलते हैं वे छोटी उम्र के होते हैं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप उन लोगों के वेतन को बढ़ायें ताकि अच्छे लोग आपको मिल सकें और सड़कों का काम अच्छी तरह हो सके । यह भी सुनने में आया है कि वे बच्चे एक घंटा या डेढ़ घंटा काम करते हैं और बाकी समय में आफिसरों तथा इंजीनियरों के घर पर उनका काम करते हैं । इसलिये यह जरूरी है कि उनका वेतन बढ़ाया जाय ताकि अच्छे आदमी मिल सकें ।

श्रीमन्, मुझे एक बात का अफसोस है कि जो सड़क बड़कोट-कालसी रोड बनी है उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ है । मैं आपको बताऊं कि रवाई जो वहां का इलाका है जहां राइस काफी पैदा होता है । वहां जौनपुर में आलू बहुत होता है । टीहरी से बड़कोट जो सड़क है वहां एक जगह करीब ६ महीने बर्फ रहती है और ३–४ महीने वह रास्ता बरसात में टूटा रहता है । उस सड़क से उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिये था । रवाई और जौनपुर की सहूलियत के लिये जो बड़कोट से सड़क अब ली गयी है, वह सड़क अगर जमुना की बाईं तरफ सारी बनायी गयी होती तो वह एक छोटी सड़क होती, उस पर कम खर्चा होता, और ऐसी जगह से जाती जहां पहाड़ आदि भी नहीं गिरते । मैंने इंजीनियर महोदय से भी पूछा कि आप उसको दूसरी तरफ से क्यों ले गये हैं, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कह सकते, हमने सड़क बना दी है । मैं यह भी कह दूं कि अगर बाईं तरफ सारी सड़क जाती तो वहां लाइम स्टोन भी काफी मिलता और उसको वहां से लाने में सुभीता होता ।

एक बड़ा गम्भीर आरोप मैंने वहां सुना है । आपके विभाग के लोग, जो पुल वगैरह बनाते हैं, और जो कान्ट्रैक्टर्स के जरिये बनवाते हैं, उनमें विभाग के कर्मचारी कान्ट्रैक्टर्स से मिलकर अपना शेयर भी रख लेते हैं । अगर यह बात ठीक है तो मैं समझता हूं कि यह गम्भीर विषय है इसमें गवर्नमेंट का काफी पैसा खर्च हो रहा है और जहां पर करोड़ों रुपये सरकार खर्च कर रही है, मैं चाहता हूं कि वहां हमारे योग्य मंत्री ज्यादा ध्यान दें । खुद आप जाकर इन्क्वायरी करें और जो गलती करे उस विभागीय कर्मचारी को सजा दें । यह हो सकता है कि मंत्री जी के दिमाग में यह हो कि चूंकि कांट्रैक्टर्स से झगड़ा हो गया है इसलिए वह झूठी शिकायत कर रहे हों, या ऐसी बातें कर रहे हों । मैं यह नहीं कहता कि उनकी सब बातों को सच ही माना जाय । इंक्वायरी हो और जो दोषी हो उसको दण्ड दिया जाय और जो झूठे आरोप लगावे उन पर मुकदमा चलाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––आपका समय समाप्त ।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)––व्यवस्था का सवाल है । श्रीमन्, मेरा चौथा नाम है कटमोशन देने वालों में । मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव का नोटिस देना क्या व्यर्थ है या जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार उठा बैठा, लेकिन मुझे अवसर नहीं दिया गया । मेरा कटमोशन यह था कि गढ़वाल में सार्वजनिक निर्माण में कार्य नहीं हो रहा है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—मैंने समझ लिया है, आप जरा सा सब्र कीजिये। आपको समय दूंगा।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश और प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग बहुत महत्वपूर्ण होता है, परन्तु इस विभाग को जितना रुपया दिया गया, जब हम देखते हैं कि उससे काम कितना हुआ तो बड़ी निराशा होती है। अधिकांश भाग उस रुपये का ओवरसियरों, इंजीनियरों और ठेकेदारों की जेब में गया। यह एक आम बात है और इसकी चर्चा हर जुबान पर है। परन्तु मंत्री महोदय इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। जब कि एक तरफ कर भार से लदी हुई जनता पर विकास के नाम पर कर भार बढ़ा कर उसका मेरुदण्ड तोड़ने के लिए तत्पर हैं तो क्या हमें यह अधिकार नहीं है कि हम पूछें कि उस पैसे का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है? उसका समुचित उत्तर नहीं दिया जाता तो हम निस्संकोच कह सकते हैं कि जिस तरह से ५ प्रतिशत हिस्सा ओवर-सीयर का होता है तो क्या मंत्री महोदय का भी उसमें उसी तरीके से हिस्सा होता है? अगर यह भ्रष्टाचार बन्द करना चाहें तो मैं नहीं समझ सकता कि वह बन्द नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार ऊपर से होता है। उसकी जड़ें वट-वृक्ष की जड़ों की भांति नीचे को चलती हैं। भवन निर्माण होते हैं और उद्घाटन होने के पूर्व ही टपकने लगते हैं, सड़कें बनने के बाद तुरन्त टूट जाती हैं और उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं। पुल बनते बनते टूट जाते हैं। आये दिन इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं, इसका क्या कारण है? क्या यह सत्य नहीं है कि सीमेंट की जगह राख लगायी जाती है? क्या जब कि जन-समुदाय को पता है तो मंत्री महोदय को नहीं है और अगर भ्रष्टाचार को बन्द करने की नीयत है तो वह बन्द क्यों नहीं हो पाता? एक भवन बनता है और मंत्री महोदय उद्घाटन के लिये पहुंचते हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि वह किस तरह का बना है और अगर खराबी हो तो जवाब तलब किया जाय, सम्बन्धित इंजीनियर और ओवरसियर से और उनको प्रासीक्यूट किया जाय। तभी भ्रष्टाचार बन्द हो सकता है।

जहां तक ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने का प्रश्न है, उसको खत्म किया जाय, लेकिन कोआपरेटिव सिस्टम लाने से भी कोई कल्याण होने वाला नहीं है, जब तक कि ऊपर से इस चीज को दुरुस्त नहीं किया जाता। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं जिला बिजनौर से, वह अफजलगढ़ जिले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उससे मंत्री महोदय भी सम्बन्ध रखते हैं। कल यहां एक प्रश्न पूछा गया था तो बतलाया गया कि स्टार ऐंड ग्रिड फारमूला के मातहत सड़कें बनायी जाती हैं। जब हम बिजनौर की सड़कों को देखते हैं तो पता नहीं चलता कि वह कौन सा फार्मूला है जिसके आधार पर सड़कों का निर्माण किया गया है।

जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह बहुत ही बैकवर्ड है। जिले के सारे बैकवर्ड एरियाज को काट काट कर उसमें मिला दिया गया है। उसकी सीमा एक ओर जिला सहारनपुर से मिलती है और दूसरी ओर जिला मुरादाबाद से, उसको लोग कालापानी कहते हैं। वहां पर सड़कों का अभाव है। जहां पर मंत्री जी के रिश्तेदारों का फार्म है वहां पर मंत्री जी ने सड़क बनवा दी और दूसरी सड़क वहां बनवा दी जहां पर उनकी ससुराल है। ये बातें वहां पर बच्चे-बच्चे की जबान पर हैं कि फार्म के लिये सड़क बनी। एक मर्तबे मंत्री जी की पत्नी मायके जा रही थीं तो रास्ते में मोटर फंस गई। उन्होंने कहा होगा तो सड़क बन गई। मैं यह नहीं कहता कि आप उनकी बातों को न मानें, क्योंकि होम गवर्नमेंट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जनता की तकलीफों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। जो सड़क केवल फार्म पर जाने के लिए बनाई गई रेहड़ से केहरीपुर को वह कासमपुर-गढ़ी से तिलोकपुर, कल्लूवाला होती हुई बनाई जाती तो कई गांवों की जनता को लाभ होता। इस क्षेत्र के लोग अपने मरीजों को सड़क के अभाव में उन स्थानों पर नहीं ले जा पाते, जहां डाक्टर उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार कई मौतें हो जाती हैं सड़कों के अभाव में। मैं मंत्री महोदय का ध्यान उन सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनके बनाने की शीघ्र आवश्यकता है। नजीबाबाद से जोगीरमपुरी जाने वाली सड़क कोटकादर तक बढ़ाई जाय। गढ़ी से कल्लूवाला तक सड़क बनायी जाय तथा अकबराबाद से किरतपुर तक।

नगीना-बढ़ापुर सड़क पर पांचवें से आंठवें मील तक कोलतार डाला जाय और नकटा तथा उननी के पुल बनाये जायं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का घोर विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करता हूं।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि पी० डब्ल्यू० डी० ने पीलीभीत को छोड़कर बाकी सारे सूबे में काफी तरक्की की है। पीलीभीत ही एक ऐसा बदनसीब जिला है जहां यातायात के कोई साधन नहीं हैं। खासतौर से पच्छिमी इलाके में कोई सड़क नहीं है। एक सड़क ऐसी है जो कि पीलीभीत से सितारगंज तक है और जहानाबाद से अमरिया तक पक्की बनी है, बाकी सारी की सारी कच्ची है। वहां पर कोई रेल भी नहीं है और न कोई दूसरा जरिया यातायात का है। इसलिये वहां पर इन्तहाई जरूरत पक्की सड़क की है। अगर यह सड़क सितारगंज तक बन गई तो नैनीताल, खटीमा, टनकपुर ये सारी जगहें मिल जायंगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इंसाफ को काम में लेते हुये इस क्षेत्र में सबसे पहली और सबसे आखिरी सड़क बनवाने की कृपा करें।

दूसरी बात यह है कि पीलीभीत में देवा नदी पर कोई पुल नहीं है, न पी० डब्ल्यू० डी० का और न सिंचाई विभाग का, सिर्फ एक रेलवे ब्रिज है जिसपर रेल आने के वास्ते काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां पर पी० डब्ल्यू० डी० का पुल बनवा दिया जाय। पूरनपुर और पीलीभीत के मिलाने का भी कोई साधन नहीं है, पीलीभीत जिला है और पूरनपुर पुरानी तहसील है। इसलिये जिले से तहसील तक सड़क बना दी जाय। खास तौर से वह सड़क आपको बनानी है जो जहानाबाद से सितारगंज को जाती है। यह बहुत बैकवार्ड इलाका है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, न रेल है और न कोई और जरिया है। अगर यह सड़क बन जायगी तो इस इलाके की हालत ही बदल जायगी।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव का अभिप्राय यह था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का ध्यान गढ़वाल जिले की जरूरतों की तरफ दिलाऊं। चुनाव के जमाने में जब मैं ४६ दिन तक रात-दिन चुनाव के सिलसिले में अपने क्षेत्र में फिरा तो मुझे मालूम हुआ कि इस क्षेत्र में यातायात के साधनों का कितना अभाव है। आज जो माननीय सदस्य इस विभाग में दिलचस्पी ले रहे हैं उससे मालूम होता है कि माननीय सदस्यों का इस ओर कितना ध्यान है। सभी लोग यह जानते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के जरिये देश की बड़ी सेवा हो सकती है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि दस वर्ष के लिये स्कूलों और कालेजों को बंद कर दिया जाय, और अस्पतालों को बंद कर दिया जाय। और उससे जो खर्चा बचे उससे पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को चलाया जाय, सड़कों को बनवाया जाय। लेकिन इस विभाग में जरूरत इस बात की है कि उसका निरीक्षण पूरी तरह से होना चाहिये। सड़कें मौजूद हैं लेकिन उनमें २-२, ३-३ फीट के गड्ढे हो रहे हैं।

श्रमदान से काम शुरू हो गया है, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया है। केन्द्रीय सरकार से उत्तराखंड के लिये बहुत सा रुपया मिलता है। लेकिन अफसोस है कि इस रुपये को खर्च करने में पक्षपात से काम लिया जाता है। मैंने पी० डब्ल्यू० डी० के आंकड़ों को देखा तो मुझे पता लगा कि टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल दोनों जिलों में ३३५ मील सड़कें सन् ४७ में थीं, जो अब ७३५ मील हो गयी हैं। लेकिन दूसरे पहाड़ी जिले (नैनीताल और अल्मोड़ा) में उसी अरसे में २५७ मील के स्थान पर १,०५८ मील सड़कें हो गयीं।

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

जो अनुदान कुमायूं डिवीजन के लिये दिया जाता है उसका तीन-चौथाई भाग अल्मोड़ा और नैनीताल पर खर्च कर दिया जाता है । उसका कारण यह है कि पहले जो मुख्य मंत्री थे वे अल्मोड़ा के रहने वाले थे, उनके इशारे को देखकर पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर ३/४ पया वहां खर्च कर देते थे । उसी तरह वर्तमान मुख्य मंत्री भी रानीखेत से प्रतिनिधि हैं इसलिये कुमायूं डिवीजन के लिये जो अनुदान है उसका तीन चौथाई रुपया अल्मोड़ा और नैनीताल में खर्च हो जाता है । इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार से जो ३ करोड़ रुपया उत्तराखंड डिवीजन से लिये मिला है उसका भी तीन-चौथाई रुपया अल्मोड़ा नैनीताल के जिलों पर खर्च हो जायगा । दोनों गढ़वाल में केवल चौथाई रुपया खर्च होता है । इस ओर खास तौर से मैं पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गढ़वाल को इस तरह अवहेलना न की जाय और आइन्दा गढ़वाल की सड़कों पर अनुदान खर्च किया जाय ।

हमारे यहां गढ़वाल में जो सड़क दुगड्डा से रतनाड़ाट तक ३१—३२ में बनाई गयी थी । वह दुगड्डा से रतनाड़ाट की सड़क जो ३५ मील की है वह अब तक कच्ची है, उसको ठीक मेटल्ड कराया जाय ताकि वह १२ महीने चालू रहे । उस पर न आपको पुल बनवाना है और न पहाड़ ही काटना है । इस वक्त वह सड़क साल भर में केवल तीन चार महीने चालू रहती है । बाकी समय में वह बंद रहती है इसी प्रकार से बोरीखाल से बैजरो को मोटर सड़क श्रमदान से शुरू हुयी थी, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा रहा है । इसी तरह से लैंसडाउन से रिखणीखाल तक जाने वाली सड़क श्रमदान से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई, वैसी ही पड़ी हुई है । एक सड़क जो सतपुड़ी से पोढ़ी बानघाट होकर जाती है उस पर बानघाट में पुल बनने की बहुत आवश्यकता है । अस्थायी पुल बनाने में हर साल १२ हजार रुपया खर्च होता है । अगर स्थायी पुल बनवा दिया होता तो अब तक जो रुपया लग चुका है इतने खर्च में पक्का पुल बन गया होता । नयार नदी में अभी ६ औरतें डूब कर मर गयीं, मार्च के महीने में । पुल न होने के कारण वे उसमें डूब गयीं । एक एक दिन में कई कई बार उसको पार करना पड़ता है और उसे पार करने के लिये १०—१५ मील तक नयार नदी पर कोई पुल नहीं है । इसलिये वहां इतनी मौतें होती हैं । आपका ध्यान सिर्फ एक-दो केस की ओर ले जाया गया लेकिन ऐसे सैकड़ों केस हैं कि नयार नदी पर पुल न होने की वजह से कई मर्द या स्त्री व पुरुष डूब मरे । इसलिये मेरा कहना यह है कि लैंसडाउन के सारे क्षेत्र में माननीय मंत्री जी को जाकर देखना चाहिये । मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० का कोई मंत्री तब तक नियुक्त न किया जाय जब तक कि वह मेरे लैंसडाउन क्षेत्र से या गढ़वाल क्षेत्र से खड़ा न हो । क्योंकि तब माननीय मंत्री महोदय को मालूम होगा कि वहां यातायात की कितनी दिक्कतें हैं । इसीलिये यह कहते हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गढ़वाल के तीन पासों (दर्रों) की तरफ दिलाना चाहता हूं—नीति पास, माना पास और नीलम पास । अगर माननीय मंत्री जी ने टेहरी-गढ़वाल व मेरे गढ़वाल की कोई परवाह नहीं की तो चीन के लिये सब से नजदीकी रास्ते यही होंगे । और चीन को पहले ही नहीं रोका गया तो फिर उसे हम इधर आने से नहीं रोक सकेंगे । जैसा कि एक बार एक मंत्री ने कहा था कि हम पहाड़ी क्षेत्र के लोग चीन को इधर नहीं बढ़ने देंगे, वे ऐसा करने में असमर्थ होंगे । जब तक कि पहाड़ी जनता में यह विश्वास न पैदा करें कि हमारी सरकार हमारी सेवा करने के लिये, हमारी यातायात के लिये मोटर सड़कों व स्थानीय सड़क व पुल का निर्माण करने को तैयार है ।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान मिर्जापुर जिले के पहाड़ी स्थानों की ओर दिलाना चाहता हूं । मिर्जापुर जिले की राबर्ट्स-गंज तहसील में ५० मील अन्दर तक कोई सड़क नहीं है । वहां सैकड़ों मील में जंगल व

पहाड़ फैला हुआ है । सदन के सामने बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में बहुत सी बातें कहीं । हमारा वह क्षेत्र है जो १०० मील पूरब पश्चिम और लगभग ५०–५५ मील उत्तर दक्षिण घोर जंगल व पहाड़ों से भरा पड़ा है । उस स्थान पर आज तक यातायात के लिये कोई भी सड़क नहीं बनायी गयी । उस पहाड़ी क्षेत्र के लोग जानते तक नहीं कि सड़कें कैसी होती हैं । मेरे क्षेत्र में ५० मील दूर चल कर, कहीं-कहीं १२५ मील दूर चल कर तब कहीं रोडवेज की गाड़ी मिलती है । ५० मील दूर चल कर लोग तहसील के सदर स्थान पर पहुंचते हैं और इस तरह से लोगों को वहां पहुंचने में दो तीन दिन से ज्यादा लग जाता है । अधिकतर बरसात के दिनों में तो वे पहुंच भी नहीं पाते और इस तरह से बहुतों के मुकदमे खारिज हो जाया करते हैं ।

इसलिये मैं यह चाहता हूं कि राबर्ट्सगंज से खलियारी होते हुए सुअरसोत वाया पन्नूगंज को एक सड़क निकाली जाय, राबर्ट्सगंज से घोराबल को एक सड़क निकाली जाय, राबर्ट्सगंज से भरहारी वाया कौडियाघाट से कोट को एक सड़क निकाली जाय । जिन सड़कों का मैंने नाम लिया है अगर वे सड़कें बन जायें तो उनसे इस देश व प्रदेश की बड़ी भलाई होगी । एक सड़क रिहन्द पर बन जाने से हमारे प्रदेश को इतना लाभ हुआ कि वहां कोयले की खान कोट में निकल आयी, रिहन्द डैम में बिजली व अलमुनियम की फैक्टरी बन गयी और तमाम चीजें वहां निकल रही हैं, इसमें तमाम स्थान आज घोर जंगल व पहाड़ों से घिरे हुए हैं, जिससे कोई भी आदमी वहां तक पहुंच नहीं सकता । अगर आवागमन के साधन हो जायं तो मेरा खयाल है कि वहां बहुत से नये-नये कारखाने लग जायेंगे व उन इलाकों से बहुत से सामान भी प्राप्त हो सकेंगे । उस इलाके में अधिकतर पहाड़ी व आदिवासी ही बसे हुए हैं जो जानते तक नहीं कि सड़कें क्या हैं, वे आज कहते हैं कि स्वराज्य हुआ तो हमें क्या मिला, "हमरे लिये तो एको सड़को नहीं बा" । इस तरह से सब बोलते हैं । तो कम से कम उस इलाके में इन सड़कों को बनवा दिया जाय ताकि लोगों के दिल में भी विश्वास पैदा किया जा सके कि हमारी सरकार से हमें भी फायदा है । इन सड़कों से तमाम प्रदेश का लाभ होगा, राबर्ट्सगंज और चुर्क को मिलाने से बहुत लाभ होगा और बड़ी-बड़ी खानों का पता लग सकेगा । मैं प्रार्थना करूंगा कि राबर्ट्सगंज से पन्नूगंज भरारी और खिलियारी को व कोराब लटभरती सड़क बनाई जाय । यह सड़क पहले कभी अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी लेकिन अब तो वह केवल नदी नालों की ही सड़क रह गई है और उस पर चलना मुश्किल है और लोग केवल एक पगडंडी से ही उस पर चलते हैं । मैं चाहता हूं कि इसको किसी तरह से मरम्मत कराई जाय । बस मुझे यही कहना था, मैं मंत्री जी के अनुदान का समर्थन कर के अब बैठता हूं ।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कल्पनाथसिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कुछ दिन पहले जब मद्रास में माननीय राजगोपालाचारी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि देश के शत्रु नम्बर एक तो कम्युनिस्ट हैं और शत्रु नम्बर दो सार्वजनिक निर्माण विभाग । पत्रकारों के पूछने पर यही बतलाया कि समय आने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग शत्रु नंबर एक का भी स्थान ले सकता है, लेकिन आज वह दिन आ गया है कि शत्रु नंबर एक का स्थान अब सार्वजनिक निर्माण को दे देना चाहिये । जिस प्रदेश के एक नेता को प्रधान मंत्री का पद सुशोभित करने का अवसर प्राप्त हो और केन्द्र में अनेकानेक मंत्री हों, उस प्रदेश में मैं कुछ तीसरी योजना पेश करना चाहता हूं । मैं सड़कों के मामले में अन्य देशों के प्रति १०० वर्ग मील के हिसाब से आंकड़े देना चाहता हूं । बंगाल में १६·७१, मद्रास ३०·२६, आंध्र १३·६८, मैसूर १५·४९, और यू० पी० १२·८० । इस तरह से इस दिशा में हमारा प्रदेश इतना बड़ा होने पर भी सबसे पिछड़ा है ।

[श्री कैलाश]

मैं तो एक ऐसे अभागे जिले के एक क्षेत्र से आया हूं कि जहां पर एक मील भी पक्की सड़क नहीं है । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर २ चीनी मिलें हैं । सब जगह चीनी मिलें अभी तक इसलिये चालू रहती हैं कि उनको गन्ना पेरने को बहुत होता है लेकिन हमारे यहां भटनी मिल को गन्ना नहीं मिलता वह इसी कारण से जल्दी बन्द हो जाती है कि उसमें गन्ना लाने के लिये एक इंच भी पक्की सड़क नहीं है । वहां पर मोटर भी नहीं चल सकती और इस वास्ते लोग गन्ना लाने के लिये तैयार नहीं होते ।

इसके अलावा हमारे यहां एक नरावर घाट का पुल है । सब जगह पुल के नीचे से पानी बहता है लेकिन यहां पुल के ऊपर से पानी बहता है । यह स्थान जैसे कि कहावत है 'अवशी देखिये देखन जोगू' । जिनको देखने का सदन के अनेक नेताओं को सौभाग्य प्राप्त है अभी-अभी मुख्य मंत्री भाटपार क्षेत्र में मदनमोहन मालवीय विद्यालय में स्वर्गीय मालवीय जी की मूर्ति अनावरण करने गये थे मंत्री जी वहां गये थे भाटपार के क्षेत्र में वह एक तथ्य है उस पर कोई आवरण नहीं डाल सकता । उस इलाके में खुरुआ पर २ रेगुलेटर लगे हैं और सरयां और धर्म-कोरकरा ग्रामों में आप देखें कि ऊपर से पानी बहता है । वहां इस विभाग का जो कुछ काम होता है वह नाममात्र का होता है, जो काम होता है बस सीमेंट में बालू ही बालू रहता है । वह क्षेत्र ऐसा है जो बिहार की सीमा से मिला हुआ है लेकिन माननीय मंत्री जी आज भी वहां के लोगों को स्वराज्य का लाभ नहीं देना चाहते हैं । अगर वह उसके लिये कुछ नहीं कर सकते तो अच्छा है कि वह उस क्षेत्र को अपने यहां से निकाल कर बिहार से मिला दें । उसी क्षेत्र से मिले क्षेत्र में बिहार में तो पक्की सड़क हैं लेकिन हमारे यहां एक इंच भी पक्की सड़क नहीं है । चुनाव के दौरान में वहां हमारे मंत्री श्री चरण सिंह जी गये थे और उनको वहां ४ मील जाने में २ घंटे का समय लगा था । आज दुर्भाग्य से वह यहां नहीं हैं, वहां की हालत वह मंत्री जी ही बता देंगे । उस क्षेत्र में नलकूप का या कोई भी काम नहीं हो सका है । वहां के लोग समझते हैं, वह क्षेत्र बरसात में एक टापू बन जाता है । नमक तक लेने के लिये आसपास के बाजार में लोग नहीं जा पाते । यह हालत है उस क्षेत्र की ।

मेरे क्षेत्र में भटनी में नदी का पुल बनने के लिये माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य आश्वासन दे आये थे कि यहां पुल जरूर बनेगा । लेकिन भटनी के बजाय कुछ कहने में यह मालूम होता है कि गोठनी हो गया । लेकिन आज तक उसका भी नम्बर नहीं आया । ३, ४ सड़कें ऐसी हैं अगर उनको बिहार से मिला दिया जाय तो वहां के लोगों को काफी सुविधा मिल जाय जैसे भटनी से लछमीपुर बाजार, भटनी से घाटी होते हुये भिंगारी बाजार, भाटपार रानी से भिंगारी होते हुए रामपुर मिल, भाटपार-सोहनपार होते हुए रामपुर मिल, रामपुर मिल से बंगरा बाजार होते हुए पकड़ी ग्राम, भाटपारा से बढ़ियारीबघेल-सोहनपुर होते हुए रामपुर मिल । अगर यह सड़कें बन जायं तो भटनी मिल को गन्ना मिलेगा । और जो जिले में १४ मिलें हैं उनसे सरकार, केन्द्रीय और प्रान्तीय जो ४ करोड़ रुपये के करीब ऐक्साइज और केन से के रूप में लेती है उसका कुछ अंश वहां भी खर्च होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया ।

***श्री इन्द्रासन** (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, जो अनुदान मंत्री जी ने पेश की हैं उनका मैं समर्थन करता हूं । विरोधी पक्ष के कई सदस्यों ने यह दोष लगाया कि इस विभाग में ज्यादा करप्शन है । तो इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वे सदस्य यह नहीं बताते कि इसको दूर करने के क्या उपाय हैं । यह जिम्मेदारी केवल सरकारी पक्ष के लोगों की ही, ऐसी बात नहीं है । यह जिम्मेदारी उन पर उतनी ही है जितनी सरकारी पक्ष पर ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ से गोरखपुर जो सड़क जाती है उस पर दोहरीघाट पर एक पुल बनने की स्कीम दूसरी योजना में थी। लेकिन वह पुल अब तक नहीं बना जब कि घाघरा नदी पर चौका घाट से लेकर लार रोड तक कोई पुल नहीं है और अगर है भी तो पोपों का पुल होगा जो सुरक्षा और प्रशासन की दृष्टि से उतनी उपयोगिता नहीं रखता जितना कि पक्का पुल। इसलिये दोहरीघाट का यह पुल सुरक्षा, प्रशासन और जनहित की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जो बनना चाहिये, यह मेरा मंत्री जी से अनुरोध है। आजमगढ़ से एक सड़क बिलरियागंज होते हुये रौनापार के उस थाने तक जाती है जो गोरखपुर से मिला हुआ है। घाघरा नदी तक कच्चा है। घाघरा नदी के उस पार बासगांव तहसील पड़ती है और इधर सगड़ी तहसील है। जनता का आना जाना उसी सड़क से होता है। वहां के लोगों ने काफी लिखा-पढ़ी की रोडवेज को बस चलाने के लिये लेकिन जवाब यह मिलता है कि इस सड़क पर कोई ड्राइवर बस चलाने के लिये तैयार नहीं होता है। उस सड़क के संबंध में मेरा निवेदन यह है कि वह एरिया उस जिले का बहुत पिछड़ा हुआ है, उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात यह कहनी है कि महाराजगंज डुमरियागंज होते हुये जो सड़क घोसी और बलिया को जाती है वह सड़क कम से कम ४० मील लम्बी है उसे मंत्री महोदय अपने विभाग में ले कर ठीक कराने का प्रयत्न करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जहां तक संबंध है मैं सुबह से पूर्व वक्ताओं का भाषण सुन रहा था। सभी लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार प्रकट किये। लेकिन मुझे आशा नहीं है कि उन समस्याओं पर मंत्री महोदय विचार करेंगे चूंकि इस विभाग में जितना करप्शन है उतना शायद ही दूसरे किसी विभाग में हो। उनके लिये जितने पुराने कार्य हैं उनका ही पूरा करना मुश्किल हो रहा है। एक सड़क ठीक नहीं हो पाती कि दूसरी सड़क खराब हो जाती है। उसका कारण यह है कि इंजीनियर, ओवरसियर आदि का परसेंटेज फिक्स्ड है। ठेकेदार लोग खुद इस बात को चाहते हैं। उन्होंने कमीशन दिया और कच्चा कंकड़ पीस दिया, सीमेंट में ज्यादा रेत मिला दिया। जब तक यह करेप्शन रहेगा तब तक यह विभाग ठीक तरह से कार्य नहीं कर सकता।

क्षेत्रीय समस्याओं का जहां तक संबंध है मजबूर हो कर मुझे उस क्षेत्र की समस्याओं को मंत्री महोदय के सामने रखना पड़ रहा है यद्यपि मुझे आशा नहीं है कि उन पर कोई कार्यवाही हो सकेगी। जो कुछ तरक्की हुई है वह उन्हीं क्षेत्रों की हुई है जहां के मंत्री हैं, उपमंत्री हैं या कोई प्रमुख आदमी है। मुझ जैसे विधायक के क्षेत्र पर गौर करना बहुत मुश्किल बात है।

जसराना क्षेत्र जिला मैनपुरी में घिरौर से एकाफरिया एक सड़क आती है जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है उस पर करीब-करीब बीसियों साल से ट्रेफिक चल रहा है लेकिन हालत उसकी आज तक इतनी खराब है जिसे देख कर मन्त्री महोदय अन्दाज लगायेंगे कि वहां का काम कैसे चल रहा है? उसके ऊपर कई दफा यह विचार हो चुका है कि उसे पी० डब्ल्यू० डी० में ले लिया जाय। उस सड़क पर एक मेला भी लगता है। लेकिन आज तक उसे पी० डब्ल्यू० डी० में ट्रांसफर नहीं किया गया। उसका कारण यह था कि उस क्षेत्र से ठीक व्यक्ति चुन कर नहीं आया। उस क्षेत्र से बाहर का ही व्यक्ति चुना जाता रहा है।

एक सदस्य—श्री रामस्वरूप यादव वहां से चुन कर आये थे।

श्री बलवीरसिंह—वह दूसरे क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्हें हमारे क्षेत्र से कोई हमदर्दी नहीं थी और उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई कार्य करके नहीं दिखाया। इसी तरह से कोटला फरिया सड़क पर तीन मील का टुकड़ा है जिसको पक्का करने से हदबन्दी मिल जाती है। और एक सड़क शिकोहाबाद से मुस्तफाबाद जो काफी समय से बोर्ड की कच्ची सड़क है, उस पर मील के पत्थर आदि भी गड़े हुये हैं, उसे पक्का कराया जाय। आगरा से जसराना के लिये सीधी सड़क हो जाती है सिर्फ तीन मील के टुकड़े के मिलाने से। दूसरी मुस्तफाबाद आवागढ़ सड़क है जो श्रमदान के द्वारा काफी चौड़ी और मजबूत बना दी गई है लेकिन आज तक उसकी दोबारा मरम्मत नहीं हुई। आवागढ़ के पास जो क्षेत्र मैनपुरी जिले का है वहां के लोगों को बड़ी परेशानी है। उन्हें मैनपुरी या जसराना तहसील में आने के लिये एटा हो कर आना पड़ता है। इसलिये या तो उस क्षेत्र को काट कर एटा जिले में मिला दिया जाय या उस सड़क को जल्द से जल्द पक्की कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री रामपालसिंह** (जिला मुरादाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विषय पर मैं कुछ चर्चा करूं उससे पहले आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान मैं दो चीजों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो खोया हुआ आत्मसम्मान वापस आये और दूसरा देश मालदार हो। पहला उद्देश्य तो पूरा हुआ किन्तु दूसरा अभी तक नहीं। स्वतन्त्रता की लड़ाई में सब की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ लोगों के ही प्रयत्न से देश स्वतन्त्र हो गया। किन्तु आज जब कि हम गरीबी के खिलाफ युद्ध छेड़े हुये हैं तो कुछ के चलाये से काम नहीं चल सकेगा। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि जो कुछ हम करते हैं वही सही है और जो दूसरे करते हैं वह गलत है। हम प्रदेश की समस्याओं को मिलजुल कर ढूंढें और संयुक्त ज्ञान द्वारा उनका हल निकालें। प्रदेश का भाग्य हमारे हाथों में है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं। हमें त्याग की भावना से काम करना चाहिये। संसार अपने स्थान पर है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जो इतिहास बना जाते हैं। आप में और हम में भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं त्याग की भावनायें हम सब में होनी चाहिये। इसी पर जनतन्त्र की बुनियाद है। आज हमारा गरीबी के विरुद्ध युद्ध छिड़ा हुआ है। यहां के रहने वालों की जो मूलभूत समस्यायें हैं, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, और मकान और आने जाने के साधन इनको पूरे प्रदेश को सोचना पड़ेगा और मिलजुल कर तेजी के साथ कदम उठाना पड़ेगा।

आज के विषय में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर कुछ शब्द कह कर दिलाना चाहता हूं। मैं लम्बे चौड़े भाषण तो पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि उत्तेजनापूर्ण भाषण देश की तरक्की में कोई सहायक नहीं होते। हमारे ठोस विचार, ठोस सुझाव, ठोस संशोधन जो ठंडे दिल व दिमाग से विचार करके यहां रखे जाते हैं वे देश और प्रदेश की उन्नति के लिये ज्यादा हितकर होंगे। यातायात या देश में जिस ओर भी ध्यान दिया जाय, स्वतंत्रता के बाद हम आगे बढ़े हैं और काफी आगे बढ़े हैं, इसमें मेरे खयाल से दो रायें नहीं होनी चाहिये। किन्तु अभी जो हमारा लक्ष्य है वह बहुत दूर है। उस लक्ष्य को पाने के लिये हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है। एक दूसरे की नुक्ताचीनी हम आपस में करते रहें तो यह कुछ भला प्रतीत नहीं होता। यातायात के विषय में भी हम काफी आगे बढ़े हैं। काफी सड़कें स्वतन्त्रता के बाद देश और प्रदेश में बन चुकी हैं। बहुत से पुलों का निर्माण हुआ, बहुत सी पुलियां तैयार हुई, बड़े-बड़े काम हुये। जैसे मुरादाबाद से देहली जो सड़क जाती है वहां पर एक काफी लम्बा चौड़ा गंगा का पुल बना है। मगर मैं थोड़ा ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो भी निर्माण के कार्य हों उनका अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाय ताकि हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी भी सदस्य को या जनता के किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहने का मौका न मिले। निरीक्षण की कमी के कारण भ्रष्टाचार होता है। मैं जिस कांस्टीटुऐंसी से आता हूं उसे मुरादाबाद का काला पानी कहा जाता था। किन्तु आज उसमें आने-जाने के साधन हो गये हैं। दो पुल जो ढोला नदी के ऊपर काशीपुर के नजदीक हैं उस पर काम चल रहा है और आने जाने का रास्ता रुका हुआ है। इसलिये जो काम हो वह ठीक से होना चाहिये। हमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा चाहे ठेकेदार हों या सरकारी कर्मचारी हों। हम बराबर भ्रष्टाचार की बात कहते चले जांय यह भला प्रतीत नहीं होता। यह हमारी गुलामी की बात है, हम काफी दिनों से गुलाम रहे हैं इसलिये अपने स्वार्थ के सामने देश का स्वार्थ दब गया है। धीरे-धीरे यह चीज दूर होती चली जायगी और जब देश का स्वार्थ पहले आ जायगा तो सब बातें दूर हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के संबंध में वक्तव्य

***विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने एक विशेष वक्तव्य देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के विकास के लिये तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत गोरखपुर में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान योजना के अनुसार यह कालेज इंजीनियरिंग की एक डिग्री संस्था होगी। यह गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित एक राजकीय संस्था होगी जिसमें प्रति वर्ष १२० छात्र भर्ती होंगे, ३० सिविल में, ४५ इलैक्ट्रिकल में तथा ४५ मिकेनिकल में। तृतीय पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में इस कालेज पर ५१ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। मार्च, १९६२ के अनुपूरक अनुदानों के द्वारा सदन की इस कालेज की स्थापना के लिये स्वीकृति ली गई थी। कालेज को आगामी शैक्षिक सत्र से खोलने का यथा सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

कालेज के एक सरकारी संस्था होने से राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न नियम तथा विनियम इस पर लागू होंगे। इसके कारण कालेज के चलाने में और खास तौर पर कर्मचारियों की नियुक्ति तथा दिन प्रति दिन के कार्यों को सम्पन्न करने में आवश्यक प्रक्रियात्मक विलम्ब होगा। इसका नतीजा यह होगा कि कालेज की उत्तरोत्तर वृद्धि उस गति से न हो पायगी जिस प्रगति से हाल में स्थापित देश में रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों की हो रही है क्योंकि रीजनल इंजीनियरिंग कालेज स्वायत्त संस्थायें हैं और उनके प्रशासन तथा प्रबन्ध के लिये बोर्ड आफ गवर्नर्स हैं जिन्हें पूरे अधिकार प्रदत्त किये गये हैं।

चूंकि सरकार गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र करना चाहती है इसलिये वह इस कालेज को वही स्वायत्त अधिकार प्रदान करना चाहती है जो रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों को दिये गये हैं जिससे कि इसकी स्थापना तथा विकास अधिकतम प्रगति से हो सके और इसके दैनिककार्यों में प्रक्रियात्मक विलम्ब न हो। इस उद्देश्य से सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अन्तर्गत एक सोसाइटी स्थापित करने का विचार है जिसका नाम गोरखपुर इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी होगा। इसके अन्तर्गत एक बोर्ड आफ गवर्नर्स होगा जिसे कालेज के प्रशासन तथा प्रबन्ध के लिये उपयुक्त अधिकार प्रदत्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

होंगे। सोसाइटी के मेमोरेंडम आफ असोसियेशन में इस बात का भी उल्लेख होगा कि यदि कालेज का कार्य सुचारु रूप से नहीं चलता है तो सरकार को उसके प्रशासन और सम्पत्ति को ले लेने का अधिकार होगा।

हमारा यह प्रयत्न है कि इस साल जुलाई में यह कालेज प्रारम्भ होगा।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३७—संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत (क्रमागत)

श्री कल्पनार्थसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोगों की बातों को इत्मीनान से सुनने की कोशिश की। श्रीमन, जहां तक मैं समझता हूं कि एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने मन्त्री जी की मांग का खुले दिल से समर्थन किया हो। यह दूसरी बात है कि उस पक्ष में रहने के नाते किसी आदमी ने यह कह दिया हो कि मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जो चार्जेज मैंने लगाये हैं, या इधर से लगाये गये हैं, उसी तरह के ऐलीगेशन्स उस तरफ से भी किये गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी के मुहकमे के ऊपर पूरे सदन का अविश्वास सा हो गया है। एक भी आदमी इस सदन का इस मुहकमे के पक्ष में नहीं है। बहुत से उधर के बैठने वालों ने मेरी बातों का समर्थन किया है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि मन्त्री जी इस बात को चाहे यह वैधानिक हो या न हो लेकिन इसको अविश्वास समझें ही कि सारे सदस्य मन्त्री जी और उनके मुकहमे पर अविश्वास कर रहे हैं। इसलिये मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था।

हां, लोगों ने कुछ बातें कहीं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि डिफरेंसेज हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में इसलिये उनके परमानेंसी के सवाल पर थोड़ा अन्तर हो सकता है। यह मैंने माना कि इस तरह के डिफरेंसेज हैं। इस सिलसिले में मैं इसी विभाग की पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट के पैरा ५, पेज ३९ का हवाला देना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि मेंटिनेंस लगातार चलने वाला कार्य है। अतः सड़क व पुल भवनों की देखभाल का कार्य करने वाले कर्मचारियों को वर्क चार्ज के आधार पर रखना न्यायपूर्ण नहीं है।

दूसरी एक चीज और माननीय सदस्य गौर फरमायें कि इस विभाग के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अन्य राज्यों में क्या है। केरल में न्यूनतम वेतन ६७ रुपये है, मद्रास में ६०, महाराष्ट्र में ७० और मध्यप्रदेश में ६५ है जब कि उत्तर प्रदेश में ३०, ३५, ४०, ५२ है। श्रीमन, जरा गौर करने की बात है। दूसरे प्रदेशों में कर्मचारी इसलिये लगन से काम करते हैं कि उनको कुछ सुविधायें हैं, उनकी परमानेंसी के बारे में वेतन के बारे में। बंगाल में ८० परसेंट स्टाफ परमानेंट है। मद्रास में ७५ परसेंट परमानेंट है लेकिन इस सूबे में महज १४ परसेंट स्टाफ परमानेंट है। यह हालत है इस सूबे में पी० डब्ल्यू० डी० की। यही नहीं जो इस सरकार के दूसरे इंजीनियरिंग विभाग हैं उनमें परमानेंसी का परसेन्टेज ३० है, जबकि इस विभाग में इतना कम है।

असिस्टेन्ट इंजीनियर्स के लिये यह भी एक बाधा हो गई है कि जो पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस साल से काम कर रहे हैं, ए० बी० कैटेगरी के हैं, कल का लड़का जो निकल कर आयेगा, उसके मुकाबले में उनको इम्तहान देना पड़ेगा तब फिर उसके ऊपर विचार होगा। कहां से इफीशेंसी आयेगी। २४ घंटे वह इसी फिक्र में रहेगा कि किस जरिये से मिनिस्टर साहब के पास पहुंचा जाय।

आखिर मन्त्री जी का यह मुहकमा है, इसमें ७ करोड़ रुपये का प्रोग्राम बिल्डिंग के लिये बना। इसमें अगर सीधे तौर पर हिसाब लगाया जाय तो ५ हजार वैगन कोयले की जरूरत पड़ेगी उस काम को पूरा करने के लिये। कह सकेंगे मन्त्री जी कि कहां से वह कोयला आयेगा? नतीजा यह होगा कि अनुदान मांगा जायगा इस हाउस में बैठकर और वह खर्च भी नहीं होगा। इसकी भी मिसाल मैं पेश कर देना चाहता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना में ७ करोड़ ३२ लाख रुपया दिया गया जिसमें से ६ करोड़ ६७ लाख ही कुल खर्च हुआ। ६५ लाख पया खर्च भी न हो सका। यह आपका मुहकमा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह बचत ५ करोड़ १ लाख की हो गई दिया गया था १७ करोड़ २७ लाख, खर्च हुआ १२ करोड़ २६ लाख। तो आखिर क्या होगा इस मुहकमें को पया देकर। केन्द्रीय सरकार से किस मुंह से रुपये की मांग की जा सकती है? आज यह प्रदेश इस स्थिति में है कि जिसको देखते हुये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के लोगों की आंख इस प्रदेश पर लगनी चाहिये, और खास तौर पर उस इलाके की ओर जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, और जहां की इंक्वायरी कमेटी के श्रीमन्, आप चेयरमैन थे, उसकी तरफ में माननीय मन्त्री जी का ध्यान पुनः दिलाना चाहता हूं। उधर के कुछ लोगों ने सी० आई० डी० इंक्वायरी की मांग की। मैं तो मांग करता हूं कि एक कमीशन मुकर्रर किया जाय इस मुहकमे के ऊपर जो इसके कर्मचारियों को देखे, उनकी वर्किंग को देखे, उनकी सुख सुविधाओं को देखे, तब जाकर एफिशियेंसी इस विभाग में आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। तभी प्रापर ग्रान्टस का यूटिलाइजेशन हो सकता है और तब जाकर इस प्रदेश का कल्याण हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पुनः दोहराता हूं।

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, मैंने तमाम बातें बड़े ध्यान से सुनीं, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उन बातों के लिये जो कि मुहकमे के काम के ऊपर रोशनी डालने के उद्देश्य से कही गईं। उसमें कुछ बातें ऐसी भी कही गईं जिनके सिलसिले में मुझे कहना है।

सबसे पहले इसमें जितना भी वर्क चार्ज्ड एस्टैब्लिशमेंट है या जो दूसरे एस्टैबलिशमेंट हैं हमारे रेगुलर उनके सिलसिले में कहा गया कि वह टेम्पोरेरी हैं। तो मैं कई दफा इस बात को पहले बतला चुका हूं कि इस मुहकमे का काम इस किस्म का काम है कि सब के सब आदमी परमानेंट नहीं हो सकते। जहां तक वर्क चार्ज्ड की बात है उसमें जितने ऊपर के हैं मिस्त्री हैं, वर्क सुपरवाइजर हैं, या टेकनिकल आदमी हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट के अन्दर लेने की कोशिश की जा रही है और दूसरे आदमियों के विषय में भी यह सोचा जा रहा है कि कोई तरीका ऐसा निकले जिससे उनका आउटपुट जो गैंग के आदमी हैं, ज्यादा हो और मजदूरी भी उनको ऐसी मिले जो मुनासिब मालूम हो।

एक बात यह कही गई कि जितना अनुदान मन्जूर होता चला आया है उसके माफिक काम नहीं हुआ है। मैं दो बात कहना चाहता हूं। इस विभाग के अन्दर एक बिल्डिंग्स का काम है और एक काम सड़कों का है। जहां तक बिल्डिंग्स का काम है वह काम इस मुहकमे की अपनी बिल्डिंग्स का काम नहीं है बल्कि दूसरे विभागों की बिल्डिंग्स का काम है, पुलिस का है, हास्पिटल्स का है, एजूकेशन विभाग का है यानी जितने और और मुहकमे हैं उनकी बिल्डिंग्स का काम इस विभाग द्वारा हुआ करता है और बजट के अन्दर उसका प्राविजन कर दिया जाता है, । फिर सवाल उठा करता है कि कहां साइट हो, कैसी डिजाइन हो, कैसे कमरे हों, किस तरीके से हों, किस तरीके से न हों, । उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी उन्हीं मुहकमों से आता है। इन बातों की वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से

[श्री गिरधारीलाल]

काफी शार्टफाल हुआ है। लेकिन जहां तक सड़कों की बात है इसके अन्दर कोई शार्टफाल नहीं हुआ है। ९५ प्रतिशत काम हमारा सड़कों और पुलों के विषय में हुआ है बल्कि पुलों में शायद हम लोग कुछ आगे को भी बढ़े हैं। तो यह खास बात है।

इसके अलावा एक और बात भ्रष्टाचार के सिलसिले में कही गई। ठीक है, होगा। भ्रष्टाचार लोगों के दिमाग में और इधर उधर संसार में हर स्थान पर दिखाई देता है लेकिन उसका क्या तरीका है। मैंने किसी भाषण में इस बात को नहीं सुना कि कोई इलाज बताया गया हो। यह बतलाया गया कि बोर्ड बैठाया जाय या कमीशन बनाया जाय। उस काम को कमीशन नहीं कर सकता जो इस समय हमारे आदमी कर रहे हैं। वह यहां पर हो रहा है। मैंने शुरू में कहा कि हमारा सब तरफ ध्यान है। जो काम हो रहा है उसके वर्किंग को यदि माननीय सदस्य ने देखा होता और उनको उसका पता होता और अन्दाजा होता तो कभी भी वह यह सवाल न उठाते। टेक्नीकल काम के अन्दर आपने गवर्नमेंट आफ इंडिया से आदमी मांगे यह देखने के लिये कि क्या हमारे आदमी उस काम को खराब कर रहे हैं। उन्होंने काम किया है और उन्होंने २, ३ वर्ष के अन्दर ४३५ केसेज देखे हैं। उन केसेज में २५ लाख रुपये का काम हुआ था। जिले में जाकर आजमाइश करके उन्होंने देखा है। ३२७ काम ऐसे हैं जिनके विषय में उन्होंने हिदायत निकाली है। जो भी उनमें एतराज रहा हो लेकिन इतने केसेज के बारे में उन्होंने कहा है। उसमें रिकवरी के केसेज भी ठेकेदारों के सम्बन्ध में थे और सरकारी कर्मचारियों से भी ४ लाख रुपये की रिकवरी की गई है। बहुत से केसेज ऐसे थे जिनमें वास्तव में कुछ गलतफहमी थी तो वह गलतफहमी दूर हुई। वह इस तरीके के थे। बहुत से केसेज ऐसे हैं जिनमें बहुत से लोगों के क्लेम रिजेक्ट किये गये हैं जो ३ लाख ६४ हजार रुपये के थे। इस तरीके के ये काम किये गये हैं जिनसे सरकार को बहुत लाभ हुआ है। मैं यह समझता हूं कि कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है जिससे किसी काम की देख-रेख की जा सके। वह अधिकारी यहां पर बैठते हैं और यहां से हर पूरे काम के जितने ब्योरे होते हैं, डिटेल होती हैं वह सब उनके पास हर जिले से आती है। जहां पर जाना चाहिये वहां पर तुरन्त पहुंचते हैं। यदि वह स्वयं नहीं जा सकते तो उनके सहायक लोग जाते हैं। जिस बिल्डिंग को ले लेते हैं, सड़क को ले लेते हैं और पुल को ले लेते हैं उसको गौर से देखते हैं। अगर ओवर पेमेंट हुआ है तो अकाउन्ट देखते हैं। आफिस में जाते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं। मैं समझता हूं वह इतनी डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि दूसरा कमीशन कोई नहीं जा सकता। यह भी ख्याल है कि इन तमाम बातों के होते हुये भी अब भले ही इस तरीके पर लांछन लगाया जाता हो लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज कल की परिस्थिति में पहले से विभाग सुधरा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से विभाग चल रहा है। इसके अलावा मालूम नहीं है हरवक्त हर स्थान पर हर किस्म की चीज होती है। तो यह बात इसमें हो सकती है और उनके लिये जो तरीका हो वह बतलाया जाय उसपर विचार करने का प्रयत्न किया जायगा। ऊपर के जितने तरीके हो सकते हैं वह किये जा रहे हैं। फिर जितने भी काम हैं उन कामों को हमने देखा और हमारे यहां जो काम हैं उन सब की देखभाल बहुत ढंग से हो रही है। एक दफा माननीय सम्पूर्णानन्द जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी और उसने यह देखा कि हमारे यहां काम कैसे होते हैं। उस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड, गवर्नमेंट आफ इंडिया एस० ई० एस० और दूसरी स्टेट के लोगों को बुलाया गया था। उस कमेटी ने बतलाया कि हमारे यहां के काम सस्ते पड़ते हैं। इस पर भी हमारे यहां यह दूसरा चेक है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। फिर क्या तरीका है ठीक करने का। उन सरकारी कर्मचारियों के घरों में ठेकेदार घुसकर अपने आप कुछ दे आते हों तो वह कोई दूसरा मन्त्र होगा जिसमें उनको सफलता मिल जाती हो। उसको बतलाया जाय तो वह भी देखने का प्रयत्न किया जायगा और तब हम अपने को और सफल समझेंगे। अब इसके माने यह भी नहीं हैं कि हमारी

कोशिश नहीं है। हमारी कोशिश बराबर है और हम जहां तक हो सकेगा आगे और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे।

इन बातों के अलावा जहां तक उत्तराखंड की बात कही गई कि वहां पर अब सड़क क्यों बनाई गई और पहले क्यों नहीं बनाई गई ? उत्तरकाशी की ५० हजार की आबादी है और चमोली में ५० हजार की आबादी है। सारे प्रदेश से सड़कों की मांग है। गोरखपुर की मांग है और देवरिया की मांग है लेकिन अब सोचना यह है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं वह लिमिटेड हैं। वह सब वहां पर लगे हुये हैं। जहां पर जिस तरह से जरूरत पड़ती है वैसे वह काम किया जाता है। जिस वक्त मर्ज होता है तो उसके लिये सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया का आदेश था और उसका आदेश ही नहीं बल्कि उसकी सहायता से, उसके हुकुम से वहां पर जल्द से जल्द वह काम किया जा रहा है। उस काम में सिवाय इसके कि यहां के आदमी काम कर रहे हैं और कोई सम्पर्क नहीं है। सीधा उनका ही वहां के काम से सम्पर्क है। उसके चीफ इंजीनियर अलग हैं उनके ऊपर हमारा सेक्रेटरी भी नहीं होता। चीफ सेक्रेटरी उनका सेक्रेटरी होता है और चीफ मिनिस्टर उनका इंचार्ज होता है और उनके मातहत जितने भी काम वहां होते रहते हैं उसका यहां से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसमें एक बात यह कही गई कि हमारी स्टेट बहुत गरीब है, पिछड़ी हुई है। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि हमें तैयार रहना चाहिये। हर एक की ख्वाहिश है कि हमारे यहां सड़कें ज्यादा बनें, ज्यादा से ज्यादा काम हो और मेरे स्थान पर कोई भी हो, उसकी यह ख्वाहिश होगी, लेकिन वह सब हमारे साधनों पर निर्भर करता है। मद्रास, केरल आदि से मुकाबला किया गया लेकिन देखा जाय कि वहां टैक्स का इंसीडेंस ११ से १२ परसेंट तक है जब कि हमारे यहां ६ से ७ परसेंट तक ही है। हमें इसके लिये तैयार रहना चाहिये। कल को जब हम टैक्स का प्रपोजल ले कर आयेंगे तो आपका ही मुंह बनेगा। मैं समझता हूं कि उस समय हमारे उन साथियों को उसका विरोध नहीं करना चाहिये जिन्होंने इस समय यह एतराज किया है उनको उस समय बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

रामजानकी रोड की बाबत मैंने देखा और यह मानता हूं, कि उनको बनाये जाने की जरूरत है, बहुत सी सड़कें हैं, कि जिनको बनना चाहिये, लेकिन हमारे साधन सीमित हैं। जो स्टार एंड ग्रिड का फारमूला है उस हिसाब से हम चल रहे हैं लेकिन अगर बीच में किसी विभाग में शार्टफाल हो जाता है तो उस समय हम इन बातों पर विचार करेंगे।

फ्लड प्रोटेक्शन के सिलसिले में कहा गया कि कौन करता है, कौन नहीं करता। उसका काम एक फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड करता है और उसके अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं। जितने उसमें शहरी और अरबन एरिया के काम हैं उनको पी० डब्ल्यू० डी० करता है और रूरल एरिया के काम इरिगेशन विभाग के इंजीनियर्स देखते हैं। वे ही उसकी देखभाल भी करते हैं।

मैं समझता हूं कि इसके बाद कोई और विशेष बात बाकी नहीं रहती। दो एक बातें और कही गयीं जिनके सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूं। किसी ने कहा कि भोजपुर में सड़क इसलिये बनी कि वहां मेरे रिश्तेदार रहते हैं। महज मेरे रिश्तेदार वहां होने की वजह से वहां सड़क न बने और दूसरे आदमी उससे यह महरूम रह जांय, कहां के न्याय की बात है। मैंने खुद उसे देखा है और उस प्रपोजल को रखा है और वह सड़क बनवाई है। मैंने अभी तक ऐसी बात नहीं सुनी थी, लेकिन इस बार सुनी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करके आशा करता हूं कि सदन इन अनुदानों को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,८८,०२,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३७—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१८,२९,६०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९४,२८,८०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,८३,४९,३०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

२४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न १–३ के विषय पर नियम ५० (१) के अन्तर्गत विवाद

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने आज एक गंभीर प्रश्न पर विचार करने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, माननीय रामसुन्दर जी इस सम्मानित सदन के पिछले ११ वर्षों से सदस्य हैं जिन्हें सम्मानित सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं और सरकार के लोग जानते हैं। वे आजमगढ़ के एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं जिनकी देश के लिये बड़ी कुर्बानियां रही हैं और जिनकी स्पष्टता के बारे में जिले के और सदन के लोग भलीभांति जानते हैं। उन्होंने आजमगढ़ की पुलिस के आचरण के बारे में जबानी ही नहीं लिखित कई पत्र गृह मंत्री जी को भेजे इस साल भर के अन्दर। श्रीमन् यह एक गंभीर प्रश्न है कि सम्मानित सदन के किसी सदस्य को पुलिस के अधिकारी जान से मारने की धमकी दें और उनके साथियों को विभिन्न षड यंत्रों में फंसाने और तंग करने की धमकी दें तो उस समय सरकार का कर्त्तव्य यह होता है कि सूचना पाने पर आवश्यक कार्यवाही करे। माननीय पांडेय जी ने गृह मंत्री को साफ-साफ लिखा है अपनी चिट्ठियों में कि किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा इस बात की जांच कराई जाय और जांच करने के बाद उचित कार्यवाही की जाय। श्रीमन्, माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर जो दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि ज्यादा तथ्य नहीं पाये गये और आरोप निराधार रहे। ज्यादा तथ्य न होने का मतलब क्या है ? कुछ तथ्य तो रहे होंगे। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि गुप्त जांच हुई और प्रत्यक्ष जांच भी हुई। लेकिन जब उस जांच की रिपोर्ट यहां सदन में मांगी गयी तो माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कुछ नहीं बताया गया। जांच के बारे में माननीय सदस्यों ने जो शिकायत की थी उस जांच के बारे में उनको सूचना तक न दी गयी। प्रश्न पूछने पर माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि माननीय सदस्य का पता लगाने की कोशिश की गयी वे मिले नहीं। माननीय पांडेय जी इस सदन के सदस्य हैं, वे यहां रहे होंगे, अपने जिले में रहे होंगे, प्रदेश में ही रहे होंगे, जब यह इतना गम्भीर मसला था तो उनको सूचना देनी चाहिये थी। फिर जब उन्होंने लिखकर शिकायत की थी तो क्या यह जरूरी नहीं था कि उसकी इत्तिला उनको दी जाती उनके साथियों को दी जाती और उनसे उस जांच के बारे में कुछ पूछा जाता ? अगर माननीय रामसुन्दर पांडेय जी से नहीं पूछा गया तो क्या उस इलाके के और उनके साथियों से पूछा गया ? और अगर पूछा गया तो उनके नाम माननीय मंत्री जी यहां बताने की कृपा करेंगे ?

दूसरी बात षड़यन्त्र के बारे में रही। आप कह सकते हैं कि जब जानमाल का खतरा था तो श्री राम सुन्दर पांडेय जी यहां कैसे मौजूद हैं ? लेकिन क्या यह सही नहीं है कि उनके सैकड़ों साथी विभिन्न मुकदमों में परेशान किये जाते हैं। सौभाग्य से माननीय बृजबिहारी मिश्र जी भी उसी इलाके के हैं जहां के हम हैं और माननीय रामसुन्दर पांडेय जी हैं। आप उनसे ही पूछ सकते हैं। मैं इसके लिये तैयार हूं कि सारा मामला उनके सुपुर्द कर दिया जाय और फिर हम भी हों पांडेय जी भी हों और उसकी खुली जांच हो। माननीय बृजबिहारी मिश्र जी के साथ रामवृक्ष चौबे जी आजमगढ़ तक एक साथ मोटर में बैठकर गये। चौबे जी मामूली आदमी नहीं हैं। देश की सेवा में उनको काले पानी की सजा हुई थी। फिर भी उनको एक झूठे मुकदमें में परेशान किया गया। दर्जनों और उनके साथी ऐसे हैं जिनको झूठे मुकदमों में परेशान किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये।

उसी क्षेत्र में माननीय रामसुन्दर जी के एक साथी फोजदार गड़ेरी भी हैं। वे इसलिये कसूरवार हैं कि वे उनके साथी हैं। उनको भी बहुत तंग किया जा रहा है। उनका एक खेत और उनका नाम खसरा और खतौनी में दर्ज भी है। उनकी अरहर की फसल बरबाद हो गयी और उनकी अरहर जब्त है। कई और उनके साथी हैं जिनको १०७ आदि कई दफाओं में परेशान किया जा रहा है। जब माननीय पांडेय जी के साथ यह हालत है तो फिर

[श्री मंगलदेव]

मामूली आदमी की क्या हालत हो सकती है उसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है। पुलिस विभाग द्वारा गरीब आदमी के साथ इसी तरह की हकतलफी हो रही है।

श्री अध्यक्ष---आप पुलिस अनुदान पर नहीं बोल रहे हैं, विषय पर कृपया बोलें।

श्री मंगलदेव---यह अप्रसांगिक नहीं है। पुलिस के चरित्र की क्या हालत है मैं उसे बताने जा रहा था। पुलिस जिस तरह से काम आजमगढ़ में कर रही है।

श्रीमन्,अतरौलिया के जिस थानेदार के खिलाफ शिकायत की गयी थी उसी को जांच करने का आर्डर दे दिया गया, मैं उस कागज को पेश कर सकता हूं। मऊ थाने के थानेदार केदारनाथ श्रीवास्तव को पीटा गया, उनका रिवाल्वर छीन लिया गया और वह बाद में बरामद हुआ और रिपोर्ट गलत लिखा दी गयी। बार-बार कहा गया कि यह मुकदमा खराब दर्ज किया गया है, मुल्जिम अदालत से छूट जायंगे, लेकिन श्रीमन्, जाति के नाम पर वह मामला गड़बड़ कर दिया गया। उसमें कुछ नहीं हुआ। आज भी उसकी गुप्तचर विभाग से जांच करा ली जाय। स्वतः एस० पी० की नालेज में बहुत सी बातें लायी गयीं, लेकिन फिर भी उनकी उपेक्षा की गयी।

श्री अध्यक्ष---आपका प्रश्न यह था कि क्या मुख्य मंत्री जी ६ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न ७७ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पत्र में उल्लिखित दरगाह के श्री सीताराम की डकैती के संबंध में जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? तो उसी पर आइये, आप न मालूम क्या कह रहे हैं।

श्री मंगलदेव---श्री सीताराम के घर पर डकैती पड़ी। बन्दूकधारी पुलिस वहां ४-४ रही, लेकिन कुछ नहीं किया। गांव वालों ने डाकुओं का पीछा किया, पुलिस ने पीछा नहीं किया। इसी तरह श्रीमन्, अतरौलिया थाने और मधुबन थाने में जिसमें मैं रहता हूं कभी भी अमनचैन नहीं है। कोई न कोई साजिश होती रहती है, इससे बड़ी परेशानी हो गयी है। जांच का जो तरीका है, जिस तरह की जांच की गयी, जिस तरह का जवाब दिया गया, यह लोकतंत्र के काबिल नहीं है। हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, पुलिस के अत्याचार के खिलाफ उसके रवैये के खिलाफ आपसे निवेदन करते हैं। मधुबन थाने में लोग शहीद हुए हैं। अंग्रेजों के जमाने में काफी लोग शहीद हुए, हमने उनसे लड़ाई लड़ी। लेकिन आज गणतंत्र के समय में हम लोग पुलिस के द्वारा तंग किये जा रहे हैं। अत्याचार को ज्यादा दिनों तक बरदाश्त नहीं कर सकते। श्री ब्रजबिहारी मिश्र जी इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि हमने कोई बढ़ाचढ़ा कर बात नहीं की। हमारा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि जो जवाब दिया गया है वह ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी बतायें कि किसी भी आदमी से जो रामसुन्दर पांडेय जी के साथ रहते हों कोई जांच की गयी ? बिलकुल उपेक्षा की गयी। इस प्रकार से बड़ी-बड़ी कठिनाइयां होती हैं। मधुबन में सोशलिस्ट पार्टी के बिशुनदेव को गुंडों द्वारा पिटवाया गया।

श्री अध्यक्ष---मैं तो आपको कई मर्तबा कह चुका। अभी तक मैं समझता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री यह बतायें कि रामसुन्दर पांडेय जी अगर नहीं थे तो उनके किसी साथी से कुछ पुछवाया गया। यह सवाल आपका है, इसी का उत्तर उनसे पूछा गया। अभी तक इसके सिवा आपने कुछ नहीं कहा। स्पष्ट कीजिये, क्या जानना चाहते हैं, आपको १०-१२ मिनट हो गये।

श्री मंगलदेव---माननीय रामसुन्दरजी ने जो जो शिकायतें की हैं उनकी पुनः जांच हो, खुली जांच हो, उसकी जांच कराकर पुनः माननीय गृह मंत्री जी इस हाउस में स्पष्ट करें। यही मुझे आपके द्वारा निवेदन करना है।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न पूछे गये थे जिनके संबंध में आपने वादविवाद का आदेश दिया है। मैं समझता था कि प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त

ढंग से दे दिये गये हैं। मान्यवर, अभी जो मंगलदेवजी ने बहुत सी बातें कहीं आपने स्वयं टोक दिया मैं उनमें नहीं जाऊंगा बल्कि संक्षेप में उनकी शिकायतों के बारे में निवेदन करूंगा। रामसुन्दर जी ने तीन शिकायती पत्र भेजे थे। एक शिकायती पत्र में उनकी दो शिकायतें थी। एक तो यह कि मधुबन थाने के अन्तर्गत एक श्री विश्वनाथप्रसाद जी के मकान पर डकैती पड़ी। उनका कहना है कि काफी शोर मचा आस–पास के दुकानदार आ गये मगर पुलिस के लोग नहीं आये जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि यह बात ऐसी नहीं है। जो रिपोर्ट लिखी गई है थाने में वह उस थाने के सिपाहियों ने या दीवान ने अपनी तरफ से नहीं लिखी बल्कि जो लिखित रिपोर्ट दी गई थी उसी के आधार पर रिपोर्ट लिखी गई है। लिहाजा यह कहना कि पुलिस ने ठीक ढंग से रिपोर्ट नहीं लिखी, सही नहीं है।

इसके साथ-साथ जो उनकी रिपोर्ट लिखी गई उसमें उनके जो मुनीम वगैरह थे उनको एन्टोरोगेट किया गया। तो वाक़यात जो रिपोर्ट में लिखे थे वह अपनी जगह पर सही पाये गये। तहकीकात से यह पता चला कि थानेदार और अफसर दोयम और चार सिपाही भी घटना स्थल पर तुरन्त ही पहुंच गये थे। जो उनका सामान था वह भी आस–पास मिला पाया गया कुछ मिला और कुछ नहीं मिला। मेरे कहने का मतलब यह है कि विश्वनाथप्रसाद जी के बारे में जो रिपोर्ट है उसके सम्बन्ध में यह कहना कि रिपोर्ट गलत लिखी गई और पुलिस नहीं पहुंची, मेरी सूचना के आधार पर यह गलत है।

दूसरा केस श्री सीताराम जी के यहां चोरी या डकैती के सम्बन्ध में था। उनका कहना था और वह यह जानना चाहते थे कि उनकी लड़कियों से पूछ तांछ की गई या नहीं। मैंने यह बताया था कि उनकी स्त्री से और लड़कियों से पूछ तांछ की गई। अब भी यही सूचना है और उससे यह स्पष्ट है कि स्त्री से भी पूछा गया और दोनों लड़कियों से भी पूछा गया। इसके अलावा ९ व्यक्तियों से इस मामले में और पूछ तांछ की गई। एक बात सही है कि जो गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे यह जरूर महसूस हुआ कि उसने अपने फर्ज को ठीक अन्जाम नहीं दिया इस संबंध में उसके ऊपर डिपार्टमेन्टल कार्यवाही चल रही है।

दूसरा खत उन्होंने यह लिखा कि उनको अन्देशा है कि पुलिस उनसे नाराज है शायद वह उनको मारना चाहती है। मान्यवर, इस सिलसिले में एक ही बात कहना चाहता हूं कि उनकी शिकायत २७–३–६१ की है और आज २–६–६२ है। एक साल बीत गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय रामसुन्दर जी की लाइफ पर कोई खतरा नहीं है भगवान करे वह १०० वर्ष तक और जिन्दा रहें। ऐसी कोई बात नहीं है इसकी भी तहकीकात की गई। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको डीसेन्सी के आधार पर साफ-साफ नहीं कहना चाहता क्योंकि उससे कोई मर्यादा नहीं बढ़ने वाली है। एक ही बात कहना चाहता हूं कि उस बात की जांच की गई डी० एस० पी० ने जांच की और उसको निराधार पाया गया जोकि उनके आरोप थे। एक बात सही है कि आजकल वहां एक थानेदार है वह थोड़ा सख्त है। उस इलाके के जो बदमाश हैं उनपर वह सख्ती करता है। रामसुन्दर जी के भी कुछ ऐसे साथी हैं जिनके कहने के मुताबिक वह अमल नहीं करता है इसलिये उनकी नाराजगी है। ३४ आदमी ऐसे हैं जिनमें ३३ ऐक्टिव हिस्ट्रीशीटर हैं उनके सम्बन्ध में मैं जाना नहीं चाहता केवल यही कहना चाहता हूं कि उसकी जांच की गई। एक शिकायत यह थी कि उनसे पूछ तांछ की गई या नहीं की गई? मैंने कहा था कि उनसे सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि आपने कौन से जरिये अखतियार किये उसका विवरण उस दिन मेरे पास नहीं था और मुझे खेद है कि चूंकि आपने आजकी डेट रखी कोशिश करने के बावजूद भी मैं उसको हासिल नहीं कर सका लेकिन जांच अच्छी तरह से कराई गई और पाया गया कि जो आरोप हैं वह गलत हैं। उनके पीछे क्या मोटिव है वह मैं स्पष्ट रूप से कहना नहीं चाहता, इशारतन मैंने उसको कहा। तीसरी शिकायत उनकी यह थी कि वहां पर श्री केदारप्रसाद श्रीवास्तव थानेदार को बुरी तरह से पीटा गया और उनका रिवाल्वर छीन लिया गया और वहां

[श्री नवलकिशोर]

के थानेदार ने, जहां कि डी० वाई० एस० पी० मौजूद थे रिवाल्वर छीनने की बात रिपोर्ट में नहीं लिखी जिससे केस बजाय संगीन होने के मामूली केस हो गया। इस सम्बन्ध में जांच की गयी। यह बात सही है कि इस मामले में जांच एस० ओ० ने की एस० पी० ने यह जांच की कि वहां के सर्किल इंसपेक्टर की कोई रिश्तेदारी तो नहीं है क्योंकि यह भी आरोप था हमने डी० आई० जी० को भी लिखा। उनसे मालूम हुआ कि यह जो आरोप थे कि गलत इन्दराज से केस अदालत से छूट गया। सो उसकी वजह यह नहीं थी कि रिवाल्वर वाली बात रिपोर्ट न होने से केस अदालत से छूट गया। मिस्टर गुप्ता जो प्रेसाइडिंग आफिसर थे उन्होंने कुछ आदमियों का नाम लिया लेकिन उनको वे पहचान नहीं पाये जिससे केस छूट गया।

जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है या सरकार का सम्बन्ध है उन्होंने जो तीन पत्र दिये थे उनकी पूरी जांच की गयी और उस जांच के अन्दर कोई चीज नहीं मिली। उसके बाद भी कहा जाय कि उनकी जान का खतरा है तो क्या कहा जा सकता है। फिर मैं आपके द्वारा श्रीमन्, उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आज भी उनको अपनी जान का खतरा हो तो हम उनकी रक्षा करने के लिये तैयार हैं। मान्यवर आपके द्वारा मैं आश्वासन देता हूं कि यदि वह कोई नई शिकायत देंगे तब उसकी पूरी जांच कराऊंगा और उनके जीवन की रक्षा यथा सम्भव जरूर की जायगी लेकिन अगर उनको अपने एसोशिएट्स से ही कोई खतरा हो तो फिर हमारे लिये मजबूरी है।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री जी उन व्यक्तियों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनके बयान खुली जांच में लिये गये हैं?

श्री नवलकिशोर—मैंने आपसे शुरू में ही बतला दिया था कि किन-किन लोगों ने बयान दिये उनके डिटेल मेरे पास नहीं हैं।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय रामसुन्दर जी ने अपने पत्र में लिखा था कि किस व्यक्ति के जरिये उनकी जान को खतरा है? यदि हां, तो वे कौन व्यक्ति हैं?

श्री नवलकिशोर—स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति का नाम उन्होंने नहीं लिखा था। अपने बारे में उनको एक भ्रम सा हो गया था कि उनकी जान को खतरा है।

श्री रामसुन्दर—अध्यक्ष जी, मैं फिर आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पत्र को वे फिर पढें और अपने दिमाग को जरा संतुलित करके पढ़ें। पत्र में हमने साफ लिखा है कि जिले के जितने पुलिस प्रशासक हैं एस० पी० से लेकर थानेदार तक सब बार-बार असेम्बली में व बाहर भी शिकायत करने की वजह से मुझ से व मेरे साथियों से नाराज हैं। मुश्किल है कि मेरे पूछने पर भी वे पत्र को नहीं पढ़ रहे हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खुली जांच में किन-किन व्यक्तियों ने बयान दिये उनके नाम बतला दें और गुप्त जांच हुई तो कौन अधिकारी जांच पर गया था इसे बतलादें। श्रीमन्, एक बात मैं आपको बतला दूं कि वहां के एस० पी० जो हैं सभा सचिव पंडित बृजबिहारी जी के साथ घंटों बैठा करते हैं लेकिन उस बहस में मैं नहीं पड़ना चाहता। लेकिन इतना मैं जरूर माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब लिखित रूप से एस० पी० के खिलाफ रिपोर्ट है तो उसी एस० पी० से इनक्वायरी कराने के बजाय किसी मैजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी करावें जिससे मालूम हो जाय कि रामसुन्दर बदचलन हैं या कैसे हैं। इतनी बेहयाई है कि असेम्बली का एक मेम्बर चिट्ठी लिखता है और साल भर पूछ ताछ करने के बाद भी माननीय मंत्री को फुरसत नहीं मिलती कि उसकी जांच कर सकें और उसी एस० पी० से जांच भी कराते हैं जिसके खिलाफ पचासों लिखित शिकायतें घूसखोरी, बेईमानी व गलत काम करने की हैं। मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे ईमानदारी के साथ किसी मैजिस्ट्रेट से इसकी खुली जांच करावें।

श्री अध्यक्ष––आप प्रश्न पूछें।

श्री राम सुन्दर––मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे फिर से इसकी खुली जांच कराने की कृपा करेंगे जिसमें मैं भी मौजूद रहूं और हमारे जितने साथी उनकी नजरों में हैं उनको भी बुला लिया जाय और उसकी खुली जांच हो जाय तथा एस० पी० से लेकर थानेदार तक भी वहां मौजूद रहें।

श्री अध्यक्ष ––खुली जांच के पहले जो जांच हुई उसके संबंध में जो पूछना चाहते हैं, पूछें।

श्री रामसुन्दर––उन्होंने यही जवाब दिया कि खुली और गुप्त दोनों जांचें कराई गयीं। मैं पूछ रहा हूं कि जो खुली जांच कराई गयी उसमें कौन-कौन लोग थे ?

श्री नवलकिशोर––श्रीमन्, मैं कौन सी बात का उत्तर दूं। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि होश संभाल कर जवाब दें। तो मैं आपके द्वारा माननीय पांडेय जी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं बड़े संतुलित मस्तिष्क से उत्तर दे रहा हूं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस हाउस के सामने बहुत सी बातों को कहना नहीं चाहता लेकिन उन्होंने किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराये जाने की बात कही इस पर सरकार ने यह समझा कि एस० पी० द्वारा जो जांच की गयी है वही काफी है और अब सरकार कोई नयी जांच कराने के लिये तैयार नहीं है। मैं उन्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि पांडेय जी इस प्रकार से पुलिस अधिकारियों पर आतंक जमाने की चेष्टा करें तो सरकार इसको सहन करने के लिये तैयार नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)––जिस दरोगा के बारे में माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि वह बड़ा सख्त और ईमानदार दरोगा है और वह राम सुन्दर जी के साथ रहने वाले बदमाशों को दुरुस्त करता है, क्या इस दरोगा की इससे पहले की कार्यवाहियों के बारे में भी मंत्री जी जानते हैं ?

श्री नवलकिशोर––यह तो एक नया प्रश्न है। उसका प्रीवियस रिकार्ड मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदासिंह––क्या मंत्री जी उसके प्रीवियस रिकार्ड को देखकर माननीय सदस्य को संतुष्ट करने की कृपा करेंगे ? मेरी तो सूचना यह है कि वह बहुत ही खतरनाक, शरारत करने वाला और बेईमान दरोगा है ?

श्री अध्यक्ष––अच्छा हो आप कोई प्रश्न करें जिससे यह साबित हो जाय कि यह बेईमान दरोगा है।

श्री गेंदासिंह––मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी मुझे ठीक से उत्तर दें। आजमगढ़ में एक मर्तबा और ऐसी बात हुई थी। गवर्नमेंट के पास कलेक्टर तक की उसमें शिकायत हुई थी। माननीय मुजफ्फर साहब उसमें जांच करने के लिये गये थे और इसलिये कि सही जांच हो सके। मैं उस जांच में था। तो क्या मैं पूछ सकता हूं और माननीय मंत्री जी से उम्मीद कर सकता हूं कि इस शिकायत में जहां तक जान माल की शिकायत की गयी है, उसमें माननीय राम सुन्दर जी और माननीय गृह मंत्री जी को जिन आदमियों में विश्वास हो, उनके इत्मीनान के लिये जांच की खातिर भिजवाने की कृपा करेंगे जिससे यदि उनका भ्रम ही है तो वह भ्रम दूर हो सके ? क्या मंत्री जी कोई ऐसा उपाय निकाल सकते हैं जिससे उनको विश्वास दिला दिया जाय ?

श्री नवलकिशोर---माननीय गेंदासिंह जी चाहें तो इस संबंध में मुझसे बातें कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि उनको विश्वास हो जायगा और साथ ही संतोष भी हो जायगा । लेकिन अगर किसी माननीय सदस्य को भ्रम है तो उस भ्रम को कहां तक दूर किया जा सकता है ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---क्या गृह मंत्री जी यह बतायेंगे कि माननीय सदस्य श्री परशुराम सिंह जी ने जो मुख राम और परशुराम नामक दो सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं के बारे में बताया है कि वे मारना चाहते हैं तो क्या उनसे माननीय सदस्य को बचाने की उन्होंने कोई कार्यवाही की ?

श्री नवलकिशोर---आपने जो श्री परशुरामसिंह का नाम लिया वे हिस्ट्री शीटर हैं और वे किसी पार्टी के मेम्बर भी हैं और उनका मर्डर में कनविक्शन भी हो चुका है ।

श्री नरसिंहनारायण---मैं जानना चाहता हूं कि वह पार्टी कौन है ?

श्री अध्यक्ष---यह वह नहीं बतलायेंगे क्योंकि उनको मालूम नहीं है ।

श्री नरसिंह नारायण---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस डाकू की आप बात कर रहे हैं उसी डाकू को इंगित कर के माननीय पांडेय जी ने कहा था कि हमारी जान का इससे खतरा है, ऐसी बात पर क्या कार्यवाही मंत्री जी ने उनकी रक्षा के लिये की ?

श्री नवलकिशोर---मेरी सूचना है कि जिस सज्जन का नाम लिया गया माननीय पांडेय जी उसके मुख्य आश्रयदाताओं में से हैं, इसलिये उसके द्वारा उनके मर्डर का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं बहुत अदब के साथ माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि जो कुछ भी उन्होंने यहां माननीय रामसुन्दर जी के खिलाफ कहा मैं समझता हूं कि किसी भी आदरणीय सदस्य के लिये इस प्रकार का आचरण रखना बहुत ही आपत्तिजनक है कि वह बदमाशों को और हिस्ट्रीशीटर्स को आश्रय देते हैं और डाकुओं को आश्रय देते हैं जिन को कि दरोगा जी नहीं रखना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं । तो क्या माननीय पांडेय जी के खिलाफ कोई जांच कराई जायगी ताकि इस मामले का स्पष्टीकरण हो सके ।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो आप को आमंत्रित किया हैं, आप जो कुछ है वह सब जाकर देख लें ।

श्री नवलकिशोर---जहां तक सरकार का संबंध है उस की तरफ से तो स्पष्टीकरण हो गया । मैंने निवेदन किया था कि माननीय गेंदा सिंह जी को यदि भ्रम हो तो मैं उनको बात कर के संतुष्ट कर दूंगा ।

श्री गेंदासिंह---मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को संतोष हो गया है कि रामसुन्दर जी एक भले आदमी हैं और वह भले आदमियों की मदद करते हैं और डकैतों को दुरुस्त करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष---माननीय गेंदा सिंह जी आप नाराज न हों, आप तो बहुत संतुलित रहते हैं । वह यह कह रहे हैं कि जो सूचना हमारे पास है उसको आप भी आकर देख लें, उससे आपको भी संतोष हो जायगा ।

श्री गेंदासिंह---हमारे संतोष से बात नहीं होती, हम तो इस सदन का संतोष चाहते हैं और हम सरकार का संतोष चाहते हैं तो क्या सरकार ने इतमिनान कर लिया कि माननीय राम सुन्दर जी के खिलाफ शिकायत थी कि वह अनडिजायरेबिल लोगों की मदद करते हैं तो वह बात सही है या नहीं ?

श्री नवलकिशोर––सरकार इस बात से संतुष्ट है कि माननीय पांडेय जी का जो खयाल है कि उनके खिलाफ पुलिस के कर्मचारियों की साजिश है तो यह बात सही नहीं है ।

श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)––यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और जैसा कि माननीय पांडेय जी ने बताया कि जांच उन लोगों के द्वारा कराई गई जिनके खिलाफ शिकायत थी इसलिये यह तो निश्चित था कि वह अपने खिलाफ ही जांच कर के रिपोर्ट नहीं देंगे तो इस हालत में मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस गंभीर मसले पर किसी मेजिस्ट्रेट या उच्च अधिकारी की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष––इसका उत्तर हो चुका है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)––क्या यह सही है कि जिस सब इंसपेक्टर के खिलाफ पांडेय जी की शिकायत थी उसको अब सेकिन्ड आफिसर बनाया गया है ?

श्री नवलकिशोर––ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष––इसका समय समाप्त हुआ ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३७ मिनट पर सोमवार, ४ जून, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
२ जून, १९६२

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८१० पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६२) के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित सर्वश्री यादवेन्द्र दत्त दुबे, जगन्नाथराव तथा गयाप्रसाद मेहरोत्रा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर ।

प्रश्न

२—क्या सरकार बतायेगी कि इस समय कानपुर में जे० के० ग्रुप तथा बी० आई० ग्रुप तथा लक्ष्मी रतन काटन मिल पर प्रदेशीय सरकार का कितना-कितना सेल्स टैक्स का देय बाकी है ?

उत्तर

२—"कानपुर में जे० के० ग्रुप मिल्स तथा लक्ष्मी रतन मिल पर सरकार का कुल बकाया सेल्स टैक्स क्रमशः ९,००,३६२ रु० ८९ नये पैसे तथा ५,७०,८७९ रु० ६ नये पैसे है ।

कानपुर में बी० आई० ग्रुप की मिलें नहीं हैं । इसलिये उन पर बकाया सेल्स टैक्स देय होने का प्रश्न नहीं उठता ।"

कमलापति त्रिपाठी,
वित्त मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—९३ एल० ए०—१९६२—८४५ ।